सूर्योदय 6.12 सूर्यास्त 6:13

आज का तापमान

शिमला	15.0 न्यू	25.0 अधि
धर्मशाला	18.0 न्यू	28.5 अधि

बाजार

सेंसेक्स	73,896
निफ्टी	23,141

सोना 1,52,000 चांदी 2,32,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 10 अश्विन, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 152, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

एअर इंडिया पायलट अल्कोहल टेस्ट में फेल होने पर सस्पेंड

एजेंसी, नई दिल्ली। एअर इंडिया के पायलट को ज्यूरिख-दिल्ली फ्लाइट से पहले अल्कोहल टेस्ट में फेल होने पर शुक्रवार को सस्पेंड कर दिया गया है। अंतिम मेडिकल रिपोर्ट और जांच पूरी होने तक पायलट का निलंबन जारी रहेगा। यह मामला 6 सितंबर का है। टेकऑफ से पहले ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को पायलट से शराब की स्मेल आई थी। उन्होंने अफसरों को उसकी सूचना दी, जिसके बाद पायलट को विमान से उतार दिया गया। अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पायलट को टेकऑफ से कुछ समय पहले ज्यूरिख एयरपोर्ट पर विमान से उतार दिया गया था। यात्री की तरह उसी फ्लाइट से भारत भेजा गया था।

मणिपुर में उग्रवादियों ने 4 नगा लोगों की हत्या की

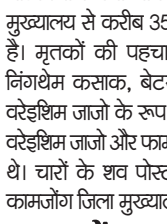
एजेंसी, कामजोंग। मणिपुर के कामजोंग जिले में चार नगा लोगों की हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने हत्या का आरोप कुकी नेशनल आर्मी-बर्मा के उग्रवादियों पर लगाया है। पुलिस के मुताबिक, हथियारों से लैस उग्रवादियों ने पिलोंग नगा गांव में ग्रामीणों पर गोलीबारी की थी। पिलोंग नगा गांव कामजोंग जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है। मृतकों की पहचान फामी जाजो, निंगथेम कसाक, बेटरसन जाजो और वरेइशिम जाजो के रूप में हुई है। इनमें वरेइशिम जाजो और फामी जाजो पिता-पुत्र थे। चारों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए कामजोंग जिला मुख्यालय लाए गए हैं।

यूएन में 75 देशों ने बेंजामिन नेतन्याहू का बायकॉट किया

एजेंसी, न्यूयॉर्क। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वीरवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया, जैसे ही वह मंच पर आए तो 75 देशों के प्रतिनिधियों ने हूटिंग करके उनका विरोध किया, फिर बाहर चले गए। इस घटनाक्रम के बाद नेतन्याहू करीब 3 मिनट तक चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, भाषण शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर यहां कोई और कायर है तो बाहर चला जाए। हालांकि, इस दौरान गैलरी नेतन्याहू के समर्थकों से भरी हुई थी। उन्होंने तालियां बजाकर नेतन्याहू का स्वागत किया और 'अम यिसराइल चाई' यानि 'इजराइल की जनता जिंदा है' के नारे लगाए।

इटली में स्कूलों में बुर्का-नकाब पर बैन

एजेंसी, रोम। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने स्कूलों के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। इसके तहत स्कूलों में बुर्का और नकाब जैसे पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने पर 1000 यूरो यानी करीब 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ विदेशी छात्रों की संख्या एक क्लास में 30% तक सीमित की गई है। हालांकि, हिजाब यानी सिर और बाल ढकने वाले स्कार्फ पर यह रोक लागू नहीं होगी। अगर चेहरा ढकने वाला छात्र नाबालिग है तो जुर्माना उसके माता-पिता पर लगाया जा सकता है।



समाज के लिए काम करें, वोटबैंक की राजनीति के लिए नहीं : मोदी

सेवा यात्रा के अनुभव जीवन की पूंजी, भारत को किताबों से नहीं गांव-गांव जाकर समझें

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'सेवा संकल्प अभियान' के सेवा यात्रियों से कहा कि यात्रा के दौरान अलग-अलग राज्यों के गांवों में लोगों से जुड़ने और सेवा कार्य करने के अनुभव उनके जीवन की अमूल्य पूंजी बनेंगे।



उन्होंने युवाओं से कहा कि भारत की विविधता, गांवों की संस्कृति और समाज की सेवा भावना को किताबों से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, इसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों के बीच रहना जरूरी है। मोदी ने यात्रियों से यात्रा के अनुभवों को लिखने और दर्ज करते रहने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत वडनगर से वाराणसी जाने वाले दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में कहा कि पिछले करीब 10-12 वर्षों में गांवों में बुनियादी ढांचे व सुविधाओं में बड़ा बदलाव आया है तथा शहर और गांव के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। उन्होंने नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए यात्रियों से पूछा कि क्या उन्हें गांवों में बदलाव महसूस हो रहा है और क्या ग्रामीण भी इस बदलाव की चर्चा करते हैं।

यात्रा युवाओं को इन बदलावों को प्रत्यक्ष रूप से देखने और लोगों से सीधे संवाद करने का अवसर दे रही है। मोदी ने महात्मा गांधी के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सामाजिक सुधार के लिए भी काम किया और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सिर्फ अपनी वोट बैंक की तरफ ध्यान रख के सब कुछ चलता है चलने दो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के लिए सफाई का काम करने वालों का सम्मान होना चाहिए।

सेवा संकल्प यात्रा नदी की तरह सबको जोड़ती है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प यात्रा नदी की तरह सबको जोड़ने वाली है। नदी यह नहीं पूछती कि कौन किस भाषा, परिवार या आर्थिक वर्ग से है, वह सभी को नवजीवन देती है। इसी तरह सेवा यात्रा भी लोगों से जुड़ते हुए जनकल्याण से जगकल्याण की भावना को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने सेवा यात्रियों से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने, परिवार से संपर्क बनाए रखने और यात्रा के दौरान अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने का आह्वान किया।

◆सामाजिक बदलाव के लिए निरंतर प्रयास जरूरी, सफाईकर्मियों का सम्मान हो

एशियन गेम्स में भारत को पोल वॉल्ट में पहली बार मेडल



एजेंसी, नागोया। भारत ने एशियन गेम्स में पोल वॉल्ट का पहला मेडल जीत लिया है। बरानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर ब्रॉन्ज जीता। पोल वॉल्ट में खिलाड़ी लंबी डंडी की मदद से खुद को हवा में उठाकर एक पट्टी को पार करता है। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10 हजार मीटर रेस में सिल्वर जीता। उन्होंने 28 मिनट 29.38 सेकेंड में रेस पूरी की। 2023 में इसी इवेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। छठे दिन भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 मेडल जीते। इसके साथ भारत के खाते में 23 मेडल हो गए हैं। चीन 157 मेडल के साथ टॉप पर है।

कोर्ट ने मेटा से कहा-मोदी और महिला की फोटो हटाएं

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेटा को एक महिला के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें उसकी फोटो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉर्फ किया गया है।

जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह पर कंटेंट सर्कुलेट करने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि न यह केवल एक महिला का मामला है, बल्कि यह देश के प्रधानमंत्री की छवि से भी जुड़ा है। इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी तरह संवेदनशील रहे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील उमेश शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सीजेपी प्रदर्शन के दौरान महिला का फोटो मार्फ करके इंटरनेट के जरिये सोशल मीडिया पर वायरल किया गया लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखने के अलावा कोई और कार्रवाई नहीं की।

याचिका में कहा गया है कि सीजेपी नेताओं ने एआई के जरिये संबंधित महिला का आपत्तिजनक फोटो बनाकर अपलोड किया। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत दिल्ली पुलिस के साइबर सेल से भी की लेकिन साइबर सेल उनकी वह फोटो हटवा तक नहीं सका। ऐसा करना याचिकाकर्ता की गरिमा और निजता का उल्लंघन है।



◆वे देश के पीएम, मामला सिर्फ महिला का नहीं

हरियाणा सरकार की शहरी क्षेत्रों के लिए पहल, 1646 वार्ड कमेटियों का किया गठन

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आमजन की सुविधा व शिकायतों के समाधान के लिए प्रदेश के सभी शहरी निकायों में 1646 वार्ड समितियों का गठन किया गया है। कोई भी व्यक्ति स्वच्छता व कचरा संग्रहण के संबंध में इन वार्ड समितियों के व्हाटसएप नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकता है जिसका समयबद्ध समाधान किया जाएगा।

इसी प्रकार घर-घर कचरा उठाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए 87 में से 83 शहरी स्थानीय निकायों में 4जी व 5जी नेटवर्क वाली जीपीएस प्रणाली के वाहन चलाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को शेष चार शहरी स्थानीय निकायों में भी इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के शहरी निकायों में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रूट मैपिंग, मशीनरी की उपलब्धता, पोर्टल के माध्यम से भुगतान, वार्ड समितियों के गठन, स्वच्छता पखवाड़ा कलैंडर, बल्क वेस्ट जनरेटर्स की पहचान व पंजीकरण तथा एनजीओ मैपिंग एंड एमओयू सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने घर-घर कचरा संग्रहण के लिए रूट मैपिंग की स्थिति की भी समीक्षा की। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जून में जहां प्रदेश के 87 में से केवल 28 शहरी स्थानीय निकायों में 100 रूट मैपिंग का कार्य पूरा हुआ था, वहीं 20 सितंबर तक यह संख्या बढ़कर 66 हो गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक वार्ड के रूट मैपिंग में संबंधित कचरा संग्रहण वाहन, उसका समय और चालक का संपर्क नंबर शामिल किया जाए।



◆आम जनता स्वच्छता व कचरा संग्रहण को वार्ड कमेटियों को कर सकेंगी शिकायत

एसबीआई एटीएम से कैश निकालने पर 3 दिन चार्ज नहीं

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने कस्टमर्स के लिए 3 दिन तक एटीएम से कैश निकालने को लेकर ट्रांजेक्शन चार्ज को माफ कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आप तीन दिन तक बिना किसी चार्ज के जितना मर्जी, उतनी बार अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, एसबीआई आपसे लिमिट पूरे होने पर भी इन तीन दिनों का कोई चार्ज नहीं वसूलेगा। बैंक ने कहा है कि जिन ग्राहकों ने 28 से 30 सितंबर, 2026 तक प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के दौरान अपने एटीएम लेनदेन की योजना बनाई है, उन्हें कुछ राहत मिलेगी क्योंकि बैंक ने तीन दिनों के लिए शुल्क माफ कर दिया है। एसबीआई ने यह भी दोहराया कि प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल के दौरान उसकी सभी शाखाएं खुली रहेंगी।

हिमाचल की जरूरतों के अनुरूप शोध को बढ़ावा दें निजी विश्वविद्यालय : सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों से हिमाचल की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को सोलन में 'हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग एवं निजी विश्वविद्यालयों के संस्थागत योगदान, भविष्य की प्राथमिकताएं एवं सहयोगात्मक कार्यप्रणाली' विषय पर आयोजित शैक्षणिक सम्मेलन सत्र एवं छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। सम्मेलन का आयोजन हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन, सतत पर्यटन, अक्षय ऊर्जा, बागवानी, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सार्थक शोध प्रदेश के हितों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय सरकार के लिए केवल शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। विश्वविद्यालयों को रोजगार की बदलती संभावनाओं के अनुरूप अपने पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन करना चाहिए।



सुक्खू ने निजी विश्वविद्यालयों से संकाय विकास, अनुसंधान सहयोग, छात्र आदान-प्रदान, स्टार्टअप और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि तकनीक, पर्यटन एवं आतिथ्य, अक्षय ऊर्जा, वानिकी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कौशल आधारित तथा उद्योग से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी जोर दिया।

बालोद में गेहूं से लदे ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, छह की मौत, 7 घायल

एजेंसी, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गेहूं से भरे ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार 6 लड़कों की मौत हो गई, 7 गंभीर घायलों को रायपुर रेफर किया गया है।

हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे जगदलपुर नेशनल हाइवे पर मरकाटोला घाट के पास हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक सड़क पर पलट गया। ट्रक के नीचे दबे लोगों की जान गई है, जबकि टक्कर लगने से दूर जा गिरे लड़के घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना पुरूर थाना क्षेत्र की है। सभी मृतक कवर्धा के रहने वाले हैं। पिकअप में साउंड सिस्टम का सेटअप बंधा हुआ था। सभी लड़के जगदलपुर जा रहे थे। गाड़ी खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़े थे।



दुर्घटना के कारण मरकाटोला घाट में कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट में याचिका; 2 अक्तूबर से आंदोलन करेगी कॉकरोच जनता पार्टी

एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन किया।

उत्तराखंड के देहरादून में कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इधर, कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया, तो 2 अक्तूबर से देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सीजेपी ने वीरवार को ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में एसआईआर के फैसलों, दिशानिर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की एसआईटी जांच की मांग है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। बिहार के पटना में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। प्रशासन ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।



कांग्रेस बोली- चुनाव आयोग मनमानी कर रहा

कांग्रेस का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में मनमानी कर रहे हैं और दो अन्य आयुक्तों की बात नहीं सुन रहे हैं। पार्टी का ये आरोप इंडियन एक्सप्रेस में छपी उस खबर के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 महीनों में 14 बार दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों पर आपत्ति जताई है।

40% एयर पॉल्यूशन के लिए मैं जिम्मेदार : नितिन गडकरी

एजेंसी, भोपाल। मध्यप्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा फिर शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को भेल दशहरा मैदान से 351 बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा लॉन्च की।

भोपाल-इंदौर समेत 7 शहरों में इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसें चलेंगी। इनमें 180 इलेक्ट्रिक बसें हैं। सरकार का पहले साल 1,500 और 2031 तक 15 हजार बसें चलाने का लक्ष्य है। गडकरी ने कहा- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना सरकार का विजन है। ट्रांसपोर्ट सुधार के लिए 5 एजेंडा बनाए गए हैं, जिसमें पहला क्लीन ट्रांसपोर्ट है। देश के एयर पॉल्यूशन में करीब 40% हिस्सेदारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है। प्रदूषण के लिए मैं जिम्मेदार हूं। एमपी में प्रदूषण के लिए सीएम मोहन जिम्मेदार हैं।



बसें सुधारिए, नहीं तो रगड़ूंगा : गडकरी

गडकरी ने ऑल इंडिया बस एंड कार कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रसन्ना पटवर्धन से बसों की गुणवत्ता पर कहा- अभी भी बस में बहुत सुधार करने की जरूरत है। पटवर्धनजी अभी भी तुम्हारी बस बराबर स्टेंडर्ड पर नहीं बनी है। ये कंपनी वालों को कहो सुधरिए। नहीं तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को रगड़ने का काम करता हूं, वैसे आपके क्षत्रपों को रगड़ूंगा।

सीएम धामी ने खटीमा में 15 कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

एजेंसी, खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को खटीमा में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 15 कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन में आधुनिक संसाधनों, जनभागीदारी और कॉरपोरेट सेक्टर का सहयोग महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित किया जा रहा स्वावलंबी मॉडल स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा। सरकार का प्रयास कचरा संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था को व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाना है। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश सासनी ने बताया कि ऊधम सिंह नगर की 373 ग्राम पंचायतों में 71 क्लस्टरों के माध्यम से ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार की गई है। नगर निकायों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों और प्रमुख स्थानीय बाजारों में नियमित कूड़ा संग्रहण एवं निस्तारण के लिए संबंधित नगर निकायों के साथ एमओयू किए गए हैं। जिले में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुल 231 वाहनों का बेड़ा तैयार किया गया है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 134 ई-रिक्शा और 75 ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ सीएसआर एवं अन्य योजनाओं से उपलब्ध कराए गए वाहन शामिल हैं। विभिन्न विकासखंडों में जिला पंचायत की ओर से कॉम्पेक्टर का भी संचालन किया जा रहा है। इस पहल में कॉरपोरेट सेक्टर भी सहयोग कर रहा है। नेस्ले इंडिया ने सीएसआर के तहत सात इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए हैं। ये वाहन धर्मपुर, छत्तरपुर, बिंदूखेड़ा (फौजी मटकोटा), कीरतपुर, बागवाला, दानपुर और नगला तराई के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।



◆373 ग्राम पंचायतों के लिए 231 वाहनों का बेड़ा तैयार

जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री ने नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन, गिनाईं उपलब्धियां

योगी सरकार ने सपा-बसपा की गुंडागर्दी को किया नेस्तनाबूद : शाह

एजेंसी, नोएडा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि कहा योगी सरकार ने सपा-बसपा की गुंडागर्दी को नेस्तनाबूद कर दिया। सारे माफिया समाप्त हो गए, अब यूपी में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान की नींद उड़ा देती हैं। शाह ने कहा कि सपा-बसपा के शासन में अपराध की इंडस्ट्री चलती थी। कट्टा-तमंचा का कुटीर उद्योग लगता था। कट्टा उद्योग की जगह आज डिफेंस कॉरिडोर बना है। अमेठी में बनी राइफल नक्सलवादियों और आतंकियों की नींद उड़ा चुकी है। शाह सुबह साढ़े 11 बजे ट्रेड शो में पहुंचे। सीएम योगी पहले से ही वहां मौजूद थे। दोनों नेताओं ने एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी (गोल्फ कार्ट) में बैठकर ट्रेड शो देखा। स्टॉल पर प्रोडक्ट्स की जानकारी ली। मंच पर दोनों नेता काफी देर तक बातचीत करते रहे। योगी ने गृहमंत्री को राधा-कृष्ण की मूर्ति भेंट की। अमित शाह ने कहा- देशभर में बने डिफेंस के उत्पाद का विकास हुआ है। 2013-14 की तुलना में हमने 56 गुना ग्रोथ की है। इसमें यूपी ने ढेर सारा काम किया है। यूपी में बने ब्रह्मोश पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी राइफल नक्सलवादी और आतंकियों की नींद उड़ा चुकी है। सपा-बसपा के शासन में अपराध की इंडस्ट्री चलती थी। कट्टा और तमंचा का कुटीर उद्योग लगता था। कट्टा उद्योग की जगह आज डिफेंस कॉरिडोर बना है।



◆कहा- यूपी में बने ब्रह्मोश पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं

◆पहले यूपी में निवेशक आने से डरते थे

अमित शाह ने कहा- साल 2013 में यूपी सरकार ने एक इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। उस समय यह कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी। उस समय कानून-व्यवस्था को लेकर ऐसी स्थिति थी कि निवेशक यूपी आने से डरते थे। आज यूपी भयमुक्त है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में नोएडा, काशी और झांसी जैसे शहरों में भी ऐसी कॉन्फ्रेंस हो सकेंगी।

दुनिया को यूपी के उत्पादों की गुणवत्ता पर भरोसा : योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा- यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जापान, वियतनाम, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और ऑस्ट्रिया जैसे पार्टनर देश जुड़े हैं। दुनिया के कई देशों से आए इंटरनेशनल बायर्स को यूपी के उत्पादों की गुणवत्ता और यहां की मजबूत सप्लाई चेन पर भरोसा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पिछले चार वर्षों से प्रदेश के उत्पादों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का मंच बना है। इस साल 90 देशों के 500 से ज्यादा खरीदार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 36 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में 2,400 से ज्यादा प्रदर्शक ट्रेड शो में शामिल हुए हैं। विभिन्न देशों के साथ एमओयू हो चुके हैं और तकनीक और जॉइंट वेंचर के क्षेत्र में भी सहयोग की नई संभावनाएं बन रही हैं। यूपी के 79 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई पारंपरिक उत्पाद अब करोड़ों रुपए के कारोबार का आधार बन चुके हैं। सरकार का प्रयास इन स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़कर उन्हें नई पहचान दिलाना है।

हिम ई-पंचायत प्रोसिडिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश

पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद बैठकों का विवरण डिजिटल रूप में होगा सुरक्षित

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए हिम ई-पंचायत प्रोसिडिंग सिस्टम पोर्टल शुरू किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान (एमएसहिपा) में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला के दौरान पोर्टल का शुभारंभ किया। मंत्री ने इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों पर आधारित पत्रिका का भी विमोचन किया।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिम ई-पंचायत प्रोसिडिंग सिस्टम पोर्टल शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बैठकों की कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इससे बैठक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और बैठक से संबंधित अभिलेख सुरक्षित एवं व्यवस्थित डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगे।



नियमों की जानकारी और पालन पर जोर : मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं, नियमों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी होना जरूरी है। नियमों की सही जानकारी और पालन नहीं होने के कारण कई बार बजट का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता। इसके अलावा पंचायतों के निर्णयों से जुड़े विवाद और न्यायालयीन मामले भी सामने आते हैं। हिम ई-पंचायत व्यवस्था से बैठकों की कार्यवाही निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार दर्ज करने में मदद मिलेगी।

◆पारदर्शिता बढ़ाने के साथ नागरिकों को बैठक विवरण ऑनलाइन देखने की मिलेगी सुविधा

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का करीब 90 प्रतिशत क्षेत्र ग्रामीण है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार तकनीक के माध्यम से विभागीय कामकाज की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

एजेंडा से ई-हस्ताक्षर तक ऑनलाइन व्यवस्था : मंत्री के अनुसार पोर्टल से पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारी जुड़ सकेंगे। हिम एक्सेस के माध्यम से एक ही लॉगिन से सुविधा मिलने के कारण अलग-अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत कम होगी। पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद की बैठकों का एजेंडा, बैठक का विवरण और कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी।

बैठकों में प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्यों और ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी। बैठक के लिए जरूरी कोरम की स्थिति भी सिस्टम के माध्यम से निर्धारित की जा सकेगी। कार्यवाही तैयार होने के बाद ई-हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे कागजी अभिलेखों पर निर्भरता कम होगी और बैठक से संबंधित आंकड़े डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे।

अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि हिम ई-पंचायत पोर्टल को पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से जोड़ा जाएगा। इसके बाद भविष्य में आम नागरिक भी किसी पंचायत की बैठक की कार्यवाही ऑनलाइन देख सकेंगे।

मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोपों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकेश अग्निहोत्री का प्रदर्शन

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शामिल हुए। राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष हुए प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देश में मतदाता सूचियों और चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस लंबे समय से सवाल उठाती रही है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों ने मतदान के अधिकार और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ाई है।

13 करोड़ से अधिक नाम हटाने का दावा: अग्निहोत्री ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 13 करोड़ से अधिक नाम प्रारूप मतदाता सूचियों से हटाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के अनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार निर्वाचन आयोग के भीतर विभिन्न फैसलों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति दर्ज की।



मतदाता सूची पुनरीक्षण और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

राहुल गांधी के उठाए मुद्दों का किया उल्लेख

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और कथित 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाते रहे हैं। उनके अनुसार, अब निर्वाचन आयोग के भीतर दो आयुक्तों की ओर से दर्ज की गई आपत्तियों ने इस विषय को और चर्चा में ला दिया है। अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे सवालों का जवाब कई बार भाजपा नेताओं की ओर से दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग को प्रक्रिया और आंकड़ों के संबंध में स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि मतदाताओं के बीच किसी प्रकार की आशंका न रहे।

ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

अग्निहोत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने और उन्हें पद से हटाने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों में चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं, वहां आवश्यक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने दोबारा चुनाव कराने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा निर्वाचन प्रक्रिया की मूल जिम्मेदारी है। वहीं, निर्वाचन आयोग से जुड़े हालिया विवाद पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद या असहमति को लोकतांत्रिक संस्थान के भीतर होने वाली चर्चा के रूप में देखा जाना चाहिए।

अपना परिवार सुखी परिवार योजना की आवेदन तिथि बढ़ाने की उठी मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर को समाप्त होने के बाद मशोबरा विकासखंड के कई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रदेश सरकार से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है, ताकि निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाने वाले पात्र परिवारों को भी योजना में शामिल होने का अवसर मिल सके।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई परिवार निर्धारित अवधि के दौरान आय प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार नहीं करवा सके। दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण पात्र होने के बावजूद वे आवेदन नहीं कर पाए। लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि अंतिम तिथि बढ़ाकर छूटे हुए परिवारों को राहत दी जाए।

योजना के तहत पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।



◆समय पर दस्तावेज नहीं बनवा पाने से कई पात्र परिवार आवेदन करने से रह गए

इसके अलावा आवेदक परिवार के पास मनरेगा जॉब कार्ड होना और मनरेगा के तहत कार्य किया होना आवश्यक है। परिवार के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सरकार की ओर से निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य है।

स्थानीय लोगों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों को योजना की जानकारी देर से मिली। कुछ परिवार दस्तावेज संबंधी औपचारिकताएं समय पर पूरी नहीं कर सके। इसके कारण अंतिम तिथि समाप्त होने तक वे आवेदन नहीं कर पाए। लोगों का कहना है कि अतिरिक्त समय मिलने से ऐसे परिवार भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

हिमाचल में 28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल



अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और नई प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) वापस लेने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी और अधिकारी 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की हिमाचल इकाई ने शुक्रवार को शिमला में पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी।

यूएफबीयू हिमाचल के संयोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि हड़ताल में प्रदेश के सात बैंक कर्मचारी संगठन शामिल होंगे। हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। शिमला में कर्मचारी और अधिकारी उपायुक्त कार्यालय के सामने तीनों दिन शांतिपूर्ण धरना देंगे।

नरेंद्र शर्मा ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग वर्ष 2015 से की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने से बैंकिंग व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हो सकती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी ग्राहकों की परेशानी कम करने के लिए रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं।

एशियाई खेलों में सीमा कुमारी ने कांस्य जीत कर हिमाचल को किया गौरवान्वित

भारतेन्दु संवाददाता , शिमला। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की धाविका सीमा कुमारी ने एशियाई खेल-2026 में महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। जापान के आइची-नागोया में आयोजित प्रतियोगिता में सीमा ने 32 मिनट 50.05 सेकेंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि सीमा की सफलता पूरे हिमाचल के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में सीमा ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि चंबा की इस बेटी ने प्रदेश की खेल प्रतिभा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री के अनुसार सीमा की उपलब्धि प्रदेश के हजारों युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी।

सीमा कुमारी की इस उपलब्धि का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि महिलाओं की 10 हजार मीटर स्पर्धा में भारत को एशियाई खेलों में 16 वर्षों बाद पदक मिला है। सीमा ने शुरुआती दौर से ही पदक की दौड़ में अपनी स्थिति बनाए रखी और अंतिम चरण तक मजबूती से मुकाबला किया। वह बहरीन की विनफ्रेड यावी और जापान की नोजोमी तनाका के बाद तीसरे स्थान पर रहीं।

सीमा कुमारी चंबा के रेटा गांव से ताल्लुक रखती हैं। उनकी खेल प्रतिभा की पहचान शुरुआती दौर में स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं में हुई, जिसके बाद उन्होंने जिला और राज्य स्तर की स्पर्धाओं में भाग लेते हुए आगे का सफर तय किया। सीमित संसाधनों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना उनके खेल सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में एथलेटिक्स समेत विभिन्न खेलों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित करेगी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सीमा की आगामी 5,000 मीटर स्पर्धा के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। सीमा की जीत के बाद चंबा और हिमाचल प्रदेश में खुशी का माहौल है। उनके पदक को प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

ठियोग में कार सवार से पांच ग्राम चिट्टा बरामद, युवक गिरफ्तार



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को करीब पांच ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को थाना ठियोग की टीम सैंज-सोलन मार्ग पर भोटका मोड़ के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने वहां से गुजर रही एक कार को जांच के लिए रोका। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें सवार युवक के कब्जे से करीब पांच ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय कमल पुत्र स्वर्गीय करम चंद, निवासी तहसील ठियोग, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ थाना ठियोग में मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया है।

कोटखाई में एक स्वर में गूंजा वंदे मातरम्

कार्यक्रम संयोजक सूरज पाल चौहान ने सामूहिक गायन का किया नेतृत्व

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नगर पंचायत कोटखाई के अटल बिहारी वाजपेयी स्थल में 25 सितंबर को प्रात: 11 बजे वंदे मातरम् के सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर कोटखाई की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के तत्वावधान एवं मार्गदर्शन में एक स्वर, एक लय, एक स्थान और एक समय पर राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर किया गया।

कार्यक्रम में नगर पंचायत कोटखाई के अध्यक्ष राजेश चौहान, ग्राम पंचायत के प्रधान सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ प्रताप नाथ भी विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों और लोगों के साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन किया। सामूहिक गायन कार्यक्रम में गिरिराज पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल कोटखाई और क्षेत्र के अन्य स्थानीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक, शिक्षक और समाज के अन्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पूरे स्थल पर देशभक्ति का वातावरण देखने को मिला।

आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत करने में सहायक होते हैं। सामूहिक गायन के माध्यम से बच्चों और समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया।



◆विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में लिया भाग

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने एक साथ राष्ट्रगीत का गायन कर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। आयोजकों ने कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी अतिथियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को देश की संस्कृति, राष्ट्रभावना और सामाजिक एकजुटता से जोड़ना बताया गया।

रोहडू में अस्पताल से लौट रही युवती से बदसलूकी, एफआईआर दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। रोहडू थाना क्षेत्र में अस्पताल से बहन और भाई के साथ घर लौट रही युवती का कथित तौर पर कार और स्कूटर सवार लोगों ने पीछा किया। आरोप है कि घर पहुंचने के बाद आरोपियों ने युवती और उसके परिवार के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इस दौरान युवती के साथ बदसलूकी करने और उसकी बहन से छेड़छाड़ का प्रयास भी किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में रोहडू निवासी युवती ने बताया कि वह अपनी बहन और भाई के साथ अस्पताल से घर लौट रही थी। इसी दौरान नीली ऑल्टो कार और नीले स्कूटर पर सवार लोग उनका पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए। शिकायत के अनुसार, वहां पहुंचकर आरोपियों ने परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट की। घटना में युवती को चोटें आई हैं।



आरोप है कि एक युवक ने युवती के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए उसे गलत तरीके से छुआ और उसकी बहन के साथ भी छेड़छाड़ का प्रयास किया। शिकायत में भाई के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है।

शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 74, 78, 115(2), 352 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है।

कूटनीति भारत-फिनलैंड सहयोग और हिमाचली पर्यटन की संभावनाओं पर प्रतिनिधिमंडल ने किया विचार-विमर्श

पठानियां के सम्मान में हेलसिंकी उच्चायोग ने रात्रिभोज किया आयोजित

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां के सम्मान में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी स्थित भारतीय उच्चायोग में रात्रिभोज का आयोजन किया गया। अपने अध्ययन प्रवास के दौरान इटली से फिनलैंड पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारतीय उच्चायोग के मिशन प्रमुख मयंक गोयल ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर भारत-फिनलैंड संबंधों के साथ हिमाचल प्रदेश और फिनलैंड के बीच सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और सहयोग को आगे बढ़ाने के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें शिक्षा, पर्यटन, हरित ऊर्जा, सतत विकास तथा संसदीय कार्यप्रणाली के अनुभवों के आदान-प्रदान जैसे विषय प्रमुख रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश में इन क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं और संसाधनों की जानकारी भी साझा की।



कुलदीप सिंह पठानियां ने भारतीय उच्चायोग के मिशन प्रमुख मयंक गोयल को आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत और फिनलैंड के संबंधों को मजबूत बनाने तथा वहां रह रहे भारतीय समुदाय के सहयोग के लिए उच्चायोग के प्रयासों की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष ने मयंक गोयल को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया।

विधानसभा अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हिमाचली टोपी, शॉल तथा राज्य के अन्य पारंपरिक उत्पादों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के प्रमुख स्थलों और उनकी संभावनाओं की जानकारी देते हुए भारतीय उच्चायोग के माध्यम से इनका विदेशों में प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया।

एचपीटीडीसी मुख्यालय स्थानांतरण के खिलाफ हाईकोर्ट याचिकाएं ने की खारिज

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के कॉरपोरेट कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी सरकारी कार्यालय का स्थान तय करना सरकार का नीतिगत निर्णय है। ऐसे मामलों में अदालत सरकार के नीतिगत फैसले के गुण-दोष की समीक्षा अपील की तरह नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंदर नेगी की खंडपीठ ने 16 सितंबर को दोनों याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इनमें एक याचिका सेवानिवृत्त एचपीटीडीसी कर्मचारी दाबे राम और दूसरी सेवानिवृत्त कर्मचारी मुकेश भारद्वाज ने दायर की थी। दोनों याचिकाओं में शिमला स्थित एचपीटीडीसी के कॉरपोरेट कार्यालय को होटल कश्मीर हाउस, धर्मशाला स्थानांतरित करने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से स्थानांतरण के कारण उनके सेवा संबंध समाप्त होने सहित अन्य मुद्दे उठाए गए थे।

सरकार और एचपीटीडीसी की ओर से अदालत को बताया गया कि 30 अप्रैल 2025 को धर्मशाला-कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था। इसके बाद निगम के निदेशक मंडल ने शिमला के बजाय धर्मशाला स्थित अपने भवन में कॉरपोरेट कार्यालय स्थानांतरित करने के लिए सरकार से मंजूरी लेने का निर्णय लिया था।

कार्यालय ग्राम पंचायत बैला विकास खण्ड गोहर तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0प्र0)
निविदा आमंत्रण सूचना

पंचायत बैठक में सर्वसम्मती से प्रस्ताव पारित हुआ कि ग्राम पंचायत बैला में विभिन्न मदों के अंतर्गत बित वर्ष 2026-27 में विकास कार्य करवाये जाने है जिस हेतु जुलाई माह में कोटेशने आमंत्रित की गयी थीं परन्तु कुछ सामग्रीयों की कुटेशने प्राप्त ना होने के कारण कार्यो को समाप्त करना मुश्किल है । इसलिए निम्न प्रकार से सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु कोटेशने आमंत्रित की जानी अनिवार्य है ताकि विकास कार्यो को सुचारु रूप से चलाया जा सके । निविदायें/कोटेशनें कार्यालय ग्राम पंचायत बैला में 02/10/2026 को 4 बजे तक किसी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है। यह निविदायें/कोटेशनें दिनांक 03/10/2026 को 11 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत बैला में कमेटी के समक्ष खोली स्वीकृत **सामग्री का विवरण-** 1. सरिया (ISI Marked / HYSD TMT) All Sizes- प्रति क्विंटल, 2. Steel(Hollow Sections of all Sizes)-प्रति क्विंटल, 3. Steel (solid sections of all sizes)-प्रति क्विंटल, 4. GI sheets/Coloured roofing sheets /PGI Sheets All) Size- प्रति पीस, 5. All Hardwares Items-प्रति वर्ग फुट/प्रति पीस/किलो 6. Segrigation shed unit-प्रति यूनिट। **नियम व शर्ते :-** 1) निविदादाता के पास अपना पंजीकरण नंबर निविदा पर भरना सुनिश्चित करें। इसके साथ R.C.No.GST.CST.No. की छाया प्रति लगाना अति आवश्यक है। सभी निविदाएं सील बन्द लिफाफे में देनी अनिवार्य होगी। अधूरी व खुली निविदाएं मान्य नहीं होगी। 2) GST/CST दरें निविदा प्रपत्र में भरी गई दरों में ही शामिल होगी। 3) सामग्री की आपूर्ति लोक निर्माण विभाग के स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होगी । 4) निर्माण सामग्री कार्य स्थल / सड़क तक उपलब्ध करवानी होगी । 5) पारित निविदादाता को मु020000/- रूपये धरोहर/सुरक्षित राशी FDR के रूप में ' प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत बैला' के नाम 5 दिन में जमा करवाना अनिवार्य है तत्पश्चात ही सामग्री आपूर्ति आदेश दिया जाएगा । 5 दिन में FDR जमा ना करने की स्थिति में निविदा को निरस्त किया जाएगा । 6) ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्राधिकार में एक ही मूल्य देय होगा व अस्वीकृत सामग्री की अदायगी देय नहीं होगी । 7) निविदादाता यदि सामग्री आपूर्ति समयानुसार नहीं कर पाता है तो उसकी गत समय में दी गयी सामग्री की देय राशी का भुगतान नहीं किया जायेगा और न ही अग्रिम / सुरक्षित राशी वापिस होगी । 8) किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत / अस्वीकृत करने, सशर्त निविदा, समान दर रहने की स्थिति में, एक या एक से अधिक निविदादाताओं के लिए कार्य आदेश निर्गत करने, सामग्री की गुणवता के चयन तथा निविदाएं किसी भी समय रद्द करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । 9) सामग्री लेने का अंतिम मूल्य / निर्णय विभाग की Justification व पारित निविदादाता के साथ negotiation अनुसार/उपरांत किया जायेगा । 10) सामग्री की अदायगी तकनीकी सहायक /JE की Verification अनुसार ही की जाएगी । सर्वसम्मति से पारित है।

प्रधान/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत बैला विकास खण्ड गोहर तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

अल्मोड़ा अर्बन बैंक की 35वीं वार्षिक बैठक संपन्न



भारतेन्दु संवाददाता, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की 35वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक मालरोड स्थित होटल शिखर में बैंक की अध्यक्ष डॉ. वसुधा पंत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बैंक की वित्तीय प्रगति, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रबंधन ने अंशधारकों को नौ प्रतिशत लाभांश देने की घोषणा की। प्रबंध निदेशक पीसी तिवारी ने बताया कि बैंक का कुल कार्य व्यवसाय 6600 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने 49.54 करोड़ रुपये का सकल लाभ अर्जित किया और 14 करोड़ रुपये अग्रिम आयकर के रूप में जमा कराया। बैंक की निज पूंजी बढ़कर 725.85 करोड़ रुपये हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंक की प्रतिभूतियों में 1691.45 करोड़ रुपये विनियोजित हैं। कुल ऋण आवंटन का 74.59 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया गया। बैंक की शाखाओं की संख्या 69 हो गई है और जल्द पांच नई शाखाएं खोलने की तैयारी है। वर्ष 2028 तक 80 शाखाएं और 8000 करोड़ रुपये का कार्य व्यवसाय हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तराखंड में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर सरकार का जोर : सीएम धामी

कहा- विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

भारतेन्दु संवाददाता,हल्द्वानी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। शुक्रवार को हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के साथ प्रदेश की संस्कृति, पहचान और देवभूमि की विशिष्टता का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय करीब चार हजार करोड़ रुपये का बजट अब लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि और उद्यानिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश ने प्रगति की है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन और फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में होम-स्टे की संख्या में करीब 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

इकोलॉजी और इकॉनमी में संतुलन जरूरी : धामी

हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संत समाज, अखाड़ों, धार्मिक संगठनों और अन्य हितधारकों के सुझावों के आधार पर व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें और कुंभ का आयोजन सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित तरीके से हो। मुख्यमंत्री ने अनियोजित विकास और जलवायु परिवर्तन को उत्तराखंड के सामने प्रमुख चुनौतियां बताते हुए कहा कि इकोलॉजी और इकॉनमी एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए। हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों की धारण क्षमता का वैज्ञानिक आकलन कराया जा रहा है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड और केरल संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे। उन्होंने कहा कि 'हाउस

उत्तराखंड में विकास के नए आयाम पर जोर



उन्होंने कहा कि विकास केवल बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। उत्तराखंड की विकास यात्रा में पर्यावरण, संस्कृति और देवभूमि की पहचान का संरक्षण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

ऑफ हिमालयाज' के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक के ब्याजमुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़कर स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को पारदर्शी व्यवस्था के तहत रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं पर रोक के लिए कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और अनियमितताओं में शामिल 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई है।

विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका : बहुगुणा



भारतेन्दु संवाददाता, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के दो दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तिलोथ स्थित गंगोत्री फिजिकल एकेडमी पहुंचकर भारतीय सेना एवं अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा अभ्यर्थियों से संवाद किया। उन्होंने युवाओं से उनकी तैयारियों, अनुभवों और चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश सेवा का सपना लेकर कठिन परिश्रम कर रहे युवाओं का अनुशासन, मेहनत और समर्पण प्रेरणादायी है। उन्होंने युवाओं से इसी भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

इससे पहले प्रभारी मंत्री ने पौराणिक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत राजकीय आदर्श कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में आयोजित 'मेरे सपनों का भारत' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में 'तब और अब' विषय पर चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने चित्रकलाओं और रंगोली के माध्यम से विकसित भारत को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। बच्चों ने देश की 25 वर्षों की विकास यात्रा और उपलब्धियों से जुड़े सवाल भी प्रभारी मंत्री से पूछे। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं।

◆मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

प्रभारी मंत्री ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से इनका लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

बद्रीनाथ धाम में कार्यक्रम पर यूकेडी आक्रोशित, भाजपा सरकार का पुतला फूंका

बद्रीनाथ धाम की मर्यादा भंग करने का आरोप, उक्रांद ने जताया विरोध

अनिल थपलियाल

देहरादून। बद्रीनाथ धाम के अराइवल प्लाजा में गायिका प्रियंका मेहर के कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। द्रोण चौक पर एकत्रित उक्रांद पदाधिकारियों ने सरकार का पुतला दहन कर धाम की परंपराओं और मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया। केंद्रीय उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में इस तरह का आयोजन पवित्र धाम की मर्यादा के साथ-साथ देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचाता है।

केंद्रीय महामंत्री संगठन गणेश काला ने कहा कि बद्रीनाथ धाम विश्वभर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यहां



ऊंची आवाज में डीजे व स्पीकर बजाना उचित नहीं है। केंद्रीय महामंत्री देवचंद्र उत्तराखंडी ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता का मुद्दा उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल किए।

सह मीडिया प्रभारी प्रकाश भट्ट ने सरकार से ऐसे आयोजनों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने और भविष्य में धामों व उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन नहीं करने का वादा करने की मांग की। उक्रांद नेताओं ने बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूर्व में हुए ऐसे आयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि धामों की धार्मिक परंपराओं और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आयोजनों के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए।

टेबल टेनिस में चमोली के 10 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय चयन



भारतेन्दु संवाददाता, चमोली। चंपावत में 21 से 23 सितंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चमोली के 23 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 10 खिलाड़ियों का चयन अक्टूबर में मध्य प्रदेश में होने वाली राष्ट्रीय स्कूली टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अंडर-17 बालिका वर्ग में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ज्योतिर्मठ की अंशिका नेगी ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर-14 बालिका वर्ग में विद्या मंदिर ज्योतिर्मठ की काव्या और बालक वर्ग में आरव ने स्वर्ण पदक हासिल किया।

अंडर-19 में सानिया और सुहानी, अंडर-17 बालिका वर्ग में अंशिका नेगी, दिया सैनी, परिधि और प्रिया तथा बालक वर्ग में समीर का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। अंडर-14 बालिका वर्ग में काव्या व अंशिका और बालक वर्ग में आरव चयनित हुए हैं। टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

आईएचएम देहरादून में एहसास एलुमनी मीट 2026 का आयोजन

पूर्व छात्रों ने साझा किए अनुभव, विद्यार्थियों को दिए करियर मंत्र

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), देहरादून में 'वेलकम बैक' थीम पर एहसास एलुमनी मीट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न बैचों के पूर्व छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रधानाचार्य डॉ. शिव मोहन ने पूर्व छात्रों का स्वागत करते हुए संस्थान की विरासत को मजबूत करने और वर्तमान विद्यार्थियों को प्रेरित करने में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में पूर्व छात्रों ने शिक्षकों और साथियों के साथ पुरानी स्मृतियां साझा कीं तथा अपने व्यावसायिक अनुभवों और उपलब्धियों के बारे में बताया।

◆मीट में शिक्षकों और पूर्व छात्रों ने साझा की स्मृतियां

अनुभवों की साझा हुई जानकारी



विद्यार्थियों के साथ संवाद सत्र में उन्हें होटल प्रबंधन और आतिथ्य क्षेत्र में करियर के अवसरों, उद्योग की अपेक्षाओं और कार्यक्षेत्र की चुनौतियों की जानकारी मिली। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं और विशिष्ट पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी और डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी भी शामिल हुए। वरिष्ठ व्याख्याता उदय प्रताप सिंह चाम्याल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आयोजन ने संस्थान और पूर्व छात्रों के बीच आत्मीय संबंधों को और मजबूत किया।

सीएसआईआर के 85वें स्थापना दिवस पर ओपन डे आयोजित

भारतेन्दु संवाददाता, रुड़की



◆सुरक्षित और आपदा-रोधी निर्माण तकनीकों से रूबरू हुए विद्यार्थी

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीएसआईआर-केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) में 25 सितंबर को ओपन डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को वैज्ञानिक अनुसंधान, भवन विज्ञान, निर्माण तकनीकों और इनके व्यावहारिक उपयोग से परिचित कराना रहा। कार्यक्रम में मेथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की 112 छात्राओं और तीन संकाय सदस्यों ने संस्थान का भ्रमण किया।

विद्यार्थियों ने सीबीआरआई की विभिन्न प्रयोगशालाओं और अनुसंधान सुविधाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने डॉ. बिलिंग प्रदर्शनी दीर्घा में भवन निर्माण एवं वास्तुकला से जुड़े मॉडल और तकनीकें देखीं। वैज्ञानिकों ने उन्हें अनुसंधान परियोजनाओं, नवीन निर्माण तकनीकों और वैज्ञानिक नवाचारों की जानकारी दी तथा उनके सवालों के जवाब दिए।

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने एनईईटीएफ, 3डी सुविधा, अग्नि सुरक्षा अभियांत्रिकी, ग्रामीण पार्क और सौर तापीय परीक्षण सुविधा का अवलोकन किया। उन्हें सुरक्षित, सतत, आपदा-रोधी, ऊर्जा-कुशल और किफायती भवन निर्माण के साथ आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी मिली। संस्थान के निदेशक प्रो. आर. प्रदीप कुमार ने विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति जिज्ञासा विकसित करने और अनुसंधान व नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

पुरानी पेंशन समेत 12 मांगों पर गरजे कर्मचारी

पौड़ी में कर्मचारियों ने निकाली रैली डीएम कार्यालय पर दिया धरना



भारतेन्दु संवाददाता, पौड़ी। पुरानी पेंशन बहाली समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पौड़ी में प्रदर्शन किया। कर्मचारी एजेंसी चौक से रैली निकालते हुए माल रोड, बस स्टेशन और धारा रोड होते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना दिया। इसके बाद डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, गोल्डन कार्ड की समस्याओं का समाधान, पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवा संबंधी विसंगतियों समेत 12 मांगों को लेकर लंबे समय से शासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष सीताराम पोखरियाल ने कहा कि मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।

चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून



भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में कथित अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को देहरादून में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सचिवालय तक मार्च निकाला और निर्वाचन कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला भी दहन किया गया। प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सीडब्ल्यूसी सदस्य करन माहरा, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी सहित कई वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल हुए।

कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर को सौंपकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने तथा पूर्व में लिए गए फैसलों को निरस्त करने की मांग की। पार्टी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआइआर के दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फार्म-7 दाखिल किए गए हैं, जिससे पात्र मतदाताओं के नाम हटने की आशंका है। उन्होंने मांग की कि फार्म-7 आवेदनों का विधानसभा और बूथवार विवरण सार्वजनिक किया जाए तथा असामान्य संख्या में आपत्तियां दाखिल करने वालों की जांच कराई जाए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि किसी पात्र मतदाता का नाम हटाने से पहले भौतिक सत्यापन और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।

परेशानी भारी वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण से लेकर सुरक्षित बैरियर तक, हाईवे पर कई चुनौतियां, ईंटों से भरा ट्रक हॉस्टल की दीवार में घुसा

मोहब्बेवाला बना हादसों का शिकार, कब जागेगी सरकार?

विकास बलूनी

देहरादून। मोहब्बेवाला हाईवे एक बार फिर हादसे का गवाह बना है। शुक्रवार तड़के करीब साढ़े चार बजे सहारनपुर की ओर से आ रहा ईंटों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित ग्राफिक एरा गर्ल्स हॉस्टल की दीवार में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हॉस्टल की बाउंड्री वॉल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक चालक को चोट आई।

गनीमत रही कि हादसा तड़के हुआ। यदि यही घटना दिन के व्यस्त समय में होती और हॉस्टल के बाहर छात्राएं, कर्मचारी या राहगीर मौजूद होते, तो इसका परिणाम कहीं अधिक गंभीर हो सकता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार किसी बड़े जनहानि वाले हादसे के बाद ही व्यवस्था जागेगी?

मोहब्बेवाला में लगातार हो रहे हादसे अब महज संयोग नहीं लगते। पिछले दिनों इसी क्षेत्र में ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत और अन्य लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस की ओर से



एनएचएआई को हादसों की रोकथाम के लिए नोटिस भी भेजा गया है और सड़क की तकनीकी जांच के निर्देश दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई है।

फिर भी आज का हादसा यह सवाल खड़ा करता है कि जांच, नोटिस और आश्वासन के बाद जमीन पर ठोस बदलाव आखिर कब दिखाई देगा?

मोहब्बेवाला की ढलान और भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए केवल अस्थायी इंतजाम पर्याप्त नहीं हो सकते। जरूरत है कि सड़क की स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट, ढलान की इंजीनियरिंग समीक्षा, भारी वाहनों की गति पर प्रभावी नियंत्रण, पर्याप्त चेतावनी संकेत, सुरक्षित बैरियर और आवश्यकतानुसार ट्रैफिक डायवर्जन जैसे उपायों पर समयबद्ध कार्रवाई हो।

सबसे बड़ा सवाल यही है—

क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है?

मोहब्बेवाला हाईवे लोगों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने का रास्ता होना चाहिए, डर और अनिश्चितता का कारण नहीं। अब जरूरत खाना-पूर्ति की कार्रवाई की नहीं, बल्कि हादसों की पुनरावृत्ति रोकने वाले ठोस और जवाबदेह सुरक्षा उपायों की है।

सरकार और संबंधित एजेंसियों को तय करना होगा—अगली खबर फिर किसी हादसे की होगी या इस बार कोई स्थायी समाधान जमीन पर दिखाई देगा?

मोहब्बेवाला में लगातार हादसों पर विधायक विनोद चमोली ने जताई चिंता



मोहब्बेवाला हाईवे पर लगातार हो रहे हादसों ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 20 सितंबर को सीमेंट से भरे ट्रक के पलटने से बाइक सवार की मौत और अन्य लोगों के घायल होने की घटना के बाद क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा उपायों की मांग फिर उठी है।

क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली ने भी लगातार हादसों को गंभीर और चिंताजनक बताया है। मोहब्बेवाला क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसों को लेकर भारतेंदु शिखर संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से सवाल उठाता रहा है। इसी क्रम में कार्यकारी संपादक विकास बलूनी ने क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली से सवाल किया कि यदि सड़क की तकनीकी परिस्थितियों और अन्य कारणों के चलते यहां लगातार हादसे हो रहे हैं, तो इन पर अंकुश लगाने के लिए स्थायी समाधान कब तक लागू किया जाएगा? विधायक चमोली ने बताया कि एनएच अधिकारियों और संबंधित विभागों से लगातार बातचीत की जा रही है, ताकि तकनीकी रूप से प्रभावी समाधान निकाला जा सके। मोहब्बेवाला में लगाए गए रबर स्ट्रिप या रंबल स्ट्रिप को लेकर भी स्पष्ट किया गया कि यह स्थायी समाधान नहीं है। सड़क की ढलान, डिजाइन, भारी वाहनों की गति और ब्रेकिंग व्यवस्था समेत सुरक्षा मानकों का व्यापक तकनीकी मूल्यांकन जरूरी है। साइन बोर्ड, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित बैरियर और आवश्यक यातायात नियंत्रण जैसे उपाय भी किए जाने चाहिए।अब स्थानीय लोग आश्वासन नहीं, समयबद्ध कार्रवाई चाहते हैं।

गौरीकुंड में चेकिंग के दौरान 131 बोतल शराब बरामद, एक गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। अवैध शराब की तस्करी और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गौरीकुंड पुलिस ने चेकिंग के दौरान 131 बोतल शराब बरामद की है। 25 सितंबर को गौरीकुंड बैरियर पर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सोनप्रयाग की ओर से आ रहे एक खच्चर संचालक को रोका गया। पुलिस के अनुसार, उसे देखकर उसके पीछे आ रहे दो अन्य घोड़ा संचालक अपने घोड़ों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों घोड़ों पर लदे सामान की तलाशी ली तो अन्य सामग्री के साथ 11 पेटी में 131 बोतल शराब बरामद हुई। शराब को जब्त कर एक आरोपित शेर बहादुर, निवासी कालीकोट, नेपाल, हाल निवासी सोनप्रयाग पार्किंग, के खिलाफ सोनप्रयाग कोतवाली में आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपित को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं, घोड़ों के टैग नंबर के आधार पर फरार आरोपितों और अन्य संलिप्त लोगों की पहचान की जा रही है।

चंडीगढ़ में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

चुनाव आयोग कार्यालय की ओर बढ़ रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, वाटर कैनन चलाया

पंजाब कांग्रेस ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग कार्यालय की ओर बढ़ रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।



प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने किया। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की। पार्टी का विरोध मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर है। कांग्रेस का कहना है कि इन मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

बैरिकेड तोड़ने की कोशिश पर वाटर कैनन : सेक्टर-17 में चुनाव आयोग कार्यालय की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें पीछे धकेला और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन चलाया। इसके बाद कई नेताओं को पुलिस वाहनों में बैठाकर हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।

मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सवाल : पंजाब कांग्रेस विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने विधानसभा चुनाव तक इस प्रक्रिया को रोकने और पिछली मतदाता सूचियों के आधार पर चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता और मतदाता सूची से जुड़े निर्णयों को सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई है।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि आयोग के भीतर तकनीकी टिप्पणियां और सवाल बहुसदस्यीय संस्था की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े अंतिम निर्णय तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए हैं।

चन्नी और बाजवा प्रदर्शन से रहे दूर : प्रदर्शन में डॉ. राजकुमार वेरका, परगट सिंह समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। इससे पंजाब कांग्रेस के भीतर नेताओं की एकजुटता को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई।

सचिन पायलट के पंजाब प्रभारी बनने के बाद यह पार्टी का दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इससे पहले 15 सितंबर को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास की ओर निकाले गए मार्च में पायलट, राजा वड़िंग और बाजवा समेत कई नेता एक साथ नजर आए थे।

शुक्रवार के प्रदर्शन में हिरासत में लिए गए नेताओं के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर डटे रहे और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पार्टी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अपने सवालों को आगे भी उठाने की बात कही है।

प्रदर्शन के दौरान सेक्टर-17 में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पुलिस ने चुनाव आयोग कार्यालय के आसपास अतिरिक्त जवानों की तैनाती की थी। कांग्रेस नेताओं के हिरासत में लिए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने कुछ देर तक मौके पर नारेबाजी की। पार्टी नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए और चुनाव प्रक्रिया में सभी पक्षों का विश्वास कायम रहना जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से संबंधित आपत्तियों और शिकायतों पर स्पष्ट जवाब दिया जाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया।

पंजाब में अध्यापकों की गैर-शैक्षणिक ड्यूटी पर शिक्षा विभाग ने लगाई रोक

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर । स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर सख्ती दिखाई है। विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि अध्यापकों को कानून के तहत स्वीकृत कार्यों के अलावा किसी भी गैर-शैक्षणिक या प्रशासनिक कार्य के लिए न तो मांगा जाए और न ही तैनात किया जाए।

विभाग के अनुसार, जिला और उपमंडल स्तर पर अध्यापकों को लंबे समय तक विभिन्न प्रशासनिक और अन्य गैर-शिक्षण कार्यों में लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे कक्षाओं में पढ़ाई प्रभावित होने के साथ शिक्षा की निरंतरता और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों पर भी असर पड़ रहा है। विभाग ने ऐसी तैनाती तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं।

30 सितंबर के बाद स्कूलों में लौटेंगे अध्यापक : पत्र में मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। इस कार्य के लिए बड़ी संख्या में अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है। विभाग ने कहा कि यह प्रक्रिया 30 सितंबर को पूरी होनी है। इसके बाद आवश्यकता से अधिक समय तक अध्यापकों को स्कूलों से बाहर न रखा जाए और उन्हें उनकी मुख्य शिक्षण जिम्मेदारियां संभालने के लिए वापस भेजा जाए।



केवल तीन कार्यों में लग सकेगी ड्यूटी : विभाग ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा संबंधित अदालती निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अध्यापकों को केवल चुनाव, जनगणना और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए ही तैनात किया जा सकता है। इन कार्यों में भी आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम संख्या में अध्यापकों की ड्यूटी लगाने को कहा गया है।

स्कूल समय के बाद हो स्वीकृत ड्यूटी : जहां संभव हो, स्वीकृत कार्यों की ड्यूटी स्कूल समय के बाद या गैर-शिक्षण दिवसों में करवाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने पहले उपलब्ध गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं लेने को प्राथमिकता देने को कहा है। चुनावी जिम्मेदारी निभा रहे अध्यापकों पर अतिरिक्त जिला स्तरीय गैर-संबंधित कार्यों का बोझ नहीं डालने के भी निर्देश हैं।

सर्वेक्षण और तस्दीक के काम से भी दूरी : उपायुक्तों से कहा गया है कि अध्यापकों को सर्वेक्षण, तस्दीक या सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए न मांगा जाए, जब तक वह कार्य कानून के तहत स्वीकृत श्रेणी में न आता हो। विशेष परिस्थिति में स्वीकृत कार्यों के अलावा अध्यापकों की तैनाती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। विभाग ने सभी उपायुक्तों को आदेशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

राजजीत केस में पंजाब पुलिस के आला अफसर आमने-सामने, बढ़ा विभागीय टकराव और विवाद

ड्रग जांच ने पुलिस मुख्यालय की कार्यप्रणाली और अधिकारियों के आपसी मतभेद किए उजागर

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। बर्खास्त एआइजी राजजीत सिंह हुंदल से जुड़ा ड्रग मामला केवल एक पुलिस अधिकारी की भूमिका की जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के बीच भी टकराव पैदा किया था। इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की जांच में राजजीत सिंह की भूमिका पर सवाल उठे। करीब नौ साल पुराने इस प्रकरण में 24 सितंबर 2026 को राजजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मामला फिर चर्चा में है।



मामला तब गहराया जब एसटीएफ ने इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंह को मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया। जांच में इंदरजीत के कथित तौर पर नशा तस्करों से संबंध और मामलों में हेरफेर के आरोप सामने आए। इसके बाद तत्कालीन एसटीएफ प्रमुख एडीजीपी हरप्रीत सिंह सिद्धू ने राजजीत सिंह और इंदरजीत के संबंधों की जांच आगे बढ़ाई। राजजीत ने आरोपों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और जांच में पक्षपात का आरोप लगाया।

इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर राजजीत सिंह की भूमिका की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया। इसमें तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, प्रबोध कुमार और कंवर विजय प्रताप सिंह शामिल थे। विशेष जांच दल की रिपोर्टों में राजजीत की इंदरजीत सिंह के साथ कथित मिलीभगत और पुलिस पद के दुरुपयोग से जुड़े गंभीर आरोपों का उल्लेख हुआ। बाद में राज्य सरकार ने इन रिपोर्टों के आधार पर अप्रैल 2023 में राजजीत को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

जांच के दौरान पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के बीच भी मतभेद सामने आए। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और तत्कालीन डीजीपी सुरेश अरोड़ा तथा डीजीपी इंटेलिजेंस दिनकर गुप्ता के बीच विवाद अदालत तक पहुंचा। स्थिति ऐसी बनी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पुलिस अधिकारियों को अनुशासन और कमांड व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत देनी पड़ी। राजजीत सिंह के खिलाफ बाद में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले भी सामने आए।

एक अक्टूबर से शुरू होगी अमृतसर से कोलकाता सीधी उड़ान सेवा

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। पंजाब और पश्चिम बंगाल के बीच हवाई संपर्क एक बार फिर मजबूत होने जा रहा है। इंडिगो एयरलाइन एक अक्टूबर से श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अमृतसर से कोलकाता के लिए सीधी उड़ान सेवा दोबारा शुरू करने जा रही है। यह सेवा सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। इससे अमृतसर और कोलकाता के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इस सेवा के दोबारा शुरू होने से पंजाब से पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को भी लाभ होगा। कोलकाता के रास्ते गुवाहाटी के लिए आगे की हवाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को अलग-अलग उड़ानों की व्यवस्था करने की जरूरत कम होगी और पूर्वोत्तर की यात्रा का समय भी बच सकता है। नई उड़ान सेवा से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल और असम से श्री हरिमंदिर साहिब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अमृतसर पहुंचना आसान होगा। इसके अलावा पर्यटकों, विद्यार्थियों और कारोबारियों को भी सीधी उड़ान का लाभ मिलेगा।

भाजपा कार्यालय हमले की जांच में एनआइए ने बढ़ाई रफ्तार

विदेशी साजिश, धन लेनदेन और हथियारों की कड़ियां खंगालेगी केंद्रीय जांच एजेंसी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित पंजाब भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर एक अप्रैल को हुए ग्रेनेड हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआइए को सौंपने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद एनआइए ने नई प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की सुनवाई अब एनआइए की विशेष अदालत में होगी।

जांच अपने हाथ में लेने के बाद एनआइए ने मामले से जुड़े न्यायिक अभिलेख हासिल करने के लिए चंडीगढ़ जिला अदालत में आवेदन किया था। आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले से संबंधित सभी न्यायिक रिकॉर्ड एनआइए की विशेष अदालत को भेजने के निर्देश दिए हैं। इनमें चंडीगढ़ पुलिस की ओर से 13 जुलाई को दाखिल आरोपपत्र, मामले से संबंधित दस्तावेज, अब तक हुई जांच से जुड़े कागजात और अदालत में हुई कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड शामिल है।



11 आरोपितों को विशेष अदालत में किया जाएगा पेश : मामले में जेल में बंद 11 आरोपितों को भी अब एनआइए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से की गई शुरुआती जांच में हमले के पीछे विदेश में बैठे कथित संचालकों की भूमिका सामने आने की बात कही गई थी। जांच में पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं।

पुलिस जांच के अनुसार, विदेश में बैठे कथित संचालकों की ओर से हमले के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये अलग-अलग किस्तों में भेजे गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि हमले को अंजाम देने वाले गुरतेज उर्फ तेजी और अमनप्रीत सिंह उर्फ अमन को पांच-पांच हजार रुपये दिए गए। इसके अलावा अमनप्रीत के बैंक खाते में 10 हजार रुपये स्थानांतरित किए गए थे।

हमले के बाद आरोपितों ने बदले ठिकाने : पुलिस के अनुसार, भाजपा कार्यालय पर हमले का वीडियो सामने आने के बाद गुरतेज और अमन वहां से निकल गए थे। दोनों पहले खाटू श्याम पहुंचे और इसके बाद रेवाड़ी गए, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।

जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि हमले की साजिश पुर्तगाल में बैठे बलजोत सिंह ने रची थी। इसके अलावा फ्रांस में मौजूद सुरजीत उर्फ सरपंच और जर्मनी में रह रहे औजला की भूमिका की भी जांच में बात सामने आई थी।

ड्रोन से हथियार पहुंचाने का दावा: जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से दो हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल और 25 से 30 कारतूस भारत पहुंचाए गए थे। अब एनआइए विदेश में बैठे कथित संचालकों, धन के लेनदेन, हथियारों की आपूर्ति और हमले की पूरी साजिश की कड़ियों की जांच करेगी। मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और पहले की जांच का रिकॉर्ड एनआइए को सौंपे जाने के बाद जांच आगे बढ़ेगी।

अवैध शराब पर कार्रवाई से नाराज कारिंदों ने एक्साइज इंस्पेक्टर को पीटा

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे एक्साइज इंस्पेक्टर हरिसमरन सिंह से चंडीगढ़ में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि शराब तस्करी के मामलों में कार्रवाई से नाराज शराब ठेकेदार के कारिंदों ने 19 सितंबर की रात सेक्टर-24 के पास उनका रास्ता रोक लिया। उन्हें कार से बाहर निकालकर धक्का-मुक्की की गई और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। आरोपितों पर कार की चाबी और मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप है।



हरिसमरन सिंह के अनुसार, वह चंडीगढ़ में परिवार के साथ रहते हैं और पंजाब में शराब तस्करी से जुड़े मामलों की जांच कर रहे हैं। पिछले करीब एक महीने में चंडीगढ़ से पंजाब जा रही लगभग 300 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई, जिसके संबंध में सात मामले दर्ज किए गए। जांच के दौरान सेक्टर-24 स्थित हिमालय वाइन नामक शराब ठेकेदार कंपनी की संलिप्तता सामने आने का दावा किया गया है।

इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना वाली रात कुछ कारिंदों ने उन्हें घेर लिया और जबरन दूसरी जगह ले जाने का प्रयास किया। वह किसी तरह कार भगाकर निकले तो आरोपितों ने उनका पीछा किया। सुरक्षा के लिए उन्होंने कार पंजाब विश्वविद्यालय परिसर की ओर मोड़ दी, लेकिन पीछा कर रहे लोग वहां तक पहुंच गए। आरोप है कि इसी दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की कर मोबाइल और कार की चाबी छीन ली गई।

अनंत चौदस पर मंदिर परिसर में उमड़े श्रद्धालु, चार सौ से अधिक स्थानों पर लगे लंगर

जालंधर में राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने सिद्ध बाबा सोढल मंदिर में टेका माथा

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने सिद्ध बाबा सोढल मंदिर में नतमस्तक होकर देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं को अनंत चौदस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने गुरुद्वारा सोढल छावनी निहंग सिंघा में भी माथा टेका। राज्यपाल ने कहा कि श्री सिद्ध बाबा सोढल के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है, जिसके चलते हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। इस दौरान सोढल सुधार सभा के अध्यक्ष पंकज चड्ढा, पूर्व विधायक केडी भंडारी समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।



अनंत चौदस के अवसर पर सिद्ध बाबा सोढल मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर और आसपास के करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में उत्सव का माहौल रहा। चार सौ से अधिक स्थानों पर लंगर लगाए गए हैं, जबकि बाजारों में देर रात तक खरीदारी का दौर चलता रहा। मेला प्रबंधकों के अनुसार मुख्य दिन करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालु खेतड़ी अर्पित करने और चौदह रोट का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा निभाएंगे।

मेले में सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मंदिर के सामने पुलिस नियंत्रण कक्ष, निशुल्क चिकित्सा शिविर और नगर निगम का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। श्रद्धालुओं से बच्चों का हाथ थामकर रखने, कीमती सामान से बचने और झूलों की सुरक्षा जांचने की अपील की गई है। खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करने की सलाह भी दी गई है।

चंडीगढ़ की विरासत कुर्सियों की विदेशों में नीलामी पर उठे सवाल

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की विरासत से जुड़ा पियरे जेनरे का फर्नीचर एक बार फिर विदेशी नीलामी बाजार में पहुंच गया है। प्रशासनिक भवनों में इस्तेमाल की गई जेनरे की कुर्सियों की पेरिस और नीदरलैंड में नीलामी प्रस्तावित है। इसे लेकर अधिवक्ता और यूटी सलाहकार समिति के सदस्य अजय जग्गा ने विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और चंडीगढ़ प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पेरिस में 'आर्टक्यूरियल एक्स रिफ्लेक्शंस' नीलामी में पियरे जेनरे की वर्ष 1958 की 'चेयर वी टाइप केन सीट केन बैक' को लॉट नंबर 73 में रखा गया है। ठोस सागौन और बेंत से बनी इस कुर्सी की अनुमानित कीमत चार से छह हजार यूरो बताई गई है। जग्गा ने नीदरलैंड में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित नीलामी का भी उल्लेख किया है। इसमें पियरे जेनरे की दो एक्स-लेग आर्मचेयर को लॉट नंबर 28 के रूप में पेश किए जाने की जानकारी दी गई है।

चंडीगढ़ में 720 की जगह 783 बेड का भुगतान, ऑडिट ने पकड़ी अनियमितता

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के सरकारी अस्पतालों से बायोमेडिकल वेस्ट उठाने के भुगतान में अनियमितता सामने आई है। अस्पतालों में स्वीकृत बेड क्षमता 720 होने के बावजूद 783 बेड के हिसाब से भुगतान किया गया। इस तरह 63 अतिरिक्त बेड के लिए सरकारी राशि जारी हुई। ऑडिट रिपोर्ट में इस पर आपत्ति जताते हुए पिछले वर्षों में किए गए भुगतानों की भी जांच और अतिरिक्त राशि की वसूली की सिफारिश की गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने बायोमेडिकल वेस्ट के संग्रह और निस्तारण के लिए 29 सितंबर 2023 को मेसर्स एलायंस एन्वायरोकेयर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था। इसके तहत जीएमएसएच-16, सिविल अस्पताल मनीमाजरा, सिविल अस्पताल सेक्टर-22 और सिविल अस्पताल सेक्टर-45 से बायोमेडिकल वेस्ट उठाया जाना था। समझौते में प्रति बेड प्रतिदिन 16.12 रुपये का भुगतान तय किया गया था।



इसमें बारकोड प्रबंधन प्रणाली समेत अन्य संबंधित सेवाएं शामिल थीं। बाद के विस्तार के लिए हर वर्ष पांच प्रतिशत वृद्धि का प्रविधान भी रखा गया था।

अस्पताल के बेड से जुड़े अभिलेखों की जांच में सामने आया कि भुगतान 783 बेड के आधार पर किया गया, जबकि स्वीकृत क्षमता 720 बेड थी। संबंधित अवधि में लागू दर 16.93 रुपये प्रति बेड प्रतिदिन रही। इस हिसाब से 63 अतिरिक्त बेड के लिए प्रतिदिन 1,066.59 रुपये का भुगतान किया गया। 30 दिन में यह राशि करीब 31,998 रुपये और 365 दिन में करीब 3.89 लाख रुपये बनती है।

चंडीगढ़ के फैदां गांव में बैक्टीरिया से साफ होगा सीवेज, 300 परिवारों को मिलेगी राहत

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। फैदां गांव से गुजरने वाले गंदे नाले में अब विशेष बैक्टीरिया डालकर सीवेज को साफ करने की योजना है। चंडीगढ़ नगर निगम मुंबई की तर्ज पर 'इन-सीटू' अपशिष्ट जल शोधन तकनीक लागू करने जा रहा है। इससे गांव के करीब 300 परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सख्ती के बाद इन घरों पर सीवेज निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण कार्रवाई और मकान टूटने का खतरा बना हुआ था।

फैदां गांव के करीब 300 घरों का सीवेज सीधे खुले नाले में गिर रहा था। इसके समाधान के लिए ग्रामीणों के सामने सीवेज शोधन संयंत्र तक पाइपलाइन बिछाने या घरों में सोखता गड्ढा बनाने का विकल्प रखा गया था। दोनों व्यवस्थाओं पर अधिक खर्च होने के कारण ग्रामीण परेशान थे। अब नई तकनीक के जरिए नाले में ही सीवेज का शोधन किया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त अमित कुमार और मुख्य अभियंता संजय अरोड़ा ने मुंबई में इस तकनीक का अध्ययन करने के बाद इसके लिए निविदा प्रक्रिया तैयार की है। योजना के तहत नाले में विशेष सूक्ष्मजीवों का मिश्रण डाला जाएगा, जो पानी में मौजूद जैविक गंदगी और प्रदूषकों को कम करने में मदद करेंगे। इसके साथ नाले पर प्रवाह मापने के उपकरण, सीसीटीवी कैमरे और आंकड़ा दर्ज करने वाले उपकरण लगाए जाएंगे। पानी की गुणवत्ता की नियमित प्रयोगशाला जांच भी होगी।

निगम ने परियोजना के लिए 'काम दिखाओ, भुगतान पाओ' व्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया है। कंपनी को तभी भुगतान किया जाएगा, जब मौके पर तकनीक की प्रभावशीलता साबित होगी और पानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्धारित मानकों के अनुरूप मिलेगा।



फैदां नाले से प्रतिदिन करीब 50 से 70 एमएलडी सीवेज निकलता है। वर्तमान में जैविक ऑक्सीजन मांग का स्तर 150 से 200 मिलीग्राम और रासायनिक ऑक्सीजन मांग 300 से 400 मिलीग्राम तक है। निगम का लक्ष्य इन्हें क्रमश: 10 और 50 मिलीग्राम से नीचे लाना है। निलंबित ठोस पदार्थों का स्तर भी 20 मिलीग्राम से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। निगम के अनुसार सफल प्रयोग के बाद इस मॉडल को अन्य स्थानों पर भी अपनाया जा सकता है।

राजनीति कैप्टन की टिप्पणी से पंजाब में भाजपा-अकाली दल गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चा फिर तेज

कैप्टन अमरिंदर का भाजपा पर असंतोष, अकाली दल से गठबंधन की सलाह

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी में करीब चार साल रहने के बाद अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर असंतोष जताया है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें वास्तव में कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी कांग्रेस में लौटने की कोई योजना नहीं है और चुनाव लड़ने के उनके दिन लगभग खत्म हो चुके हैं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह सितंबर 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, जिसका बाद में भाजपा में विलय कर दिया गया। उन्होंने बताया कि भाजपा में शामिल होने का फैसला उस समय लिया गया जब कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके सामने सीमित राजनीतिक विकल्प थे। अब चार साल बाद उनका कहना है कि पार्टी में रहने के दौरान पंजाब से जुड़े मामलों में उनसे अपेक्षित स्तर पर सलाह नहीं ली गई।

उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर वरिष्ठ नेता से सलाह-मशविरा होने की स्वाभाविक अपेक्षा रहती है। खासकर पंजाब जैसे राज्य के संबंध में, जिसे उन्होंने करीब छह दशक से करीब से देखा है। कैप्टन ने कहा कि वह यह दावा नहीं करते कि पंजाब से जुड़े सभी सवालों के जवाब उनके पास हैं, लेकिन राज्य की राजनीति और परिस्थितियों को वह अच्छी तरह समझते हैं।

कांग्रेस में वापसी से किया इनकार : भाजपा में अपने भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर कैप्टन ने कहा कि उनके पास फिलहाल कोई दूसरा राजनीतिक विकल्प नहीं है। उन्होंने अकाली दल में जाने की संभावना से भी इनकार किया और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस उन्हें वापस लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को पहले अपने स्तर पर कई चीजें व्यवस्थित करनी होंगी।



84 वर्षीय कैप्टन ने स्पष्ट किया कि वह अब चुनावी राजनीति में सक्रिय उम्मीदवार के तौर पर सामने नहीं आएंगे। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-सी पार्टी किस स्थिति में होगी। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबले की संभावना पर भी चर्चा की।

भाजपा को अकाली दल से गठबंधन की सलाह : कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा पंजाब में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है तो उसे अपने पुराने सहयोगी अकाली दल के साथ गठबंधन पर विचार करना चाहिए। उनके अनुसार दोनों दल पहले भी मिलकर सरकार चला चुके हैं।हालांकि, भाजपा की ओर से पिछले महीने पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही गई थी और अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया गया था। ऐसे में कैप्टन की गठबंधन संबंधी टिप्पणी पार्टी के मौजूदा सार्वजनिक रुख से अलग है।

राज्य का दर्जा मांगना राष्ट्र-विरोधी नहीं -मुख्यमंत्री उमर

भाजपा से प्रस्ताव में एक भी राष्ट्र-विरोधी शब्द दिखाने की मुख्यमंत्री ने मांगी चुनौती

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में राजनीतिक टकराव देखने को मिला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जे की बहाली से संबंधित प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध पर जवाब देते हुए कहा कि इस मांग को राष्ट्र-विरोधी बताना उचित नहीं है। विधानसभा में हुए हंगामे के बाद पत्रकारों से बातचीत में उमर ने भाजपा को चुनौती दी कि वह प्रस्ताव में इस्तेमाल किए गए किसी एक ऐसे शब्द की ओर इशारा करे, जिसे राष्ट्र-विरोधी कहा जा सकता है।



स्टेटहुड प्रस्ताव पर बढ़ा विवाद

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को केंद्र सरकार के सामने रखना है। उनके अनुसार यह प्रस्ताव वर्ष 2000 में विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता संबंधी प्रस्ताव से अलग है। उमर ने कहा कि अगर भाजपा पहले पारित किसी प्रस्ताव को कमजोर करना चाहती है तो उसे अपना प्रस्ताव सदन में लाना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए।

स्वायत्तता के संदर्भ को लेकर भाजपा की आपत्ति : विधानसभा में प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा सदस्यों ने वर्ष 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव के संदर्भ को लेकर सवाल उठाए। भाजपा विधायकों ने पूछा कि करीब 26 वर्ष पुराने प्रस्ताव को मौजूदा राज्य का दर्जा बहाल करने से जुड़े प्रस्ताव के साथ क्यों जोड़ा गया है। भाजपा की ओर से यह सवाल भी उठाया गया कि उस समय जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य था, जबकि वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेश है।

इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद बढ़ गए। भाजपा सदस्यों ने सदन के वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। दूसरी ओर, नेशनल कान्फ्रेंस के सदस्यों ने भी अपने अधिकारों और राज्य के दर्जे की बहाली के समर्थन में नारे लगाए। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही पहले आधे घंटे के लिए स्थगित हुई और बाद में विरोध जारी रहने पर सदन सोमवार तक स्थगित कर दिया गया।

उमर ने भाजपा पर लगाया नाटक करने का आरोप : सदन में हुए विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर राजनीतिक प्रदर्शन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के दर्जे की बहाली का मुद्दा जम्मू-कश्मीर के लोगों से जुड़ा विषय है और इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रस्ताव में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है और इसे पहले पारित किए गए प्रस्तावों से अलग समझा जाना चाहिए।

उमर ने कहा कि भाजपा यदि इस प्रस्ताव की भाषा या उद्देश्य पर आपत्ति रखती है तो उसे सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चर्चा को रोकने के बजाय प्रस्ताव के प्रावधानों पर बहस होनी चाहिए थी। उनकी यह टिप्पणी विधानसभा में हुए हंगामे के बाद सामने आई।

राज्य का दर्जा बहाली बना मुख्य मुद्दा : जम्मू-कश्मीर विधानसभा के मौजूदा सत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा प्रमुख राजनीतिक विषयों में शामिल है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले भी सार्वजनिक रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठा चुके हैं। 17 सितंबर को भी उन्होंने प्रधानमंत्री से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह दोहराया था।

वहीं, विधानसभा में भाजपा और नेशनल कान्फ्रेंस के बीच मतभेद केवल राज्य के दर्जे तक सीमित नहीं रहे हैं। मौजूदा सत्र में दोनों पक्षों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विरोध और नारेबाजी के मामले सामने आए हैं। राज्य के दर्जे को लेकर शुक्रवार का विवाद पुराने स्वायत्तता प्रस्ताव के संदर्भ के कारण और बढ़ गया।

विधानसभा में तंबाकू नहीं, हैप्पीडेंट चबा रहा था; अल्ताफ कालू ने दी सफाई

वायरल वीडियो पर विधायक ने दी सफाई, विधानसभा में कैमरों पर भी उठाए सवाल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। नेशनल कान्फ्रेंस के विधायक अल्ताफ कालू ने विधानसभा के भीतर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद स्पष्टीकरण दिया है। वीडियो में उन्हें पार्टी के सहयोगी अब्दुल मजीद लार्मी से बातचीत के दौरान मुंह से कुछ निकालते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर यह दावा किया गया कि वह विधानसभा में तंबाकू का सेवन कर रहे थे।



अल्ताफ कालू ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वह तंबाकू या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर रहे थे, बल्कि हैप्पीडेंट निकाल रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पास चबाने वाली यह चीज थी, जिसे उन्होंने मुंह से निकालने की कोशिश की। उनका कहना था कि वीडियो के आधार पर उनके बारे में गलत धारणा बनाई गई।

विधायक ने वीडियो के प्रसारित होने और उसके साथ किए जा रहे दावों पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि वीडियो का संदर्भ जाने बिना उसके आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले को विधानसभा की कार्यवाही से जोड़ते हुए सदन में लाइव वीडियो कैमरों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया।

कालू ने मांग की कि विधानसभा परिसर में लगाए गए लाइव वीडियो कैमरों की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सदन के भीतर केवल एक अधिकृत कैमरे से ही कार्यवाही रिकॉर्ड की जाए, ताकि अलग-अलग कोणों से बने वीडियो के आधार पर किसी सदस्य के बारे में भ्रामक दावे प्रसारित न हों।

अल्ताफ कालू ने वायरल वीडियो विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर को दिखाने की कोशिश भी की। हालांकि, अध्यक्ष ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बाद कालू ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वीडियो में दिखाई दे रही गतिविधि को गलत तरीके से पेश किया गया है।

न्यूज ब्रीफ

मरीजों की बढ़ती संख्या से सोपोर अस्पताल पर बढ़ा स्वास्थ्य सेवाओं का दबाव

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों के उपजिला अस्पतालों में हर महीने कुल 2,03,584 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। विधायक इरशाद रसूल के सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी।सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन अस्पतालों में सोपोर का उपजिला अस्पताल सबसे अधिक व्यस्त है। यहां एक महीने में 40,364 मरीज पहुंचे। इसके बाद कुपवाड़ा में 33,000 और पट्टन में 25,604 मरीज दर्ज किए गए। बारामूला जिले के सात उपजिला अस्पतालों में कुल 1,22,561 मरीज पहुंचे। सोपोर और पट्टन के अलावा टंगमर्ग में 20,839, क्रेरी में 15,105, रोहामा में 7,384, उरी में 7,364 और चंदूसा में 5,901 मरीज दर्ज किए गए। कुपवाड़ा जिले के आठ उपजिला अस्पतालों में कुल 78,700 मरीज पहुंचे। इनमें कुपवाड़ा के बाद टंगदार में 11,300, सोगम में 10,500, क्रालपोरा में 9,500, लंगेट में 6,000, क्रालगुंड में 3,900, विलगम में 3,000 और जचलदारा में 1,500 मरीज आए। बांदीपोरा जिले के उपजिला अस्पताल गुरेज में एक महीने के दौरान 2,323 मरीजों ने उपचार कराया। आंकड़ों से सोपोर में स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक मरीजों के दबाव का पता चलता है।

सेना प्रमुख ने करनाह में पूर्व सैनिकों से मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा

भारतेंदु संवाददाता, कुपवाड़ा। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करनाह क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र में पूर्व सैनिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी जरूरतों की जानकारी ली।दौरे के दौरान सेना प्रमुख ने टंगधार स्थित अग्रिम शल्य चिकित्सा केंद्र में चल रहे 'ऑपरेशन दृष्टि' के तहत आयोजित सात दिवसीय मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का भी जायजा लिया। यह अभियान दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और पूर्व सैनिकों को आंखों की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। सेना के अनुसार, शिविर चिनार कोर की देखरेख और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच शिविरों के माध्यम से मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए करीब 400 मरीजों की पहचान की गई है। सेना प्रमुख ने अग्रिम क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं और अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पूर्व सैनिकों से बातचीत के दौरान उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को सुना और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।

स्टेटहुड प्रस्ताव पर हंगामा, भाजपा विधायक रंधावा सदन से बाहर

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश किए गए राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को लेकर भारी हंगामा हुआ। विरोध के बीच भाजपा विधायक विक्रम रंधावा को सदन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद लगातार जारी नारेबाजी और हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। 30 मिनट के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो भाजपा सदस्यों ने राज्य के दर्जे के प्रस्ताव में वर्ष 2000 के स्वायत्तता

स्टेटहुड पर बहस को तैयार, 370-स्वायत्तता पर भाजपा का विरोध

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन अनुच्छेद 370 और वर्ष 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव पर चर्चा स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव में स्वायत्तता प्रस्ताव का संदर्भ शामिल किए जाने पर सवाल उठाया। शर्मा ने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस से अनुच्छेद 370 और स्वायत्तता के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राज्य के दर्जे के मुद्दे के जरिए अपनी कमियों से ध्यान भटका रही है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और सरकार जब तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करतीं, भाजपा प्रस्ताव का विरोध जारी रखेगी।

उरी में जैतून सहित गैर-फलदार फसलों की खेती पर होगा व्यवहार्यता अध्ययन



क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त प्रजातियों का होगा चयन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार बारामूला जिले के उरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती की संभावनाएं तलाशेगी। इसके तहत विशेष रूप से जैतून और अन्य उपयुक्त गैर-फलदार प्रजातियों की खेती को बढ़ावा देने की संभावना का आकलन किया जाएगा। कृषि उत्पादन विभाग ने शुक्रवार को विधानसभा में उरी के विधायक सज्जाद शफी के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

सरकार के अनुसार, इस संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर शोध और व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाएगा। यह अध्ययन शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर के माध्यम से किया जाएगा। इसका उद्देश्य उरी में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती की संभावनाओं और व्यवहारिकता का मूल्यांकन करना है।

सरकार ने बताया कि अध्ययन के दौरान क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, मौजूदा कृषि व्यवस्था और बागवानी की सीमित संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसके आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि किन फसलों और प्रजातियों की खेती यहां किसानों के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोगी हो सकती है।

अध्ययन में उपयुक्त पाए जाने वाले क्षेत्रों में प्रदर्शन खेती की संभावनाओं की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा पौधशालाओं के विकास और कृषि उत्पादों के लिए मूल्यवर्धन तथा विपणन से जुड़ी संभावनाओं का भी आकलन किया जाएगा।

गरीब परिवारों को सालाना छह मुफ्त गैस सिलिंडर देगी सरकार

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले परिवारों को साल में छह मुफ्त एलपीजी सिलिंडर देने की घोषणा की है। प्रदेश में एएवाई के तहत बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद परिवार शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एक जनवरी 2025 तक जम्मू-कश्मीर में कुल 8,79,112 एएवाई लाभार्थी दर्ज किए गए थे। इनमें जम्मू संभाग के 2,74,695 और कश्मीर संभाग के 6,04,417 लाभार्थी शामिल हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि जम्मू की तुलना में कश्मीर संभाग में एएवाई लाभार्थियों की संख्या अधिक है।

जम्मू संभाग में राजौरी जिले में सबसे अधिक 40,063 एएवाई लाभार्थी दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पुंछ में 39,917, डोडा में 34,532, जम्मू में 32,104, रियासी में 30,000, कठुआ में 26,477, किश्तवाड़ में 19,782, उधमपुर में 19,482 और रामबन में 17,047 लाभार्थी हैं। सांबा जिले में 7,445 एएवाई लाभार्थी दर्ज किए गए हैं।



कश्मीर संभाग में कुपवाड़ा 1,20,671 एएवाई लाभार्थियों के साथ सबसे आगे है। बारामूला में 1,09,815, अनंतनाग में 79,945, बडगाम में 68,785 और पुलवामा में 59,063 लाभार्थी दर्ज हैं। इसके अलावा बांदीपोरा में 40,307, कुलगाम में 48,619, गांदरबल में 22,613, श्रीनगर में 26,450 और शोपियां में 28,149 एएवाई लाभार्थी हैं। कुपवाड़ा के कुल लाभार्थियों में करनाह के 14,969, त्रेहगाम के 9,376, कुपवाड़ा के 25,819, लोलाब के 18,995, हंदवाड़ा के 34,320 और लंगेट के 17,192 लाभार्थी शामिल हैं। वहीं बारामूला जिले के 1,09,815 लाभार्थियों में उड़ी के 37,787 और सोपोर के 14,164 लाभार्थी हैं।

विजयपुर में जख रोड पर 26 वर्षीय युवक का मिला शव, जांच शुरू

भारतेंदु संवाददाता, सांबा। सांबा जिले के विजयपुर क्षेत्र में शुक्रवार को जख रोड पर एक 26 वर्षीय युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा देखा। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। मामले की जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की।

डबुज काका का रहने वाला था युवक : पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान पवन के रूप में हुई है। उसकी उम्र 26 वर्ष थी और वह सांबा जिले के जख क्षेत्र के डबुज काका का रहने वाला था। पहचान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया।

जांच में जुटी पुलिस : पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को चिकित्सकीय-कानूनी औपचारिकताओं के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), विजयपुर भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंपा जाएगा। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

जम्मू-कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल भर्ती नियम बदले, एसपीओ को मिला 15 प्रतिशत कोटा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती को लेकर सरकार ने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत कांस्टेबल के कुल पदों में 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती, 15 प्रतिशत पद विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) और पांच प्रतिशत पद सेवा में कार्यरत फालोअर्स की पदोन्नति से भरे जाएंगे। इससे लंबे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे एसपीओ और फालोअर्स को कांस्टेबल बनने का अवसर मिलेगा।



गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम, 1960 में नया नियम 174-ए जोड़ा है। यह संशोधन पुलिस अधिनियम, 1983 की धारा 43 की उपधारा (3) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। नए नियम के अनुसार कांस्टेबल पदों की भर्ती में निर्धारित अनुपात के आधार पर सीधी भर्ती और विभागीय अवसर उपलब्ध होंगे।

कुल कांस्टेबल पदों में 15 प्रतिशत पद उन एसपीओ के लिए आरक्षित होंगे, जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी की हो। संबंधित उम्मीदवार के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मानक होना जरूरी होगा। इसके अलावा उन्हें निर्धारित शारीरिक मानक परीक्षण भी उत्तीर्ण करना होगा। काउंटर इंसरजेंसी अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एसपीओ के लिए भी पात्रता की शर्त रखी गई है। कांस्टेबल के पांच प्रतिशत पद इन-सर्विस फालोअर्स की पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की कम से कम पांच वर्ष की सेवा, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मानक जरूरी होंगे। उन्हें भी निर्धारित शारीरिक मानक परीक्षण पास करना होगा।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नए प्रावधान जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम, 1960 में मौजूद किसी असंगत प्रावधान के बावजूद प्रभावी होंगे। नए नियमों से वर्षों से पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे एसपीओ और फालोअर्स में स्थायी नियुक्ति की उम्मीद बढ़ी है।

परियोजनाओं में देरी और बढ़ती लागत पर विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा

निर्माण सामग्री की कमी पर विधानसभा में उठेगा मुद्दा, 13 विधायकों ने मांगी चर्चा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में निर्माण सामग्री की उपलब्धता में आ रही दिक्कतों का असर विकास परियोजनाओं पर पड़ रहा है। रेत, बजरी, पत्थर और कंक्रीट जैसी आवश्यक सामग्री की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति नहीं होने से सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल तथा जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कई परियोजनाओं में काम की गति धीमी होने के साथ उनकी लागत बढ़ने की आशंका भी सामने आई है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के 13 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से सदन में 45 मिनट की चर्चा कराने की मांग की है। विधायकों ने सदन में चर्चा के दौरान सरकार से निर्माण सामग्री की कमी के कारणों की जानकारी देने की मांग की है। उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि प्रदेश में रेत, बजरी, पत्थर और अन्य आवश्यक सामग्री की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं।



सड़क और पुल समेत कई परियोजनाओं पर संकट के बादल।

निर्माण सामग्री की अनिश्चित आपूर्ति से बढ़ी चिंता

विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजे पत्र में कहा कि प्रदेश में आवश्यक निर्माण सामग्री की उपलब्धता लगातार अनिश्चित बनी हुई है। इसका सीधा प्रभाव विभिन्न सरकारी और विकास परियोजनाओं पर पड़ रहा है। समय पर रेत, बजरी और अन्य सामग्री नहीं मिलने से निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पा रहे हैं। इससे परियोजनाओं की लागत बढ़ने के साथ संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों के सामने भी चुनौती पैदा हो रही है।

13 विधायकों ने पत्र पर किए हस्ताक्षर : विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र पर जावेद हसन बेग, जस्टिस हसनैन मसूदी, निजामुद्दीन भट, हिलाल अकबर लोन, आरएस पठानिया, इरफान हफीज लोन, सैफ-उद-दीन भट, जावेद अहमद मीरचल, डॉ. सज्जाद शफी, डॉ. मोहम्मद शफी, वहीद-उर-रहमान पर्रा, फारूक अहमद शाह और नियाज अहमद ने हस्ताक्षर किए हैं।

पत्रकार कल्याण योजना के लाभ के लिए नहीं आया जम्मू-कश्मीर से कोई आवेदन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पत्रकार कल्याण योजना-2023 के तहत अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विधायक रणबीर सिंह पठानिया के प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी।

सरकार के अनुसार पत्रकार कल्याण योजना केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक अप्रैल 2023 से देशभर में लागू है। इसके तहत मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ स्वतंत्र पत्रकारों को भी अत्यधिक आर्थिक संकट की स्थिति में एकमुश्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पांच लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में भी पांच लाख रुपये तक और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना या बीमा के दायरे में नहीं आने वाली गंभीर बीमारी के उपचार के लिए तीन लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है।

सरकार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पात्र पत्रकार प्रेस सूचना ब्यूरो या सूचना विभाग के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र मामलों को आवश्यक सिफारिश के साथ



◆ योजना में गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे पत्रकारों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान

केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। हालांकि, पिछले पांच वित्तीय वर्षों में योजना के तहत जम्मू-कश्मीर से कोई आवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ।

गैर-मान्यता प्राप्त और डिजिटल मीडिया पत्रकारों को लाभ देने के संबंध में सरकार ने कहा कि योजना में मान्यता प्राप्त, गैर-मान्यता प्राप्त और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए सहायता का प्रावधान है। वहीं जम्मू-कश्मीर में पत्रकारों के लिए फिलहाल कोई अलग समर्पित कल्याण कोष नहीं है।

शोपियां दारुल उलूम को दोबारा खोलने का अदालत ने दिया आदेश

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। शोपियां स्थित बंद किए गए दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को अदालत ने दोबारा खोलने का आदेश दिया है। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश शोपियां महमूद अहमद चौधरी ने अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतिम निर्णय आने तक संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी है। संस्थान की ओर से अधिवक्ता एसएम इकबाल ने अदालत को बताया कि यहां करीब 1200 विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनमें लगभग 400 छात्रावास में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य मामला अभी विचाराधीन है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई को अनिश्चित अवधि तक प्रभावित नहीं किया जा सकता। संस्थान ने बंद रहने के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचने और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होने की बात भी अदालत के समक्ष रखी। अदालत ने सरकार की ओर से प्रस्तुत सामग्री पर विचार करते हुए कहा कि मौजूदा स्तर पर पूरे संस्थान को बंद रखने के लिए सामग्री पर्याप्त नहीं है।

335 डॉक्टरों को नियुक्ति आदेश, 1567 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के हजारों पद खाली

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को लेकर भाजपा और सत्तापक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। प्रस्ताव पर विवाद के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वह प्रस्ताव में इस्तेमाल किसी एक भी राष्ट्र-विरोधी शब्द की ओर इशारा करे। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करना राष्ट्र-विरोधी कृत्य नहीं है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करना है। उन्होंने इसे पहले पारित किए गए स्वायत्तता संबंधी प्रस्ताव से अलग बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भाजपा पहले पारित प्रस्तावों को कमजोर करना चाहती है तो वह अपना प्रस्ताव सदन में लेकर आए।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा सदस्यों ने 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव के संदर्भ को लेकर आपत्ति जताई। भाजपा विधायक सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही पहले आधे घंटे के लिए स्थगित की। बाद में स्थिति सामान्य नहीं



होने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई।

मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर भाजपा के विरोध पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है और इसका मकसद केवल पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग रखना है।

उमर ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट की हैं। इससे पहले भी वह केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहरा चुके हैं।

सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा में कांग्रेस का विरोध

◆ बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, अध्यक्ष ने दी कार्रवाई की चेतावनी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने कुछ देर विरोध प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक बैनर लेकर सामने आ गए। बैनरों पर 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, वोट बचाएं, लोकतंत्र बचाएं' लिखा था। विधायकों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की।

कांग्रेस विधायकों निजामुद्दीन भट, इरफान हाफिज लोन और इफ्तिखार ने सदन के भीतर बैनर प्रदर्शित किए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने आपत्ति जताई। उन्होंने विधायकों से सवाल किया कि उन्हें सदन के अंदर बैनर लाने की अनुमति किसने दी। अध्यक्ष ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से बैनर बंद करने को कहा।

अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग विधानसभा के नियंत्रण में नहीं है और उन्होंने सदन के भीतर बैनर लाने की अनुमति नहीं दी है। अध्यक्ष ने कहा कि उस समय प्रश्नकाल चल रहा है और सदस्यों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई करने से पहले वे अपनी सीटों पर वापस चले जाएं। इसके बाद कुछ देर तक सदन में नारेबाजी और विरोध का माहौल बना रहा।

कांग्रेस विधायकों का यह प्रदर्शन सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद हुआ। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई।

परमात्मा की लीला में कठपुतली समान है जीव, कर्म ही बनते हैं बंधन का कारण





डॉ पी सी कौंडल
वरिष्ठ साहित्यकार जिला मण्डी
हिमाचल प्रदेश

मनुष्य देह के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस पांच छः फुट मिट्टी के पुतले को दुनियां भर में घुमाती गिराती जा रही है? वह शक्ति है आत्मा जिसे न कोई आंखों से देख सकता है और न बांध ही सकता है। वह जब तक इस देह में है, तब तक यह देह अथवा शरीर जीवित है। जब वह शक्ति अथवा आत्मा इस देह से निकल जाएगी यह मनुष्य शरीर निर्जीव हो जाएगा अर्थात मृत हो जाएगा। तब इस देह में प्राण नहीं रह जाते। फिर भले ही इस मृत शरीर को आग में जला दो, मिट्टी में दबा दो, नदी नालों में फेंक दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता।

वास्तव में यह आत्मा जब से अपने निज घर अर्थात परमात्मा से अलग ही है तब से इसने मन और देह का साथ ले लिया है, जिस कारण इसका दोबारा अपने निज घर अथवा परमात्मा के पास जाने का रास्ता बंद हो गया है। यह आत्मा परमात्मा की अंश है। यह कमजोर हो कर मन के चंगुल में फंस चुकी है और अपने निज घर की याद ही भूल चुकी है। यह आत्मा इस दुख भरे संसार में दुख भरी ज़िन्दगी बिताने को मजबूर हो चुकी है। इस संसार को उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा ने बनाया है और इस संसार को देखने के दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण यह है इस संसार को परमात्मा के नजरिए से देखना अर्थात ऊपर से नीचे की ओर देखना और दूसरा दृष्टिकोण है मनुष्य के नजरिए से देखना अर्थात नीचे से ऊपर की ओर देखना।

ऊपर से यही दिखाई देता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, वही इस दुनियां का एक मात्र रचनाकार और पालनहार है और जीव आत्मा एक कठपुतली है जो धागा खींचने वाले अर्थात उस परमात्मा के इशारे पर चल, फिर और नाच कूद रही है। यही परमात्मा की लीला है। सभी पूर्ण संत सतगुरु ऊपर से देखते हैं तो वे इस संसार का परमात्मा की लीला के रूप में वर्णन करते हैं। वे हर स्थान पर परमात्मा का ही करिश्मा देखते हैं और उसी के नूर को कार्य करते हुए देखते हैं।

अगर नीचे से इन्सान के नजरिए से देखा जाए तो हमें एकता की जगह अनेकता दिखाई देती है। हरेक जीव लग्न से कार्य करता जा रहा है और जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में वह आता जाता है, उन्हें भी प्रभावित करता जाता है। जब जीव अपने आप को ही कर्ता समझता है तब वह अपने कर्मों का जिम्मेवार और उन कर्मों के फल का भागीदार बन जाता है। सभी प्रकार के कर्म मन और अंत:करण पर अंकित हो जाते हैं जिससे राग और द्वेष पैदा होते रहते हैं, जिनके कारण जीव पिछले जन्मों के अनुसार स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों में आवागमन के चक्कर में बंध जाते हैं।

कर्म तीन प्रकार के हैं; क्रियामान, प्रारब्ध और संचित। कोई भी कर्म अगर किसी इच्छा से किया जाता है तो वही इच्छा बन्धन का कारण बन जाती है। मन चेतन या अर्ध चेतनावस्था में भी कुछ न कुछ करता ही रहता है। किसी भी कर्म का कोई प्रतिफल न हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसी दास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस किन तास फल चाखा अर्थात जो जैसा कर्म करता है, उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है।

केवल संतों महात्माओं की शरण ही कर्मों से छुटकारा दिला सकती है। संत जन स्वयं कर्म रहित होते हैं। कर्म उन्हें नहीं बांध सकते क्योंकि उनकी सूरत दसवें द्वार में होती है जो तीनों मन पिंडी, अड़ी और ब्रह्माण्डी और शरीर की सीमाओं से ऊपर है। अत: वे ही जीव को कर्मों से छुटकारा पाने का रास्ता बताते हैं। संत सतगुरु कहते हैं कि जीव अपने आप को सतगुरु का सेवक समझ कर किसी भी नए कार्य को सतगुरु के नाम पर करता जाए। इस भाव से किए गए नए कर्म बंधन का कारण नहीं हो सकते। प्रारब्ध कर्म ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक खत्म हो जाते हैं और संत जैसा उचित समझते हैं, संचित कर्मों का कुछ हिस्सा अपने ऊपर ले लेते हैं और कुछ हिस्सा जीव से भुगतवा लेते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

बदलती जीवनशैली और गलत खानपान से युवाओं में बढ़ रहा हृदय रोग का खतरा





मुकेश विग
किसान निवास, सोलन

आज के समय में हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं और यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। यह समस्या अचानक नहीं बढ़ी, बल्कि हमारी बदलती जीवनशैली, गलत खानपान और बढ़ते तनाव का परिणाम है। पहले के समय में लोग सादा और पौष्टिक भोजन करते थे, नियमित शारीरिक श्रम करते थे और प्रकृति के अधिक निकट रहते थे। यही कारण था कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां कम देखने को मिलती थीं। आज इसके विपरीत, आरामदायक जीवनशैली और फास्ट फूड की आदतों ने दिल को कमजोर बना दिया है।

हमारे दैनिक आहार में नमक, चीनी और वसा की मात्रा अत्यधिक बढ़ चुकी है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के अनुसार, अधिक सोडियम का सेवन, फलों और सब्जियों की कमी, तथा साबुत अनाज से दूरी हृदय रोगों के प्रमुख कारण हैं। ज्यादा नमक खाने से उच्च रक्तचाप बढ़ता है, जो दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डालता है। धीरे-धीरे यह स्थिति दिल की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है और गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है।

हमारा सामान्य हार्ट रेट 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट के बीच होना चाहिए। यदि यह 60 से कम हो जाए तो ब्रैडीकार्डिया और यदि 100 से अधिक हो जाए तो टैकीकार्डिया कहा जाता है। ये दोनों स्थितियां संकेत देती हैं कि दिल सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है और समय रहते ध्यान देना आवश्यक है।

आजकल के युवाओं और बच्चों में भी जंक फूड का चलन बहुत बढ़ गया है। चिप्स, नमकीन, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड में अत्यधिक नमक, ट्रांस फैट और कृत्रिम पदार्थ होते हैं, जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक हैं। इनसे मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर ऊंचा होता है और धमनियों में रुकावट आने लगती है। इसके विपरीत, फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जीवनशैली में सुधार ही हृदय रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। नियमित व्यायाम, रोजाना कम से कम 30-40 मिनट पैदल चलना, साइकिल चलाना और सीढ़ियों का उपयोग करना दिल को मजबूत बनाता है। लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहना भी हानिकारक है, इसलिए बीच-बीच में सि, य रहना जरूरी है। इसके साथ ही पर्याप्त नींद और मानसिक तनाव को नियंत्रित करना भी दिल के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

आज साइलेंट हार्ट अटैक के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें व्यक्ति को पहले से कोई स्पष्ट लक्षण महसूस नहीं होते। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी हो गई है। ईसीजी, ईकोकार्डियोग्राफी और रू जैसे परीक्षण दिल की स्थिति का सही आकलन करने में मदद करते हैं। यदि कभी सीने में दर्द, भारीपन, घबराहट या सांस लेने में परेशानी हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।

यह भी समझना जरूरी है कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जैसे किसी मशीन में खराब या गंदा ईंधन डालने से वह जल्दी खराब हो जाती है, उसी प्रकार गलत खानपान और अनियमित दिनचर्या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है।

बहरहाल, स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र संतुलन में छिपा है—संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच। यदि हम समय रहते अपनी आदतों में सुधार कर लें, तो न केवल हृदय रोगों से बच सकते हैं, बल्कि एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

अंकों की दौड़ में संवेदना न छूटे

आईआईटी बॉम्बे में 22 वर्षीय छात्र साहिल वाकोड़े की मौत ने देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा किया है, जिससे बचना संभव नहीं है। एक प्रतिभाशाली युवा की जिंदगी का इस तरह असमय समाप्त हो जाना केवल उसके परिवार की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के लिए भी गंभीर चेतावनी है, जिसमें सफलता को अक्सर अंकों, ग्रेड, परीक्षा परिणाम और भविष्य के रोजगार के पैमाने से मापा जाता है। इस घटना की निष्पक्ष जांच और उसके तथ्यों के सामने आने की प्रतीक्षा जरूरी है, लेकिन इससे जुड़े व्यापक सवालों पर चर्चा अभी से होनी चाहिए।

आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश स्वयं एक कठिन और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बाद मिलता है। देशभर के लाखों विद्यार्थी सीमित सीटों के लिए तैयारी करते हैं और उनमें से कुछ ही विद्यार्थी इन संस्थानों तक पहुंच पाते हैं। प्रवेश के बाद भी चुनौती समाप्त नहीं होती। कठिन पाठ्यक्रम, लगातार परीक्षाएं, असाइनमेंट, परियोजनाएं, ग्रेड, उपस्थिति और भविष्य के करियर की चिंता विद्यार्थियों पर लगातार दबाव बनाए रखती है। एक परीक्षा में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाना या किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना कुछ विद्यार्थियों के लिए असामान्य रूप से भारी पड़ सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि परीक्षा की शुचिता या संस्थागत अनुशासन से समझौता किया जाए। शैक्षणिक ईमानदारी किसी भी शिक्षण संस्थान की बुनियादी आवश्यकता है। नकल, अनुचित साधनों या नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अनुशासन और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही आवश्यक है। किसी विद्यार्थी से गलती हो सकती है, वह तनाव में हो सकता है या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसे केवल दंडित करने के बजाय अपनी बात रखने और सुधार का अवसर देना भी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए।

शिक्षा व्यवस्था को यह समझना होगा कि विद्यार्थी केवल रोल नंबर, अंक या ग्रेड नहीं हैं। उनके पीछे परिवार, उम्मीदें, सपने और व्यक्तिगत संघर्ष होते हैं। इसलिए परीक्षा प्रणाली के साथ मानसिक और भावनात्मक सहायता की व्यवस्था को भी संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को नियमित मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध हो, प्रशिक्षित परामर्शदाता पर्याप्त संख्या में हों और संकट की स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके, इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रावास स्तर पर भी ऐसा वातावरण बनाया जाना जरूरी है, जहां विद्यार्थी बिना किसी भय या संकोच के अपनी परेशानी साझा कर सकें।

शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कई बार किसी विद्यार्थी के व्यवहार में अचानक बदलाव, पढ़ाई में गिरावट, सामाजिक दूरी या लगातार तनाव के संकेत दिखाई दे सकते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए शिक्षकों और छात्रावास से जुड़े कर्मचारियों को संवेदनशील संवाद का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ बातचीत केवल अंक और अनुशासन तक सीमित न हो, बल्कि उनकी कठिनाइयों को सुनने की व्यवस्था भी हो।

इस घटना का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसे केवल राजनीति, संस्थागत विवाद या जातिगत चश्मे से देखना उचित नहीं होगा। परिजनों की ओर से लगाए गए आरोप गंभीर हैं और उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही, अनुचित दबाव, भेदभाव या गलत व्यवहार सामने आता है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी एक पक्ष को दोषी ठहराना भी न्यायसंगत नहीं होगा। आरोप और तथ्य में अंतर बनाए रखना आवश्यक है। राजनीतिक बयानबाजी या जातिगत विमर्श यदि मूल घटना और उसके वास्तविक कारणों पर पर्दा डाल दें तो इससे छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के सुधार का उद्देश्य कमजोर होगा।

आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थानों से केवल उत्कृष्ट इंजीनियर, वैज्ञानिक और पेशेवर तैयार करने की अपेक्षा नहीं है। उनसे ऐसा शैक्षणिक वातावरण बनाने की भी अपेक्षा है, जहां उत्कृष्टता की दौड़ में मानवीय संवेदना पीछे न छूटे। प्रतिस्पर्धा शिक्षा का हिस्सा हो सकती है, लेकिन लगातार दबाव को सामान्य मान लेना उचित नहीं है। विद्यार्थी को असफल होने, गलती करने और दोबारा प्रयास करने का अवसर मिलना चाहिए।

उच्च शिक्षा संस्थानों में शिकायत निवारण व्यवस्था को भी मजबूत करने की जरूरत है। विद्यार्थियों को यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा, अनुशासन, शिक्षक, छात्रावास या किसी अन्य समस्या की स्थिति में वे किस अधिकारी या समिति से संपर्क कर सकते हैं। शिकायत करने वाले विद्यार्थी को प्रतिशोध या सामाजिक दबाव का भय न हो, इसके लिए गोपनीय और निष्पक्ष व्यवस्था जरूरी है। संकट के समय चौबीसों घंटे उपलब्ध सहायता तंत्र भी बड़े संस्थानों में उपयोगी हो सकता है।

साहिल वाकोड़े की मौत की जांच अपने निष्कर्ष तक पहुंचे, तथ्य सामने आएं और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो। साथ ही निर्दोष लोगों को बिना प्रमाण आरोपों का सामना न करना पड़े। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी घटनाओं से शिक्षा व्यवस्था सीख ले।

- शिवांश धाकड़

मैं तेरे शहर का परिंदा हूं...

डॉ. अशोक प्यारे लाल चौबे

मैं तेरे शहर का परिंदा हूं,
तालीम न दे, उड़ने की मुझे,
अपनी उड़ान से मंजिल पा जाता हूं।
कभी तेरी मुंडेर पर बैठता हूं,
कभी किसी की मुंडेर पर ठहरता हूं, कभी पेड़ की डाल पर अपना घर बनाता हूं।
खुले आसमान को अपना साथी मानता हूं, हवाओं से बातें करता हूं,
बादलों के संग सपने बुनता हूं।
पिंजरे में कैद नहीं रह सकता, मेरी सांसों में आजादी बसी है।
मेरे पंखों को किसी सहारे की जरूरत नहीं,
मैं गिरकर भी उड़ना जानता हूं।
रास्ते कठिन हों तो क्या,
हौसले मेरे आसमान से बड़े हैं।
हर रोज तेरी छत पर आता हूं, शायद तेरी खिड़की से कोई सपना झांकता मिले।
तेरे शहर की गलियों में
मैंने मौसम बदलते देखे हैं, लोगों को आते-जाते देखा है, मगर अपनी उड़ान को कभी बदलते नहीं देखा।
आखिर परिंदों के भी शौक होते हैं, कभी पेड़ बदलते हैं, कभी छत बदलते हैं।
मगर मंजिल वही रहती है—
जहां खुला आसमान मिले, जहां पंखों पर कोई पहरा न हो, जहां उड़ने की आजादी हो।
मैं तेरे शहर का परिंदा हूं, मुझे कैद मत करना,
मेरी उड़ान को सीमाओं में मत बांधना।
मैं जहां भी जाऊंगा,
अपने पंखों में तेरे शहर की याद लिए जाऊंगा।

एकल परिवार और सामाजिक माध्यमों के बढ़ते प्रभाव ने नई पीढ़ी से छीने संस्कार और सामाजिक सरोकार





सुनीता गुप्ता कपूर
प्रवक्ता इतिहास, रा.व.मा.पा.
(बाल) मंडी

भारतवर्ष प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध संस्कृति, उच्च नैतिक मूल्यों और गौरवशाली परंपराओं के लिए विश्वभर में विख्यात रहा है। यही तत्व हमारे समाज की आत्मा हैं, जो उसे विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरता है कि 'समाज' क्या है?

समाज मात्र व्यक्तियों का समूह नहीं, अपितु एक सुव्यवस्थित संरचना है, जिसमें विभिन्न लोग एक साझा भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृति, परंपराओं और व्यवहारों के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। यह सामाजिक संबंधों, पारस्परिक क्रियाओं तथा विविध संस्थाओं का जटिल तंत्र है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सहयोग, सुरक्षा और सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परस्पर आश्रित रहता है।

समाज वह मंच है जहां भाईचारा, सम्मान, सुरक्षा और सह-अस्तित्व का भाव विकसित होता है। इसी समाज में हमारी संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रहती हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी उनका हस्तांतरण होता है। भाषा, त्योहार, पारंपरिक चिकित्सा, हस्तशिल्प और खानपान जैसी धरोहरें इसी माध्यम से जीवित रहती हैं। इस हस्तांतरण में 'परिवार' की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परिवार ही वह प्रथम पाठशाला है, जहां बालक अपने संस्कार, व्यवहार और मूल्यों को आत्मसात करता है। इसके पश्चात विद्यालय और महाविद्यालय इन गुणों को और अधिक परिष्कृत करते हैं।

वर्तमान युग तकनीक का युग है, जिसने ज्ञानार्जन के नए द्वार खोले हैं। इसके माध्यम से हम अपनी प्राचीन परंपराओं और ज्ञान को पुन: समझ सकते हैं। समाज के भी अनेक स्वरूप हैं-परंपरागत समाज, आधुनिक समाज, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज। परंपरागत समाज में रीति-रिवाजों का कठोर पालन होता है, जबकि आधुनिक समाज तर्क और विज्ञान को प्राथमिकता देता है। ग्रामीण समाज सरलता और कृषि पर आधारित होता है, वहीं नगरीय समाज विविध व्यवसायों और तीव्र गति वाले जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। समाज हमें जीवन जीने की कला सिखाता है-बोलना, चलना, व्यवहार करना और सह-अस्तित्व का महत्व समझाता है। यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु इसके सुचारु संचालन हेतु नियमों का पालन आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, वर्तमान समय में इन नियमों का ह्रास हो रहा है, जिससे समाज दिशाहीन होता जा रहा है।

इस दिशाहीनता के मूल में नैतिक मूल्यों का पतन है। पारिवारिक ढांचे में परिवर्तन, शिक्षा के स्वरूप में बदलाव तथा सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रभाव इसके प्रमुख कारण हैं। संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ गया है, जिससे बच्चों को दादा-दादी जैसे अनुभवी सदस्यों के संस्कार और मार्गदर्शन से वंचित रहना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, उनमें सहनशीलता, त्याग और आदर जैसे गुणों का अभाव देखा जा रहा है। शिक्षा का उद्देश्य भी सीमित होकर केवल आजीविका अर्जन तक सिमट गया है।

जहां पहले गुरु-शिष्य संबंध अत्यंत पवित्र और आदर्श हुआ करता था, वहीं आज उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। शिक्षा, जो जीवन को दिशा देने वाली शक्ति थी, आज अपने मूल उद्देश्य से भटकती प्रतीत होती है। सोशल मीडिया ने युवाओं को गहराई से प्रभावित किया है। आभासी दुनिया में खोकर वे वास्तविकता से दूर हो रहे हैं। त्वरित सफलता की चाह में उनका संतुलन और जिम्मेदारी प्रभावित होती है।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

अभिनय से पहले शिक्षक थे चंकी

चंकी पांडे का जन्म 26 सितंबर 1962 को मुंबई में सुयश पांडे के रूप में हुआ था। वे हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं और 1980 के दशक के अंतिम वर्षों से फिल्म जगत में सक्रिय रहे हैं। अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। शुरुआती दौर में उन्हें मुख्य रूप से गंभीर और एक्शन प्रधान भूमिकाओं में देखा गया, जबकि बाद के वर्षों में उन्होंने हास्य भूमिकाओं के जरिए भी दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई। वे अभिनेत्री अनन्या पांडे के पिता हैं।



चंकी पांडे
जन्म : 26 सितंबर 1962

चंकी पांडे का जन्म ऐसे परिवार में हुआ, जिसका चिकित्सा और सार्वजनिक जीवन से गहरा संबंध रहा। उनके पिता शरद पांडे देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सकों में शामिल थे। उन्हें हृदय चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है और उनके नाम से 'पांडे शंट' तकनीक भी जुड़ी हुई है। उन्होंने भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाली चिकित्सकीय टीम का नेतृत्व किया था। उनकी मां स्नेहलता पांडे भी चिकित्सक थीं और स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करती थीं।

स्नेहलता पांडे का जन्म विभाजन से पहले रावलपिंडी में हुआ था और वे पंजाबी परिवार से थीं। चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के अलावा उन्होंने स्वास्थ्य और वजन कम करने से जुड़े विषयों पर भी काम किया। 1980 के दशक में उन्होंने मुंबई में सौंदर्य केंद्र और वजन कम करने से संबंधित एक क्लिनिक शुरू किया था। उस समय यह अपनी तरह की शुरुआती पहलों में शामिल था। बताया जाता है कि उनके कई प्रसिद्ध फिल्मी सितारे भी ग्राहक रहे। उन्होंने वजन कम करने से संबंधित विषयों पर पुस्तकें और लेख भी लिखे।

चंकी पांडे के परिवार का फिल्म जगत से भी संबंध रहा है। उनकी मां की ओर से उनके मामा राज कुमार कपूर भारतीय सेना में अधिकारी रहे थे और बाद में अभिनेता बने। राज कुमार कपूर ने अभिनय के क्षेत्र में काम किया और शाहरुख खान को टेलीविजन धारावाहिक 'फौजी' के माध्यम से शुरुआती अवसर देने वालों में उनका नाम लिया जाता है। चंकी पांडे के छोटे भाई चिकी पांडे व्यवसायी हैं और उनका विवाह स्वास्थ्य एवं जीवनशैली से जुड़ी विशेषज्ञ डीन पांडे से हुआ है।

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि, अनुचित व्यवहार की शिकायतों पर संवेदनशीलता जरूरी





डॉ. प्रियंका सौरभ
पीएचडी (राजनीति विज्ञान)

स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं होते। वे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, संस्कार, अनुशासन और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। माता-पिता जब बच्चों को विद्यालय भेजते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि शिक्षक ज्ञान देने के साथ उनकी सुरक्षा और गरिमा का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जब किसी शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी, अनुचित व्यवहार या यौन उत्पीड़न की घटना सामने आती है तो केवल एक बच्ची नहीं, बल्कि पूरे शैक्षणिक तंत्र पर सवाल खड़े होते हैं।

हर मामले की प्रकृति और तथ्य अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी ठहराना उचित नहीं है। लेकिन शिकायत को दबाना, बच्ची को चुप कराना या विद्यालय की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामले को टालना भी गंभीर समस्या है। किसी भी संस्थान की छवि बच्चों की सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती। शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है। शिक्षक के पास ज्ञान के साथ अधिकार भी होता है और बच्चे उसे एक विश्वसनीय वयस्क मानते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इस विश्वास का दुरुपयोग करता है तो बच्चे के लिए विरोध करना आसान नहीं होता।

किशोरावस्था में कई बच्चे यह समझ नहीं पाते कि किसी वयस्क का व्यवहार सामान्य है या अनुचित। डर, शर्म, सामाजिक दबाव और यह चिंता कि उनकी बात पर विश्वास किया जाएगा या नहीं, उन्हें शिकायत करने से रोक सकती है। इसलिए यह पूछने के बजाय कि बच्ची ने पहले शिकायत क्यों नहीं की, हमें यह देखना चाहिए कि क्या विद्यालय ने ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाया है जहां वह बिना डर अपनी बात कह सके।

ऐसे मामलों में सबसे खतरनाक चुप्पी होती है। परिवार बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते और कभी-कभी विद्यालय प्रशासन भी संस्थान की छवि खराब होने की चिंता में मामले को दबाने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसी चुप्पी गलत व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है। यदि शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो बच्चे को यह संदेश मिलता है कि उसकी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण संस्थान की प्रतिष्ठा है।

इसलिए हर शिकायत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोष सिद्ध होने पर कानून और संस्थागत नियमों के अनुसार कार्रवाई जरूरी है। विद्यालयों को केवल घटना के बाद सक्रिय होने के बजाय पहले से मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए। कर्मचारियों का उचित सत्यापन, स्पष्ट आचार-संहिता, विद्यार्थियों से व्यवहार के नियम और सुरक्षित शिकायत व्यवस्था आवश्यक है।

बच्चों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि अच्छा और अनुचित स्पर्श क्या होता है तथा असहज व्यवहार होने पर वे किसे बता सकते हैं। उन्हें यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि किसी अनुचित व्यवहार के लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां बच्चे बिना भय अपनी बात रख सकें। महिला शिक्षक, प्रशिक्षित परामर्शदाता और विश्वसनीय शिकायत तंत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारत में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए पॉक्सो अधिनियम मौजूद है। विद्यालयों और कर्मचारियों को इसकी मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। किसी गंभीर शिकायत को केवल विद्यालय का आंतरिक मामला मानकर दबाना उचित नहीं है। मामले की प्रकृति के अनुसार संबंधित अधिकारियों को सूचना देना और जांच में सहयोग करना आवश्यक हो सकता है।

समाज में अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद बच्ची के कपड़ों, व्यवहार या गतिविधियों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह सोच गलत है। किसी बच्चे का व्यवहार किसी वयस्क को अनुचित आचरण का अधिकार नहीं देता। जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो अपनी उम्र, स्थिति और अधिकार का दुरुपयोग करता है। बच्चों को डराने के बजाय आत्मविश्वास देना होगा ताकि वे असहज महसूस होने पर बिना शर्म और भय अपनी बात कह सकें।

अधिकांश शिक्षक ईमानदारी और समर्पण से बच्चों का भविष्य बनाते हैं। इसलिए कुछ लोगों के गलत आचरण के आधार पर पूरे शिक्षक समुदाय को दोषी ठहराना उचित नहीं है। लेकिन शिक्षकों की पेशेवर जिम्मेदारी अधिक है। व्यक्तिगत संदेश, अनुचित टिप्पणी, अनावश्यक शारीरिक संपर्क या एकांत में बुलाने जैसी स्थितियों को लेकर विद्यालयों में स्पष्ट नियम होने चाहिए।

विद्यालय प्रशासन को हर शिकायत को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन बिना जांच किसी को दोषी ठहराना भी उचित नहीं है। सही रास्ता बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना, निष्पक्ष जांच करना और निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई करना है। अभिभावकों को भी बच्चों के साथ खुला संवाद रखना चाहिए। यदि बच्चा किसी व्यक्ति के व्यवहार से असहज है तो उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए।

डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के साथ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद के लिए स्पष्ट डिजिटल आचार-संहिता जरूरी है। निजी और अनुचित बातचीत पर रोक तथा संस्थागत माध्यमों के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्यालय में किसी छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार केवल एक अपराध का मामला नहीं, बल्कि उस विश्वास पर प्रहार है जिसके आधार पर माता-पिता बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। हमें न हर आरोप को बिना जांच सत्य मानना चाहिए और न ही बदनामी के डर से शिकायत दबानी चाहिए।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

प्रयागराज नगर निगम बनाएगा 15 नए दो कमरों वाले फ्लैट, पांच करोड़ होंगे खर्च

एजेंसी, प्रयागराज। प्रयागराज नगर निगम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुख्यालय के पास नया आवासीय परिसर बनाएगा। करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस परिसर में 15 नए दो कमरों वाले फ्लैट होंगे। दो मंजिला भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परिसर में पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। नगर निगम के पुराने आवास जर्जर हो चुके हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नए आवास बनने के बाद उन्हें पुराने और जर्जर भवनों में रहने से राहत मिलेगी। मुख्यालय के नजदीक आवास होने से अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचने में भी सुविधा होगी। परियोजना के तहत पुराने आवासों के स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन तैयार किया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को इन फ्लैटों में आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

आईआईआईटी प्रयागराज में जेआरएफ से एसआरएफ की नई व्यवस्था

एजेंसी, प्रयागराज। आईआईआईटी प्रयागराज ने जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) से सीनियर रिसर्च फेलो (एसआरएफ) में अपग्रेडेशन के नियमों में बदलाव किया है। संस्थान ने नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। अब केवल एक शोध पत्र प्रकाशित करना एसआरएफ में अपग्रेडेशन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। शोधार्थियों को तीन प्रमुख कसौटियां पूरी करनी होंगी। पहली शर्त के तहत शोधार्थी को अपने शोध कार्य से संबंधित आवश्यक उपलब्धियां हासिल करनी होंगी। दूसरी शर्त में शोध की गुणवत्ता और उससे जुड़े अकादमिक कार्यों को महत्व दिया जाएगा। तीसरी शर्त शोधार्थी के शोध प्रदर्शन और प्रगति से संबंधित होगी। इन सभी मानकों का मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य शोध कार्य की गुणवत्ता बढ़ाना और शोधार्थियों के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन करना है। संस्थान की मंजूरी के बाद अब जेआरएफ से एसआरएफ अपग्रेडेशन की प्रक्रिया नए नियमों के आधार पर होगी।

स्कूल से बुलाकर 15 वर्षीय साले पर चाकुओं से हमला, जीजा गिरफ्तार

एजेंसी, अमरोहा। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगाचोली गांव में जीजा ने कक्षा आठ के 15 वर्षीय छात्र जितेंद्र पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया गया कि आरोपित जीजा छात्र को स्कूल से यह कहकर बाहर ले गया कि उसे चाबी लेनी है। इसके बाद उसने छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले के दौरान बच्चों की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने आरोपित को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद घायल छात्र को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है।

कानपुर में नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू संक्रमण तीन नए मरीज मिले, अब तक 47 केस

एजेंसी, कानपुर। कानपुर में स्वाइन फ्लू और डेंगू का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में दोनों बीमारियों के तीन-तीन नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लू संक्रमितों की संख्या 47 पहुंच गई है, जबकि डेंगू के 125 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। नए मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ ही लोगों को बीमारी से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्यकर्मी संभावित स्थानों पर लार्वा की जांच कर उसे नष्ट करने का अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। लोगों से आसपास पानी जमा न होने देने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग नए मामलों पर भी नजर रख रहा है।

सिलेंडर के साथ चायपत्ती-नमक खरीदने का दबाव, कानपुर में उपभोक्ता परेशान

एजेंसी, कानपुर

कानपुर में एलपीजी सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं को गैस के साथ चायपत्ती, नमक, सर्फ और अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए मजबूर किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसियों पर अतिरिक्त सामान की बिक्री थोपने का आरोप लगाया है। इससे ग्राहकों में नाराजगी बढ़ रही है।

उपभोक्ताओं के अनुसार, जब वे सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि गैस के साथ कोई अन्य घरेलू उत्पाद भी खरीदना होगा। चायपत्ती, नमक और सर्फ जैसे सामान लेने से इनकार करने पर एजेंसी संचालक सिलेंडर का स्टाक खत्म होने की बात कहकर उन्हें वापस कर देते हैं। कई ग्राहकों का आरोप है कि इसके बाद उन्हें सिलेंडर के लिए बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ग्राहकों का कहना है कि उन्हें आवश्यकता नहीं होने के बावजूद अतिरिक्त सामान खरीदना पड़ रहा है। कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि गैस सिलेंडर जरूरी होने के कारण मजबूरी में एजेंसी द्वारा बताए गए उत्पाद खरीदने पड़ते हैं।

इससे घरेलू बजट पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों से ऐसी शिकायतें सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों के स्तर पर मामले को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर के साथ अनावश्यक सामान खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। अधिकारियों ने शिकायतों की जांच कराने और यदि जबरन बिक्री की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

यूपी के 3.54 लाख रसोइयों का बढ़ा मानदेय अक्टूबर से खाते में आएंगे 3000 रुपए

पीएम पोषण योजना के तहत 1.42 लाख विद्यालयों में 1.46 करोड़ छात्र-छात्राएं जुड़े

एजेंसी, लखनऊ



उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले करीब 3.54 लाख रसोइयों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ अक्टूबर से मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सितंबर से रसोइयों का मानदेय 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। शासन ने जिलों में मानदेय का भुगतान समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अक्टूबर में रसोइयों के खातों में बढ़ा हुआ मानदेय पहुंचाने की तैयारी है।

पीएम पोषण योजना के तहत प्रदेश के करीब 1.42 लाख राजकीय, परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इन विद्यालयों में वर्तमान में करीब 1.46 करोड़ छात्र-छात्राएं योजना से जुड़े हैं। बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजना में भोजन की गुणवत्ता और पोषण संबंधी मानक भी निर्धारित किए गए हैं। शासन के अनुसार जिलों में रसोइयों के मानदेय का भुगतान जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाता है।

अलग-अलग जिलों में हर महीने भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसे देखते हुए शासन ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि रसोइयों का मानदेय समय से जारी किया जाए, ताकि उन्हें भुगतान के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। सरकार की ओर से सितंबर से लागू बढ़ोतरी के बाद अब रसोइयों को हर महीने 3000 रुपये मानदेय मिलेगा। पहले उन्हें 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। इस तरह मानदेय में 1000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है।

अक्टूबर में बढ़ी हुई राशि का भुगतान समय से करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों के भोजन में कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा के मानक भी तय हैं। प्राथमिक कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का मानक निर्धारित है। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराने का मानक है। योजना का उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ उनकी नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना भी है।

रसोइये विद्यालयों में भोजन तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। उनके मानदेय में बढ़ोतरी के साथ शासन ने भुगतान प्रक्रिया को भी समयबद्ध रखने पर जोर दिया है। अक्टूबर से बढ़ा हुआ मानदेय मिलने से प्रदेश के 3.54 लाख रसोइयों को सीधे लाभ मिलेगा। जिलों में भुगतान की प्रक्रिया जिलाधिकारी के माध्यम से पूरी की जाएगी। शासन के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों और अधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा। इससे रसोइयों को पुराने मानदेय की तुलना में हर महीने 1000 रुपये अधिक मिलेंगे और सितंबर से लागू बढ़ोतरी का लाभ उन्हें आगे भी मिलता रहेगा।

नीट पीजी में यशी सक्सेना ने हासिल की अखिल भारतीय 124वीं रैंक

एजेंसी, मेरठ

मेरठ की बेटी यशी सक्सेना ने नीट पीजी 2026 की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर 124वीं रैंक हासिल की है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) की ओर से आयोजित नीट पीजी परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद यशी की उपलब्धि से परिवार और शहर में खुशी का माहौल है। नीट पीजी परीक्षा मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस जैसे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।



नीट पीजी में यशी की सफलता परिवार में खुशी का माहौल

इस वर्ष यह परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित हुई थी। देशभर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था। परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों की रैंक के आधार पर आगे प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। यशी सक्सेना ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए मेरठ का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता को लेकर स्वजन और परिचितों ने खुशी जताई है। परिवार के अनुसार, यशी ने परीक्षा की तैयारी के दौरान नियमित अध्ययन और मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया। यशी के पिता डॉक्टर संजीव सक्सेना वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। वहीं उनकी माता डॉक्टर प्रीति सिन्हा एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में एनाटमी विभाग की अध्यक्ष हैं। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े परिवार में पली-बढ़ी यशी ने भी मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नीट पीजी परीक्षा में यह उपलब्धि हासिल की है।

परिणाम सामने आने के बाद यशी को बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। परिवार और परिचितों ने उनकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। अखिल भारतीय 124वीं रैंक हासिल करने के बाद अब यशी के सामने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश का अगला चरण है। उनकी इस उपलब्धि से मेरठ के लोगों में भी खुशी है।

प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग स्टेशन तैयार, बिजली मिलते ही दौड़ेंगी बसें

एजेंसी, प्रयागराज



छह फास्ट चार्जिंग मशीनें स्थापित, बिजली मिलते ही शुरू होगी इलेक्ट्रिक बसों की ट्रायल।

संगम नगरी में पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवा के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। राजापुर स्थित लीडर रोड डिपो वर्कशाप में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन का बुनियादी ढांचा पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। स्टेशन पर निर्धारित सभी छह आधुनिक फास्ट-चार्जिंग मशीनें भी स्थापित कर दी गई हैं। अब बसों के संचालन के लिए केवल बिजली कनेक्शन का इंतजार है।

तकनीकी रूप से चार्जिंग यार्ड तैयार है, लेकिन इसे हाई-टेंशन बिजली आपूर्ति से जोड़ने का काम बाकी है। बिजली कनेक्शन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार अगले एक माह के भीतर ट्रांसफार्मर और लाइन चार्जिंग का काम पूरा कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक बसों की ट्रायल चार्जिंग शुरू की जाएगी। इन बसों को इंटरसिटी सेवा के रूप में चलाने की तैयारी है।

उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे पर एक और दाग, एलिवेटेड रोड से टपका पानी

एजेंसी, लखनऊ। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड पर शुक्रवार को हल्की बारिश के दौरान कई जगहों से पानी टपकने लगा। बंथरा क्षेत्र में एलिवेटेड रोड से पानी नीचे गिरता दिखाई दिया। कुछ स्थानों पर पानी इस तरह बह रहा था, जैसे सड़क के ऊपर से छोटे-छोटे झरने उतर रहे हों। इससे एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गौरतलब है कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने के कुछ ही दिनों बाद से यह चर्चा में है। अब एलिवेटेड हिस्से में सीपेज की समस्या सामने आने से इसकी व्यवस्था पर एक और सवाल खड़ा हो गया है। शुक्रवार को बारिश के दौरान सड़क के विभिन्न हिस्सों से पानी नीचे गिरता रहा। राहगीरों और वाहन चालकों ने इस स्थिति को देखकर हैरानी जताई। एलिवेटेड रोड से पानी रिसने के कारण नीचे की सड़क और आसपास के हिस्सों में भी पानी गिरता रहा।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई स्लीपर बस, चालक समेत दो घायल

एजेंसी, लखनऊ



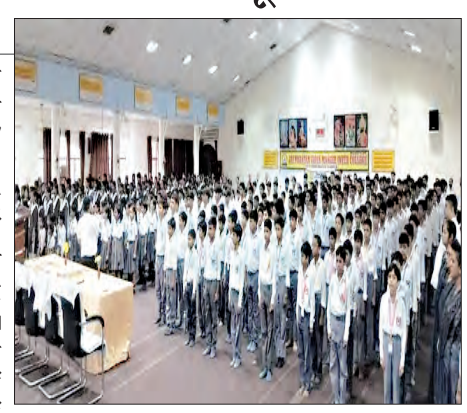
लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में शुक्रवार को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस चालक और एक यात्री घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा।

जानकारी के अनुसार, रेवरी टोल प्लाजा से आगरा की ओर करीब 500 मीटर आगे स्लीपर बस जा रही थी। इसी दौरान बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद बस सड़क पर ही रुक गई, जिससे पीछे से आने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और जाम की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलने पर काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल बस चालक और यात्री को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

बस में सवार अन्य 20 यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। हादसे में किसी अन्य यात्री के घायल होने की जानकारी नहीं है। पुलिस ने दुर्घटना के बाद सड़क पर खड़ी क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हटवाया। इसके बाद सड़क से अवरोध दूर किया गया और यातायात को सामान्य कराया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई।

बारिश के बीच 32 स्कूलों में गूंजा वंदे मातरम् 33 हजार छात्रों ने किया सामूहिक गायन

एजेंसी, कानपुर



कानपुर में हैं बारिश के बावजूद स्कूलों में गूंजा वंदे मातरम्, हजारों छात्र हुए शामिल।

कानपुर में शुक्रवार को बारिश के बीच भी विद्या भारती के 'नमामि भारतम्' कार्यक्रम के तहत 32 विद्यालयों में सामूहिक वंदे मातरम् गायन हुआ। इसमें 33 हजार से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने हिस्सा लिया। सुबह 11 बजे आयोजित विशेष सभा में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक स्वर में वंदे मातरम् का गायन किया। खराब मौसम के बावजूद छात्रों में उत्साह देखने को मिला।

विकास नगर स्थित जय नारायण विद्या मंदिर इंटर कालेज में भी विद्यार्थियों ने सामूहिक गायन किया। यहां मुख्य अतिथि प्रो. अरविंद दीक्षित और विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य नन्द किशोर मिश्र ने विद्यार्थियों को राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित किया। विद्यालय में करीब आठ सौ विद्यार्थियों और 100 से अधिक आचार्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। जवाहर नगर स्थित ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कालेज में 26 स्टाफ सदस्यों के साथ 854 विद्यार्थियों ने वंदे मातरम् गाया। न्यू आजाद नगर शाखा में भी 198 विद्यार्थियों और 32 स्टाफ सदस्यों ने हिस्सा लिया।

विद्या भारती के प्रदेश निरीक्षक अयोध्या मिश्र ने बताया कि प्रांत स्तर पर 500 विद्यालयों में दो लाख विद्यार्थियों के साथ गायन का लक्ष्य रखा गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना रहा।

कानपुर में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, चचेरा मामा फरार

एजेंसी, कानपुर। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्ची को टाफी-बिस्किट दिलाने के बहाने उसका चचेरा मामा गांव के बाहर मक्के के खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना गुरुवार देर शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, बच्ची अपनी मां के साथ ननिहाल आई हुई थी। आरोपित उसे टाफी और बिस्किट दिलाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। गांव के बाहर खेत में पहुंचने के बाद उसने बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को आता देखकर आरोपित वहां से भागने लगा।

ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। हालांकि, मौका पाकर आरोपित जंगल के रास्ते वहां से भाग निकला। इसके बाद घटना की जानकारी बच्ची के स्वजन और पुलिस को दी गई। स्वजन बच्ची को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार बच्ची की हालत सामान्य बताई गई है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। बच्ची और उसके स्वजन से भी जानकारी ली जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है और बच्ची के स्वजन से पूछताछ जारी है।

आगरा में प्लॉट पर संदिग्ध हालत में मिला साधु का शव, हत्या की आशंका

एजेंसी, आगरा



आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव सहाई में शुक्रवार सुबह 45 वर्षीय धर्मवीर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक प्लॉट पर मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। मृतक के स्वजन ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, धर्मवीर पुत्र दिगंबर सिंह सुबह करीब नौ बजे घर से निकले थे। कुछ समय बाद उनका शव गांव में स्थित एक प्लॉट पर मिला। शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। मृतक के स्वजन का कहना है कि धर्मवीर की मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शव मिलने के बाद गांव में भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक जानकारी जुटाई और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि धर्मवीर घर से निकलने के बाद प्लॉट तक कैसे पहुंचे और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई।

मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि धर्मवीर की मौत से जुड़े घटनाक्रम की पूरी जानकारी सामने आ सके।

तैयारी तीन एकड़ जमीन के लिए बजट प्रस्ताव मुख्यालय भेजा, वित्तीय मंजूरी मिलते ही शुरू होगी रजिस्ट्री

फाफामऊ में बनेगा ई-बस डिपो, जमीन खरीद के लिए भेजा गया 50 करोड़ का प्रस्ताव

एजेंसी, प्रयागराज



संगमनगरी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में फाफामऊ में प्रस्तावित इलेक्ट्रिक बस डिपो की परियोजना आगे बढ़ गई है। डिपो के लिए जमीन खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव तैयार कर लखनऊ स्थित मुख्यालय भेज दिया है। वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद जमीन की विधिवत रजिस्ट्री कराकर निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। विभाग का लक्ष्य कुंभ 2031 से पहले डिपो को चालू करना है।

फाफामऊ में प्रस्तावित ई-बस डिपो के लिए लखनऊ मार्ग के ठीक बगल में पुलिस आवास के पास करीब तीन एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। इस जमीन को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) उपलब्ध कराएगा। पीडीए बोर्ड की बैठक में जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर औपचारिक मुहर भी लग चुकी है। अब परियोजना के लिए बजट की स्वीकृति का इंतजार है।

यूपीएसआरटीसी अधिकारियों के अनुसार, बजट स्वीकृत होने के बाद जमीन की खरीद और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद डिपो के निर्माण की दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू होगी। प्रस्तावित डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से संबंधित आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे फाफामऊ क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विस्तार देने में मदद मिलेगी।

फाफामऊ का चयन परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ मार्ग के किनारे जमीन उपलब्ध होने से यहां से बसों का संचालन विभिन्न मार्गों पर सुविधाजनक तरीके से किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा।

परियोजना को कुंभ 2031 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जमीन खरीद से लेकर निर्माण तक की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करना जरूरी होगा। फिलहाल 50 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मुख्यालय भेजा जा चुका है और स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना के अगले चरण पर काम शुरू होगा। फाफामऊ में ई-बस डिपो बनने से आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मजबूत होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अलग डिपो उपलब्ध होने से बसों की पार्किंग, संचालन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा।

इससे प्रयागराज में इलेक्ट्रिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार को भी गति मिलने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद जमीन की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इसके बाद निर्माण संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर डिपो को निर्धारित समयसीमा में तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। कुंभ 2031 से पहले इसे चालू करने का लक्ष्य होने के कारण आने वाले समय में परियोजना से जुड़ी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। इस डिपो के बनने से फाफामऊ और आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर बस सेवा मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को नई दिशा मिलेगी।

प्रयागराज में दो दिनों से बारिश, मौसम हुआ सुहावना; 24 घंटे में 50 मिमी बरसा पानी

एजेंसी, प्रयागराज



मानसून की विदाई से पहले प्रयागराज में बारिश का दौर, मौसम हुआ सुहावना।

प्रयागराज में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर सक्रिय हो गया है। पिछले दो दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश ने शहर के मौसम का मिजाज बदल दिया है। लगातार बादल छाए रहने और बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार को भी सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कई इलाकों में रिमझिम बारिश होती रही।

बीते 24 घंटे में प्रयागराज में करीब 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश की रफ्तार बहुत तेज नहीं रही, लेकिन लगातार होती फुहारों ने शहर को पूरी तरह भिगो दिया। चौक समेत कई इलाकों में लोग बारिश से बचने के लिए छाते लेकर घरों से निकलते नजर आए। सड़कों पर भी बारिश का असर दिखाई दिया और लोगों को आवाजाही के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई की बेला में भी प्रयागराज और आसपास के जिलों में बादलों की सक्रियता बनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम में आए इस बदलाव से दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। लगातार बारिश से शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली है। सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस किया जा रहा है। हालांकि बारिश के कारण कुछ स्थानों पर जलभराव और यातायात की स्थिति प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की विदाई से पहले बारिश का यह दौर स्थानीय मौसम परिस्थितियों और बादलों की सक्रियता के कारण बना हुआ है।

बादलों ने डाला डेरा, रिमझिम बारिश के बीच छाते लेकर निकले लोग

आने वाले दिनों में भी रुक-रुककर बारिश जारी रहने की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है और मौसम सुहावना बना रहेगा। बारिश के चलते शहर के बाजारों में भी लोगों की आवाजाही प्रभावित रही। कई जगह दुकानदारों ने बारिश से बचाव के लिए सामान ढककर रखा। मौसम में बदलाव से किसानों को भी राहत मिली है, जबकि जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

आईवीएफ उपचार असफल होने पर अस्पताल डॉक्टर को 1.20 लाख लौटाने का आदेश

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद



आईवीएफ उपचार के बाद गर्भधारण नहीं होने से जुड़े मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता को राहत दी है। आयोग ने मेडिचेक सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, संबंधित डॉक्टर और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से 1.20 लाख रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही शिकायत दर्ज होने की तारीख से भुगतान होने तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। आयोग ने मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 5500 रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 5500 रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश दिए हैं।

शिकायतकर्ता प्रीति शर्मा ने अगस्त 2021 में आईवीएफ उपचार के लिए अस्पताल का रुख किया था। शिकायत के अनुसार अस्पताल की ओर से उपचार और परामर्श के लिए 1.50 लाख रुपये की मांग की गई थी। प्रीति शर्मा ने उपचार पर करीब 1.41 लाख रुपये खर्च किए। इसके अलावा दवाओं के लिए उन्होंने 29,529 रुपये का भुगतान किया। उपचार के बाद भी गर्भधारण नहीं होने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

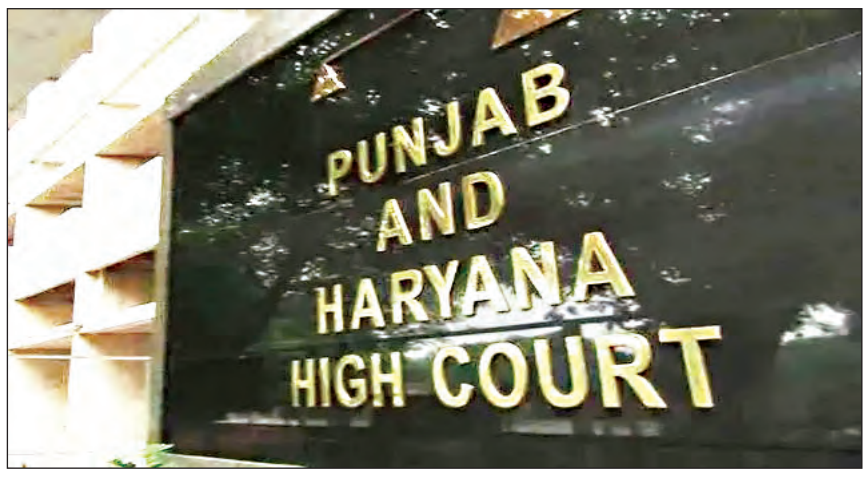
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने शिकायत से जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया। आयोग के आदेश के अनुसार अस्पताल, संबंधित डॉक्टर और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से निर्धारित राशि वापस करनी होगी। भुगतान में देरी होने पर आदेश में तय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

आयोग ने शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी और उत्पीड़न को देखते हुए 5500 रुपये अलग से देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मुकदमे पर हुए खर्च की भरपाई के लिए भी 5500 रुपये देने को कहा गया है। इस तरह मुख्य राशि के साथ ब्याज और अन्य निर्धारित रकम का भुगतान करना होगा। आईवीएफ उपचार के लिए शिकायतकर्ता ने वर्ष 2021 में अस्पताल का रुख किया था।

साक्षात्कार में अनुपयुक्त, नौकरी का दावा खारिज

परियोजना प्रभावित व्यक्ति के तौर पर नौकरी के लिए विचार हुआ, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल सकी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



जमीन अधिग्रहण के बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में नौकरी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे याचिकाकर्ता को करीब 25 साल बाद भी राहत नहीं मिल सकी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बीपीसीएल में नियुक्ति की मांग को लेकर वर्ष 2001 में दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता को परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) श्रेणी के तहत नियुक्ति के लिए विचार का अवसर दिया गया था, लेकिन साक्षात्कार में उसे उपयुक्त नहीं पाया गया था।

जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने फरीदाबाद निवासी सतिंदर सिंह और एक अन्य की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिका में आठ नवंबर 2000 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके माध्यम से बीपीसीएल में नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी जमीन का अधिग्रहण परियोजना के लिए किया गया था और इसके बाद उन्हें कंपनी में रोजगार दिए जाने की उम्मीद थी। मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता को परियोजना प्रभावित व्यक्ति के रूप में नौकरी के लिए विचार किया गया था। इसके लिए उसे साक्षात्कार का अवसर भी दिया गया। हालांकि, साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद बीपीसीएल ने उसे नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना। इसके बाद नियुक्ति नहीं मिलने पर संबंधित व्यक्ति ने विभागीय स्तर पर अपना दावा रखा और बाद में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वर्ष 2001 में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने बीपीसीएल के उस निर्णय को चुनौती दी, जिसके तहत नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं किया गया था। मामला लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में लंबित रहा। करीब 25 साल बाद हाई कोर्ट ने अब इस पर फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

जमीन अधिग्रहण, नौकरी का अधिकार नहीं

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नियुक्ति से जुड़े तथ्यों और चयन प्रक्रिया को ध्यान में रखा। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को परियोजना प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी में नौकरी के लिए विचार का अवसर दिया गया था। उसे साक्षात्कार में शामिल भी किया गया, लेकिन चयन प्रक्रिया में उपयुक्त नहीं पाए जाने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि केवल भूमि अधिग्रहण होने और पीएपी श्रेणी में विचार किए जाने से नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं बनता।

हरियाणा बैंक घोटाले में छह आईएएस पर चार्जशीट, सीबीआई के गंभीर आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला



हरियाणा के कथित बैंक घोटाले की जांच में सीबीआई ने पंचकूला की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें छह आईएएस अधिकारियों समेत बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी ने अधिकारियों पर सरकारी धन को निजी बैंकों में निवेश कराने, बैंक चयन और एफडी से जुड़े नियमों की अनदेखी करने तथा वित्त विभाग की निर्धारित सीमाओं को दरकिनार करने के आरोप लगाए हैं।

सीबीआई के आरोपपत्र में आरके सिंह (राम कुमार सिंह), पंकज अग्रवाल, प्रदीप कुमार, विनीत गर्ग और मोहम्मद शाइन समेत छह आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार, बैंक अधिकारियों और अन्य आरोपियों के साथ कथित साजिश के तहत सरकारी धन निजी बैंकों में स्थानांतरित कराया गया। निवेश प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी के अलावा दस्तावेजों में कथित हेरफेर और साक्ष्य छिपाने के आरोप भी लगाए गए हैं। आरोपपत्र में रिश्वत अथवा अन्य अनुचित लाभ लेने से संबंधित आरोपों का भी उल्लेख है।

आरोपपत्र के अनुसार, तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त एवं सचिव और बाद में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रहे पंकज अग्रवाल पर निजी बैंक अधिकारी रिभव ऋषि से कथित अनुचित लाभ लेने का आरोप है। सीबीआई ने आरोपपत्र में मुजरा पार्टियों से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख किया है। विनीत गर्ग पर आईडीएफसी बैंक को प्राथमिकता देने और सोने के सिक्के लेने से संबंधित आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने सरकारी धन के निवेश और बैंक चयन की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की भी जांच की है। आरोपपत्र में आरके सिंह पर 50 लाख रुपये की नकदी और उनके बेटे को दो करोड़ रुपये दिए जाने से संबंधित आरोपों का उल्लेख है। मामले में 10 रुपये के कथित गुप्त कोड का भी जिक्र किया गया है।

सीबीआई की ओर से लगाए गए ये आरोप अभी आरोपपत्र में दर्ज दावे हैं। मामले में अदालत के समक्ष आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत सीबीआई की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण करेगी। आरोपियों को अपना पक्ष रखने और आरोपों का जवाब देने का पूरा कानूनी अधिकार रहेगा। इसके बाद अदालत उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगी।

कैथल में ट्रक एक्सीडेंट से खुला ड्रग तस्करी का राज, 3 की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल। कैथल में दिल्ली-जम्मू नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे के बाद नशा तस्करी के मामले का खुलासा हुआ है। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में शामिल राजस्थान नंबर के एक ट्रक की जांच के दौरान उसमें बड़ी मात्रा में डोडापोस्त छिपाकर ले जाने की बात सामने आई। ट्रक में केलों की खेप के नीचे 40 कट्टे डोडापोस्त छिपाए गए थे। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ट्रक राजस्थान नंबर का था और उसमें ऊपर से केले लदे हुए थे। तस्करी के लिए डोडापोस्त के कट्टों को केलों के नीचे छिपाया गया था, ताकि पहली नजर में ट्रक में किसी तरह का संदिग्ध सामान दिखाई न दे। दिल्ली-जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य संबंधित टीमों ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जांच शुरू की। जांच के दौरान ट्रक में छिपाकर रखा गया डोडापोस्त बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने मामले को नशा तस्करी से जोड़कर जांच शुरू कर दी। बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा और अनुमानित कीमत के आधार पर पुलिस तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

सोनीपत में घटिया सड़क निर्माण पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

तीन दिन पहले बनी सड़क की परत कई जगहों से आसानी से उखड़ी

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत



सोनीपत के गांव किलोहड़द में ट्रिपल आईटी की ओर जाने वाली सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क पर चारपाई बिछाकर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सड़क की परत को हाथों से उखाड़कर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और सड़क को निर्धारित मानकों के अनुसार दोबारा बनाने की मांग की।

ग्रामीणों के अनुसार सड़क का निर्माण हुए अभी तीन दिन ही हुए हैं, लेकिन कई स्थानों पर इसकी परत हाथ से ही उखड़ रही है। ग्रामीणों ने करीब पांच से छह स्थानों पर सड़क की परत उखाड़कर देखी। उनका आरोप है कि सभी जगह निर्माण सामग्री की स्थिति एक जैसी मिली। लेयर बिछाने से पहले नीचे की सतह की ठीक से सफाई नहीं की गई और रेत के ऊपर ही सामग्री डाल दी गई। ग्रामीण वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में पर्याप्त रोड़ी नहीं डाली गई और तारकोल का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि यह मार्ग ट्रिपल आईटी जाने का छोटा रास्ता होने के साथ आसपास के खेतों तक पहुंचने का प्रमुख मार्ग भी है। बारिश होने के बाद सड़क के और टूटने की आशंका है। जिला पार्षद संजय बढ़वासनी ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत अधिकारियों से कर काम रुकवाने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद काम जारी रखा गया। उन्होंने बताया कि खराब हिस्से को दोबारा बनाने की बात कही गई, लेकिन दूसरे हिस्से में निर्माण शुरू कर पूरा मार्ग तैयार कर दिया गया। उनका आरोप है कि खराब हिस्से पर तैयार सामग्री डालने का प्रयास भी किया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। संजय बढ़वासनी ने निर्माण में मिलीभगत और कमीशनखोरी के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वह इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे।

- चारपाई बिछाकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जताया विरोध

एशियन गेम्स में हरियाणा के शूटर्स ने जीता गोल्ड, कमलजीत-सुरुचि की चमकी जोड़ी

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी/झज्जर

- एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक के साथ चमके हरियाणा के शूटर्स
- कमलजीत और सुरुचि ने एशियन गेम्स में बढ़ाया देश का मान

जापान के नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में हरियाणा के शूटर्स ने देश को गौरवान्वित किया है। रेवाड़ी के कमलजीत और झज्जर की सुरुचि ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला। दोनों ने कुल 484.6 अंक हासिल किए, जबकि दक्षिण कोरिया ने 478.0 अंक के साथ रजत और ईरान ने 415.8 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। कमलजीत और सुरुचि की कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि शूटिंग दोनों की पहली पसंद नहीं थी। सुरुचि के परिवार की इच्छा थी कि वह कबड्डी खिलाड़ी बने।

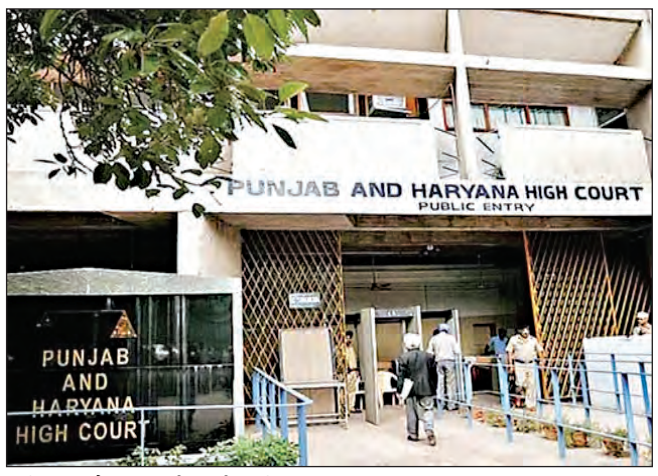
दूसरी ओर कमलजीत की शुरुआत एथलेटिक्स से हुई थी। वह स्प्रिंटर बनना चाहते थे, लेकिन चोट लगने के बाद उन्हें एथलेटिक्स छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने शूटिंग को करियर के रूप में चुना और लगातार मेहनत करते हुए इस खेल में पहचान बनाई। सुरुचि ने भी शूटिंग में अपनी प्रतिभा साबित की और कमलजीत के साथ मिलकर एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय जोड़ी ने मुकाबले के दौरान लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद दोनों खिलाड़ियों के परिवारों में खुशी का माहौल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कमलजीत और सुरुचि की उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। खिलाड़ियों की इस सफलता से उनके गृह जिलों रेवाड़ी और झज्जर में भी उत्साह का माहौल है।

दोनों खिलाड़ियों की यात्रा यह दिखाती है कि खेल में करियर बनाने की राह कई बार परिस्थितियों के साथ बदलती है। शुरुआती पसंद अलग होने के बावजूद कमलजीत और सुरुचि ने शूटिंग को अपनाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से हरियाणा के खेल जगत में भी खुशी की लहर है। कमलजीत और सुरुचि ने अपनी मेहनत और लगन से साबित किया कि सही अवसर और निरंतर अभ्यास से खिलाड़ी किसी भी खेल में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। उनके प्रदर्शन से युवा खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने और खेलों में करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी।

चाकू से हमला कर युवक संजीव कुमार की हुई थी हत्या, 26 साल बाद आया फैसला

26 साल पुराने हत्याकांड में पांच दोषियों की उम्रकैद बरकरार

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



नारायणगढ़ के करीब 26 साल पुराने हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पांच दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने दोषियों की ओर से सजा में राहत की मांग को स्वीकार नहीं किया। वहीं, मृतक के स्वजन की ओर से दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया गया, जिसमें पांचों दोषियों की उम्रकैद को मृत्युदंड में बदलने की मांग की गई थी। मामला नारायणगढ़ निवासी संजीव कुमार की हत्या से जुड़ा है। करीब 26 वर्ष पहले संजीव कुमार पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की थी। सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने पांच आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषियों ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इसी मामले में मृतक के स्वजन ने भी हाई कोर्ट का रुख करते हुए दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को मृत्युदंड में बदलने की मांग की थी। उनका कहना था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को अधिक कठोर सजा दी जानी चाहिए।

मामले की सुनवाई जस्टिस अर्चना पुरी और जस्टिस मनदीप पन्नू की पीठ ने की। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और मामले से जुड़े रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद पांचों दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। साथ ही मृतक के स्वजन की ओर से दायर मृत्युदंड की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पांचों दोषियों को अब उम्रकैद की सजा ही भुगतनी होगी। करीब ढाई दशक पुराने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों की सजा को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया है।

- संजीव कुमार हत्याकांड में हाई कोर्ट ने कायम रखी उम्रकैद

न्यूज ब्रीफ

हिसार में मंथली मांगने वाले पांच बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने कराई परेड

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। हरियाणा के हिसार में व्यापारियों से मंथली मांगने और हमला करने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान राहुल उर्फ गोल्डन, मोहित उर्फ रोज, काकू उर्फ मंगल, मोहित उर्फ भैया और आकाश के रूप में हुई है। आरोप है कि बदमाशों ने व्यापारियों से तीन लाख रुपये की मंथली मांगी थी। मांग पूरी नहीं होने पर दो व्यापारी भाइयों के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया था। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। शुक्रवार को सिविल लाइन पुलिस आरोपितों को उस स्टोर पर लेकर पहुंची, जहां से मंथली मांगी गई थी। पुलिस ने आरोपितों से घटनास्थल की निशानदेही कराई। उन्हें थाने से मुख्य मार्ग तक और वहां से करीब 200 मीटर अंदर पैदल ले जाया गया। आरोपितों को देखने के लिए बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मोहल्ले के लोग भी मौके पर पहुंच गए। मामले में पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

गैंगस्टर मैनपाल ढिल्ला की कंबोडियन पत्नी मेटाचान पहुंचीं ससुराल

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर। हरियाणा के झज्जर में जेल में बंद मैनपाल ढिल्ला ने 12 घंटे की पैरोल के दौरान कंबोडिया की मेटाचान से शादी की। शादी के बाद मैनपाल वापस जेल लौट गया, जबकि मेटाचान तीन बच्चों के साथ अपने ससुराल पहुंचीं। उन्होंने मंगलसूत्र पहन रखा था, जिस पर पति का नाम लिखा था। ससुराल पहुंचने के बाद मेटाचान ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्होंने मैनपाल से शादी की है और वह बहुत खुश हैं। मेटाचान के ससुराल पहुंचने पर परिवार के लोगों ने उनका स्वागत किया। कंबोडिया से आई बहू को देखकर उनकी मां भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेटाचान ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और घर की महिलाओं के साथ समय बिताया। इस दौरान आसपास के लोगों में भी उन्हें देखने को लेकर उत्सुकता रही। मैनपाल के जेल लौटने के बाद अब मेटाचान ससुराल में परिवार के साथ रह रही हैं।

आईटीआई प्रिंसिपल ने महिला अनुदेशक पर लगाया मारपीट का आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, नारनौल। हरियाणा के नारनौल स्थित सरकारी आईटीआई में प्रिंसिपल और दो अनुदेशकों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल विनोद खनगवाल ने एक महिला और एक पुरुष अनुदेशक पर कार्यालय में घुसकर हाथापाई करने का आरोप लगाया है। प्रिंसिपल के अनुसार, विवाद के दौरान एक अनुदेशक ने कुर्सी उठाकर उनकी ओर फेंकी और गाली-गलौज भी की। उन्होंने मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि दोनों अनुदेशकों के व्यवहार से कार्यालय में माहौल खराब हुआ और उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। शिकायत में घटना से जुड़े अन्य बिंदुओं का भी उल्लेख किया गया है। अधिकारियों को भेजी गई शिकायत के बाद मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

रोहतक में साढ़े 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म 10 दिन बाद भी आरोपी फरार

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक। रोहतक के एक निजी स्कूल में साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 10 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। परिवार का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में देरी से वे परेशान हैं और पिछले 10 दिनों से लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं। परिजनों के अनुसार, बच्ची के अब तक चार बार बयान दर्ज किए जा चुके हैं। उनका कहना है कि बार-बार पूछताछ से बच्ची और परिवार मानसिक रूप से परेशान हैं। परिजन पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने और मामले में उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद से परिवार न्याय की उम्मीद में पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर रहा है। वहीं, पुलिस की ओर से आरोपी की तलाश किए जाने की बात कही जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

गुरुग्राम मंदिर गेट पर 6 माह के मासूम को फेंककर फरार हुआ शख्स

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम



गुरुग्राम के विश्वकर्मा कॉलोनी स्थित चुकन्नी माता मंदिर के गेट पर गुरुवार रात करीब साढ़े नौ बजे छह माह के बच्चे को लावारिस छोड़ने का मामला सामने आया है। बच्चे के सिर में चोट लगी है। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-10ए थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार, रात में मंदिर के पास बच्चे के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों को घटना का पता चला। लोगों ने मंदिर के गेट के पास बच्चे को देखा और उसे तत्काल उठाकर उपचार के लिए सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बच्चे का उपचार शुरू किया। बताया गया कि बच्चे के सिर में चोट लगी थी। घटना मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास कर रही है, जिसने बच्चे को मंदिर के गेट पर छोड़ा था। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बच्चा मंदिर तक कैसे पहुंचा और उसे वहां छोड़ने के पीछे क्या कारण था। पुलिस टीम ने मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों और घटना के समय मौजूद लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस यह जानकारी जुटा रही है कि बच्चे को मंदिर के पास लाने वाले व्यक्ति को किसी ने पहले देखा था या नहीं। आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि संदिग्ध के आने और जाने का रास्ता पता चल सके। पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

लापरवाही बेटे के बजाय पिता की पेंशन बंद करने पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल

जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर रोकी पेंशन, अफसरों पर भड़के अनिल विज

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर



हरियाणा के यमुनानगर में सरकारी रिकॉर्ड की एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसमें 70 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड में मृत दिखाए जाने के बाद उसकी दिव्यांग पेंशन भी बंद कर दी गई। मामला सामने आने के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को फटकार लगाई और इस तरह की लापरवाही पर नाराजगी जताई।

मामला यमुनानगर निवासी 70 प्रतिशत दिव्यांग रवि किरण से जुड़ा है। रवि किरण वर्ष 2010 से दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे थे। बताया गया कि जनवरी 2026 में उनकी पेंशन अचानक बंद कर दी गई। इसके बाद उन्हें पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत दर्ज किया गया है। जीवित होने के बावजूद रिकॉर्ड में मृत घोषित किए जाने से वह हैरान रह गए। बताया गया कि रवि किरण अपने बेटे की दिव्यांग पेंशन बंद कराने के लिए संबंधित विभाग के कार्यालय पहुंचे थे।

इसी दौरान विभागीय स्तर पर कथित तौर पर ऐसी गलती हुई कि उनके बेटे की पेंशन के बजाय रवि किरण की अपनी पेंशन बंद कर दी गई। इसके साथ ही सरकारी रिकॉर्ड में रवि किरण को मृत दर्ज कर दिया गया। पेंशन बंद होने के बाद मामला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा। शिकायत के दौरान जब सरकारी रिकॉर्ड की स्थिति सामने आई तो विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे।

रवि किरण के अनुसार वह जीवित हैं और नियमित रूप से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड में उन्हें मृत दिखा दिया गया। मामले की जानकारी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज तक पहुंची तो उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब किया। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने सवाल किया कि जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने का अधिकार आखिर किसने दिया। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों से तीखे अंदाज में पूछा, 'तुम यमराज हो क्या?'

मंत्री की नाराजगी के बाद अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू की। अब विभागीय स्तर पर रिकॉर्ड में हुई गलती को ठीक करने और पेंशन बहाल करने की प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई की जा रही है। मामले ने सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली सूचनाओं की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। रवि किरण लंबे समय से दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे थे। ऐसे में अचानक पेंशन बंद होने और सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित किए जाने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। विभागीय गलती के कारण एक जीवित व्यक्ति को कागजों में मृत दर्ज करने का यह मामला सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली चर्चा में है।

आरके पुरम में आईटीबीपी कार्यालय को मंजूरी, 627 पेड़ों की कटाई पर उठे सवाल

2.5 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल को लेकर संरक्षण पर बहस तेज

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली रिज को अतिक्रमण और अनियंत्रित निर्माण से बचाने के लिए इसी वर्ष पुनर्गठित किए गए दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड की स्थायी समिति ने आरके पुरम में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के महानिदेशालय और केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय के निर्माण को मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए 2.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र के उपयोग का प्रस्ताव है। इसके तहत 627 पेड़ों की कटाई और 93 पेड़ों के प्रत्यारोपण की योजना है। रिज क्षेत्र में निर्माण को लेकर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है।



पर्यावरणीय संवेदनशीलता के बीच निर्माण को मंजूरी : दिल्ली रिज को राजधानी का महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र माना जाता है। रिज प्रबंधन बोर्ड का गठन और पुनर्गठन इसी उद्देश्य से किया गया है कि इसकी प्राकृतिक स्थिति बरकरार रहे, पारिस्थितिकी को बहाल किया जाए और गैर-जरूरी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। ऐसे में पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में एक बड़े प्रशासनिक कार्यालय के निर्माण को मंजूरी मिलने से संरक्षण और विकास के बीच संतुलन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

परियोजना के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। विशेषज्ञों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासनिक कार्यालय जैसी परियोजना के लिए रिज के बाहर वैकल्पिक भूमि की संभावनाओं पर पर्याप्त विचार किया गया। आइटीबीपी देश का महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा बल है, लेकिन प्रस्तावित निर्माण महानिदेशालय और केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय के लिए है।

आरके पुरम सेक्टर-10 में आवंटित है जमीन : सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आरके पुरम सेक्टर-10 में 2.487 एकड़ भूमि वर्ष 2022 में गृह मंत्रालय को आइटीबीपी से जुड़े विभिन्न कार्यालयों के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। प्रस्तावित भवन भू-आकृतिक रिज क्षेत्र और मानित वन क्षेत्र में आता है।

वैकल्पिक जमीन को लेकर उठे सवाल

पर्यावरण विशेषज्ञों और जानकारों का तर्क है कि आइटीबीपी के महानिदेशालय और केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय जैसे प्रशासनिक संस्थान दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि रिज क्षेत्र में निर्माण का विकल्प चुनने से पहले हरियाणा या उत्तर प्रदेश में उपलब्ध वैकल्पिक भूमि की संभावनाओं पर कितना विचार किया गया। जानकारों के अनुसार, रिज में ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनका सीधे दिल्लीवासियों के हित से संबंध हो। जबकि प्रशासनिक कार्यालय के लिए रिज भूमि के इस्तेमाल से जुड़े पर्यावरणीय असर पर अधिक व्यापक विचार की जरूरत बताई जा रही है। दिल्ली रिज के संरक्षण और पारिस्थितिकी बहाली के लिए सरकार और संबंधित एजेंसियां कई स्तर पर काम कर रही हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण करीब 120 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में देशज प्रजातियों के पौधे लगाने और आक्रामक वनस्पतियों को हटाने का कार्यक्रम चला रहा है।

गणेश विसर्जन के लिए यमुनापार में 20 अस्थायी तालाब तैयार

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा इंतजामों संग विसर्जन स्थलों पर व्यवस्था

एजेंसी, नई दिल्ली



गणेश उत्सव के समापन के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए यमुनापार क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से 20 अस्थायी तालाब तैयार किए गए हैं। इन तालाबों में श्रद्धालुओं को प्रतिमाओं के विसर्जन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने बृहस्पतिवार को सभी निर्धारित अस्थायी तालाबों में पानी भरने का काम पूरा किया। शुक्रवार को विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ सिविल डिफेंस वालंटियर भी तैनात रहेंगे।

उत्तर पूर्वी जिलाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर अस्थायी तालाब तैयार करवाए हैं। शास्त्री पार्क, करावल नगर समेत कई क्षेत्रों में विसर्जन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाओं को अस्थायी तालाब तक पहुंचाने के लिए निर्धारित स्थान बनाए गए हैं। प्रशासन की ओर से इन स्थानों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रतिमाएं लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित स्थानों पर व्यवस्था की गई है।

प्रशासन के अनुसार बृहस्पतिवार को भी कई श्रद्धालुओं ने निर्धारित अस्थायी तालाबों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी तालाबों में ही विसर्जन करें। इससे यमुना को प्रदूषण से बचाने के साथ विसर्जन प्रक्रिया को भी व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

सुरक्षा के लिए पुलिस और स्वयंसेवक तैनात

विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस वालंटियर की तैनाती की गई है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विसर्जन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, श्रद्धालुओं को निर्धारित मार्ग से ले जाने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा कई अस्थायी तालाबों के आसपास पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन ने निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, ताकि पूरे क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और किसी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन यमुना नदी में पूरी तरह प्रतिबंधित है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को यमुना में प्रतिमा विसर्जित न करने दिया जाए। इसके लिए प्रमुख घाटों और नदी किनारे के संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है। इस दौरान प्रशासन की ओर से विसर्जन स्थलों पर साफ-सफाई और रोशनी की भी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारियों ने लोगों से निर्धारित स्थानों पर ही प्रतिमा विसर्जित करने और नियमों का पालन करने की अपील की है।

कांस्टेबल भर्ती में फर्जीवाड़ा, असली अभ्यर्थी की जगह दूसरे ने दी परीक्षा

एजेंसी, नई दिल्ली

वजीराबाद स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में कांस्टेबल पद की शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में उतारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में सोनीपत के सिलाना डाकघर क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय अक्षत को गिरफ्तार किया है। सोनिया विहार थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

◆ बायोमीट्रिक जांच में संदिग्ध गतिविधि से पूरा फर्जीवाड़ा आया सामने



बताया गया कि अक्षत की जगह एक अन्य व्यक्ति ने दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद की शारीरिक परीक्षा दी। परीक्षा पूरी होने के बाद जब कद और सीने की माप के लिए प्रक्रिया शुरू हुई तो अक्षत खुद वहां पहुंचा। अधिकारियों को उस पर संदेह हुआ, क्योंकि दौड़ और अन्य शारीरिक गतिविधियों के बावजूद उसके शरीर पर पसीने के निशान नहीं थे और न ही धूल लगी थी। अन्य अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा देने वाले व्यक्ति की पहचान पर सवाल उठाए।

पुलिस पूछताछ में अक्षत ने बताया कि उसके भाई ने उसकी जगह शारीरिक परीक्षा देने के लिए एक अन्य व्यक्ति की व्यवस्था की थी। उस व्यक्ति ने कथित तौर पर फर्जी प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा स्थल में प्रवेश किया और अक्षत के नाम पर शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी की।

परीक्षा समाप्त करने के बाद फर्जी अभ्यर्थी ने अपना चेस्ट नंबर अक्षत को दे दिया। इसके बाद अक्षत ने स्वयं बायोमीट्रिक सत्यापन और कद-सीने की माप की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की। इसी दौरान अधिकारियों को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ और पूछताछ के बाद कथित फर्जीवाड़ा सामने आया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अक्षत को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके भाई और उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जिसने उसकी जगह शारीरिक परीक्षा दी थी।

स्कूली बच्चों में हड्डी-मांसपेशियों की बढ़ी समस्या, भारी बस्ते बने कारण

एजेंसी, नई दिल्ली। स्कूली बच्चों में हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हाल के वर्षों में ऐसी समस्याओं में करीब 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। भारी स्कूल बस्ता, लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करना, गलत मुद्रा में बैठना, लेटकर पढ़ना, बढ़ता स्क्रीन समय और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। यह जानकारी बृहस्पतिवार को दिल्ली में आयोजित विश्व भौतिक चिकित्सा के एशिया-पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों के विमर्श के दौरान सामने आई।

◆ गलत मुद्रा और कम शारीरिक गतिविधि से बढ़ रही बच्चों में परेशानी

विशेषज्ञों ने बताया कि पहले बच्चों के स्कूल बैग का वजन करीब दो किलोग्राम तक रहता था, लेकिन अब कई बच्चों के बस्ते का वजन सात से आठ किलोग्राम तक पहुंच गया है। लगातार भारी वजन उठाने से गर्दन, कंधे और कमर पर दबाव बढ़ता है। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने और गलत तरीके से पढ़ने से भी मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ सकता है।

भारतीय भौतिक चिकित्सा संघ के अध्यक्ष प्रो. डॉ. संजीव के. झा ने कहा कि बच्चों में नियमित शारीरिक गतिविधि, सही मुद्रा और शारीरिक फिटनेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आयोजन सचिव डॉ. रुचि वार्ष्णेय ने कहा कि बच्चों को नियमित रूप से चलने-फिरने और शरीर का सही इस्तेमाल करने की आदत डालना जरूरी है। भोपाल के चार स्कूलों में आठ से 15 वर्ष आयु के 934 बच्चों पर किए गए अध्ययन में 55.9 प्रतिशत बच्चों ने पिछले एक वर्ष के दौरान शरीर के किसी न किसी हिस्से में दर्द की शिकायत की।

एसओएल में स्नातक दाखिले की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 1.33 लाख विद्यार्थी ले चुके हैं दाखिला

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमित कॉलेजों और एनसीवेब में दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर बचा है। एसओएल में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद नए विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। ऐसे में जो विद्यार्थी इस सत्र में एसओएल के जरिये दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करना होगा।

जून से चल रही प्रवेश प्रक्रिया के तहत एसओएल के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में अब तक करीब 1.33 लाख विद्यार्थी दाखिला ले चुके हैं। हालांकि, अंतिम संख्या फीस भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।

◆ पंजीकरण कर विद्यार्थियों को 13 अक्टूबर तक फीस जमा करने की छूट



एसओएल प्रशासन के अनुसार विद्यार्थियों की ओर से दाखिले को लेकर लगातार आवेदन किए जा रहे हैं।

जिन विद्यार्थियों ने पंजीकरण कर लिया है, उनके लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। इसका मतलब है कि 30 सितंबर के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, लेकिन पहले से पंजीकृत विद्यार्थियों को फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

एसओएल में दाखिले के लिए विद्यार्थियों के पास अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की आईडी होना अनिवार्य है। प्रशासन ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया अंतिम तिथि से पहले पूरी कर लें। अंतिम दिनों में तकनीकी दिक्कत या दस्तावेजों से जुड़ी समस्या होने पर आवेदन प्रभावित हो सकता है।

एसओएल की निदेशक प्रो. पायल मागो ने विद्यार्थियों से अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एसओएल के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का यह सत्र का अंतिम अवसर है। विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की रुचि बनी हुई है, जिनमें बीए और बीकॉम में सबसे अधिक दाखिले दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली में ग्रिल-रेलिंग चोरी से पीडब्ल्यूडी परेशान

इस साल चोरी की 12 से अधिक घटनाएं, बारापुला से सुरक्षा स्क्रीन का हिस्सा गायब

दिल्ली में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सड़कों, पुलों और फुटओवर ब्रिज पर लगी सरकारी संपत्ति लगातार चोरों के निशाने पर है। सड़क किनारे लगी लोहे की ग्रिल और रेलिंग, डिवाइडर की जालियां, ध्वनि अवरोधक, तार, लाइटें और अन्य लोहे के सामान को चोर उखाड़कर ले जा रहे हैं। अब नवनिर्मित बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कारिडोर पर साइकिल सवारों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाई गई पुल ब्रिज स्क्रीन का करीब 20 मीटर हिस्सा चोरी हो गया है।



विभाग के अनुसार, इस वर्ष अब तक सरकारी सड़क संपत्ति चोरी होने की 12 से अधिक घटनाओं में पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है। लगातार हो रही चोरी से एक ओर जहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़क और पुलों पर सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ रहा है।

उद्घाटन से पहले बारापुला में चोरी : बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कारिडोर पर साइकिल मार्ग और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष स्क्रीन लगाई गई थीं। चोर इनका करीब 20 मीटर हिस्सा काटकर ले गए। यह घटना कारिडोर के उद्घाटन से कुछ दिन पहले सामने आई है। इन स्क्रीन का उद्देश्य वाहनों या अन्य वस्तुओं के पुल से नीचे गिरने के खतरे को कम करना और आसपास के क्षेत्रों में यातायात के शोर को नियंत्रित करना भी है।

घटना के बाद पीडब्ल्यूडी ने बारापुला फेज-3 पर रात के समय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का निर्णय लिया है। कारिडोर का उद्घाटन 29 सितंबर को प्रस्तावित है।लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के सामने आईटीओ मार्ग के डिवाइडर से करीब 50 स्टील की छड़ें भी चोरी हो चुकी हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं से सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पहले भी चोरी हो चुकी है सरकारी संपत्ति

सड़क और पुलों से सरकारी सामान चोरी होने का यह पहला मामला नहीं है। पिछले वर्ष से अब तक दिल्ली के कई इलाकों में सड़क किनारे लगी रेलिंग और डिवाइडर की ग्रिल गायब होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लक्ष्मी नगर, दिल्ली गेट, सराय काले खां और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास रेलिंग और ग्रिल चोरी होने की शिकायतें दर्ज की गई हैं। वर्ष 2023 में प्रगति मैदान और मथुरा रोड के आसपास भी पीडब्ल्यूडी की संपत्ति चोरी हुई थी। मथुरा रोड क्षेत्र में फुटओवर ब्रिज के सीढ़ीदार मार्ग की मोटर और अन्य लोहे के सामान भी चोरी किए गए थे।

वजीराबाद मुठभेड़ में गोगी-दीपक गिरोह का बदमाश गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद गोगी-दीपक बाक्सर गिरोह से जुड़े बदमाश मोहित को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मोहित टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के एक सदस्य की हत्या की साजिश के तहत दिल्ली आया था। उसे अपने एक साथी से मिलकर लक्षित व्यक्ति की गतिविधियों और ठिकाने की जानकारी लेकर हमला करना था। पुलिस ने 23 सितंबर की रात करीब 1:40 बजे वजीराबाद में मोटरसाइकिल सवार मोहित को रोकने का प्रयास किया। भागने के दौरान उसने पुलिस टीम पर दो गोलियां चलाईं। जवाब में पुलिस ने भी तीन राउंड फायर किए। बदमाश की एक गोली पुलिस अधिकारी की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी, जिससे अधिकारी सुरक्षित बच गए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मसासासोंग आओ को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी जमानत

एजेंसी, नई दिल्ली

मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार नागा विद्रोही मसासासोंग आओ को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने आओ की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया। हालांकि, उनके खिलाफ लंबित अन्य मामले के कारण जमानत मिलने के बावजूद उनकी तत्काल रिहाई नहीं हो सकेगी।

मनी लांड्रिंग का मामला वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई उस प्रकरण के बाद शुरू हुई थी, जिसमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-आइएम (एनएससीएन-आइएम) से जुड़ी एलेमला जमीर को दिल्ली हवाईअड्डे पर पकड़ा गया था। जमीर को 17 दिसंबर 2019 को 72 लाख रुपये की राशि के साथ दीमापुर जाते समय रोका गया था।

मसासासोंग आओ को वर्ष 2022 में मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें फरवरी 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। वह संबंधित मामले में अब भी हिरासत में हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आओ



और विद्रोही संगठन से जुड़े अन्य लोगों ने एलेमला जमीर के माध्यम से जबरन वसूली और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने से जुड़े लेन-देन किए। जमीर पर संगठन की ओर से खुद को कैबिनेट मंत्री बताने का भी आरोप लगाया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आओ को मनी लांड्रिंग मामले में राहत मिली है, लेकिन यूएपीए से जुड़े मामले में हिरासत जारी रहने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। ऐसे में अदालत से जमानत मिलने के बावजूद उनकी रिहाई अन्य लंबित न्यायिक कार्यवाही पर निर्भर करेगी। मामले में जांच एजेंसियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय अभी अदालतों में विचाराधीन है। आओ के खिलाफ मनी लांड्रिंग और यूएपीए से जुड़े मामलों की अलग-अलग कानूनी प्रक्रिया जारी है।

मॉडल टाउन की इमारत में आग, 25 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पाया काबू

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में शुक्रवार को एक इमारत में अचानक आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल की करीब 25 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने विभिन्न दिशाओं से अभियान चलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार आग पर अब नियंत्रण पा लिया गया है। राहत की बात रही कि घटना के समय इमारत के अंदर कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग फैलने की आशंका को देखते हुए आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों को भी एहतियात के तौर पर बाहर कर दिया गया।



दमकल विभाग की टीमों ने आग पर नियंत्रण के बाद भी मौके पर कूलिंग अभियान जारी रखा, ताकि इमारत के किसी हिस्से में बची गर्मी या सुलगती वस्तुओं के कारण दोबारा आग न भड़क सके। घटनास्थल के आसपास लोगों की आवाजाही को भी नियंत्रित किया गया। आग किस वजह से लगी, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें घटना के कारणों की जांच कर रही हैं। साथ ही इमारत के उस हिस्से का भी निरीक्षण किया जा रहा है, जहां से आग शुरू होने की आशंका है।

कारण और नुकसान की जांच जारी

आग किस वजह से लगी, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें घटना के कारणों की जांच कर रही हैं। साथ ही इमारत के उस हिस्से का भी निरीक्षण किया जा रहा है, जहां से आग शुरू होने की आशंका है। आग के कारण इमारत में कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन भी किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार आग पूरी तरह शांत होने के बाद ही नुकसान और घटना के वास्तविक कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। फिलहाल प्राथमिकता इमारत को सुरक्षित करना और किसी तरह की दोबारा दुर्घटना की आशंका को खत्म करना है।

निलंबन उड़ान से पहले जांच में नशे के संकेत, एअर इंडिया ने पायलट किया निलंबित

ज्यूरिख-दिल्ली उड़ान से अल्कोहल टेस्ट में पायलट हुआ फेल

एजेंसी, नई दिल्ली

एअर इंडिया के एक पायलट को ज्यूरिख से दिल्ली आने वाली उड़ान से ठीक पहले अल्कोहल जांच में विफल पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। घटना छह सितंबर 2026 की बताई गई है। संबंधित पायलट ज्यूरिख हवाईअड्डे पर उड़ान भरने से कुछ समय पहले अनिवार्य जांच प्रक्रिया से गुजरा, जिसमें वह निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके बाद उसे विमान का संचालन करने की अनुमति नहीं दी गई और एयरलाइन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की।



यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब विमानन क्षेत्र में उड़ान सुरक्षा और चालक दल के सदस्यों की फिटनेस को लेकर जांच व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विमान उड़ाने से पहले पायलटों और चालक दल की निर्धारित चिकित्सकीय एवं अल्कोहल जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वे ड्यूटी के लिए उपयुक्त स्थिति में हों।

बताया गया कि संबंधित पायलट प्रथम अधिकारी था। अल्कोहल जांच में विफल रहने के बाद उसे ज्यूरिख हवाईअड्डे पर विमान से उतार दिया गया। इसके बाद वह चालक दल के सदस्य के रूप में दिल्ली नहीं आया, बल्कि यात्री के तौर पर भारत वापस भेजा गया। अंतिम चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट और विभागीय जांच पूरी होने तक उसका निलंबन जारी रहेगा।

एअर इंडिया की ओर से सुरक्षा नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है। एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा, नियामकीय आवश्यकताओं या कंपनी के नियमों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है और मामले की प्रकृति के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

पायलटों की जांच को लेकर बढ़ी सख्ती

फुकेट-दिल्ली मामले के बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी भारतीय विमानन कंपनियों के पायलटों के लिए एकमुश्त मनो-सक्रिय पदार्थ जांच का निर्देश दिया है, जिसे जुलाई 2027 तक पूरा किया जाना है। एअर इंडिया समूह ने भी अपने लगभग 5000 पायलटों के लिए इस तरह की जांच शुरू की थी। ज्यूरिख-दिल्ली मामले में अब अंतिम चिकित्सकीय रिपोर्ट और विभागीय जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल एयरलाइन ने पायलट को ड्यूटी से अलग रखते हुए निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद विमानन सुरक्षा व्यवस्था के तहत अनिवार्य जांच और नियमों के पालन पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित हुआ है। मनो-सक्रिय पदार्थ संबंधी जांच का उद्देश्य शरीर में ऐसे पदार्थों या उनके अवशेषों की मौजूदगी का पता लगाना है, जो व्यक्ति की सामान्य कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। मारिजुआना परीक्षण में आमतौर पर भांग या गांजे में पाए जाने वाले टीएचसी जैसे रसायनों या उनके अवशेषों की जांच की जाती है।

न्यूज ब्रीफ

कुशाल भारद्वाज बनें हिमाचल किसान सभा के प्रधान

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल किसान सभा मंडी का 17वां जिला सम्मेलन सौली खड्ड में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन राज्य महासचिव व पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने किया। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार की नीतियों के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भूमि अधिकार, उचित मुआवजा, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग उठाई। जिला प्रधान कुशाल भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर लगाने और बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। साथ ही दूध उत्पादन बढ़ाने और किसानों को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य किया जाएगा। सम्मेलन में 31 सदस्यीय नई जिला कमेटी का गठन किया गया। जोगिंदरनगर के कुशाल भारद्वाज को पुनः जिला प्रधान, धर्मपुर के भूपेंद्र सिंह को सचिव और बल्ह के जोगिंदर वालिया को कोषाध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन में राज्य सम्मेलन के लिए 30 प्रतिनिधियों का भी चयन किया गया।

एनटीपीसी कोलडैम ने लगाया चिकित्सा शिविर

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। एनटीपीसी कोलडैम ने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत ग्राम पंचायत बेरल में निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया। शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। एनटीपीसी कोलडैम की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरजीत कौर के नेतृत्व में धन्वंतरी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ग्रामीणों की जांच की। शिविर में रक्तचाप, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, दांतों सहित सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। जांच के बाद चिकित्सकों ने मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श और व्यक्तिगत सुझाव दिए। जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। शिविर के सफल आयोजन में उप प्रबंधक सीएसआर पूरन सिंह और उनकी टीम का योगदान रहा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बेरल के प्रधान जोगिंदर कुमार और भाजपा मत्स्य पालन प्रकोष्ठ हिमाचल प्रदेश के सह-संयोजक हुक्म चंद भाटिया भी मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एनटीपीसी कोलडैम के प्रयासों की सराहना की और पूरी टीम का आभार जताया।

डीसीएम के खिलाड़ियों ने जूडो व कुराश में जीते पदक



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। जिला स्तरीय जूडो व कुराश प्रतियोगिता में डीसीएम लैंड ऑफ गॉड्स स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक हासिल किए। स्कूल की लड़कियों की जूडो टीम ने ओवरऑल विजेता ट्रॉफी जीती, जबकि लड़कों की टीम ने ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त किया। काव्यांश ने 28 किग्रा भार वर्ग में जूडो और कुराश दोनों में स्वर्ण पदक जीते। मोक्षिता ने 44 किग्रा वर्ग में दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किए। याशिका ने 27 किग्रा वर्ग में जूडो में स्वर्ण पदक जीता लावण्या, अवनी और गुंजन ने क्रमशः 36, 32 और 48 किग्रा वर्ग में जूडो एवं कुराश में रजत पदक हासिल किए। शौर्य ठाकुर ने 40 किग्रा जूडो में रजत पदक जीता। उत्कर्ष और सूर्यांश भार्गव ने क्रमशः 48 और 44 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक हासिल किए। प्रधानाचार्य डॉ. संजय गुप्ता ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और अनुशासन ने विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने विद्यार्थियों को आगे भी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

25 दिन में दीक्षा पोर्टल से 100 कोर्स पूर्ण

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। दीक्षा पोर्टल के कोर्स करने में प्रदेश के शिक्षक रुचि दिखा रहे हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में देश के प्रसिद्ध दीक्षा यानि ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना पोर्टल वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। जिला हमीरपुर के राजकीय उच्च विद्यालय पथल्यार में कार्यरत टीजीटी कला शिक्षक विजय हीर ने दीक्षा पोर्टल से एक हजार से अधिक ऑनलाइन कोर्स पूरा कर सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। वर्ष 2021 में 124 दिन में 900 सर्टिफिकेट हासिल कर उन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। 1 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2026 के मध्य भी हीर ने 100 से अधिक सर्टिफिकेट दीक्षा पोर्टल से सफल कोर्स पूरा करते हुए हासिल किए जिसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ा।। इसमें मणिपुर, गुजरात, लद्दाख, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित अनेकों राज्यों के कोर्स भी उत्तीर्ण किए हैं। इसके अलावा विदेशी विश्वविद्यालयों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी उन्होंने 100 से अधिक कोर्स किए हैं। श्री हीर का नाम देश के श्रेष्ठ 37 शिक्षकों में भी 5 सितम्बर 2026 को दैनिक भास्कर श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान में चुना गया था जो हिमाचल से एकमात्र नाम है। हीर ने कहा कि प्रदेश सरकार को शिक्षकों के अकादमिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए और एनपीएसटी के मानकों को भी अपनाना चाहिए। शिक्षकों को हर साल 50 घंटे के ऑनलाइन कोर्स करना अनिवार्य है और ऐसे में शिक्षकों के लिए मोबाईल भत्ता देने बारे सरकार को विचार करना चाहिए।

पुलिस ने मोगा से दबोचा मुख्य चिट्टा सप्लायर



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के मोगा से मुख्य चिट्टा सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 35 वर्षीय मैनी सिंह निवासी मोगा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के आठ मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक 25 जून को झंडूता थाना क्षेत्र में 101 ग्राम चिट्टे के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ, तकनीकी जांच और बैंक खातों के मनी ट्रेल के आधार पर पुलिस मुख्य सप्लायर तक पहुंची। बिलासपुर पुलिस की टीम ने 23 सितंबर को मोगा में कार्रवाई कर मैनी सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पंजाब में एनडीपीएस के छह, हत्या का एक और गैर-इरादतन हत्या का एक मामला दर्ज है। पुलिस का कहना है कि पिछले तीन महीनों में नशे से जुड़े 94 मामले दर्ज कर 197 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाहरी राज्यों से 23 मुख्य सप्लायर भी दबोचे गए हैं। पुलिस अब पूरे सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है।

डीएवी हमीरपुर में राज्यस्तरीय बॉक्सिंग रेसलिंग व ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। डीएवी संस्थाओं की दो दिवसीय राज्यस्तरीय बॉक्सिंग, रेसलिंग और ताइक्वांडो प्रतियोगिता का डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर में शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के डीएवी संस्थानों के आठ क्लस्टरों से करीब 400 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इनमें विभिन्न भार वर्गों में 300 लड़के और 100 लड़कियां शामिल हैं। कार्यक्रम में एआरओ डीएवी एचपी जोन-सी एवं डीएवी मंडी के प्रधानाचार्य केएस गुलेरिया मुख्य अतिथि रहे। डीएवी बरमाणा की प्रधानाचार्य दीपिका शर्मा, डीएवी बिजड़ी के प्रधानाचार्य एवं वेन्यू इंचार्ज दारा सिंह तथा उपप्रधानाचार्य आशा चौहान भी उपस्थित रहीं। प्रतियोगिता का आयोजन डीएवी हमीरपुर के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। मुख्यातिथि केएस गुलेरिया ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साह और खेल भावना का परिचय दिया।

आईएएस अमित कुमार शर्मा होंगे कुल्लू के नए डीसी, सोनाक्षी सिंह को किन्नौर की जिम्मेदारी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा को कुल्लू का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाक्षी सिंह तोमर को किन्नौर का उपायुक्त बनाया गया है। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार डॉ. अमित कुमार शर्मा (आईएएस, 2016 बैच) वर्तमान में किन्नौर के उपायुक्त के पद पर तैनात हैं। उनका तबादला कुल्लू के उपायुक्त के पद पर किया गया है। उनके कुल्लू का कार्यभार संभालने के बाद अतिरिक्त उपायुक्त (विकास)-सह-परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सुरजीत सिंह इस पद के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे। सोनाक्षी सिंह तोमर (आईएएस, 2016 बैच) वर्तमान में बद्दी, जिला सोलन स्थित बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सरकार ने उनका तबादला कर उन्हें किन्नौर का उपायुक्त नियुक्त किया है।

हिमाचल अपने हकों की लड़ाई में किसी के आगे नहीं झुकेगा : मुख्यमंत्री सुक्खू

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर हाल में हुआ समझौता राज्य सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने हकों और हितों की लड़ाई में किसी के आगे नहीं झुकेगा। सीएम ने शुक्रवार को सिरमौर जिला के सराहां में वामन द्वादशी मेले के समापन समारोह पर जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा।

सीएम ने कहा कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर हाल में हुआ समझौता राज्य सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। कई सालों से इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। पिछली भाजपा सरकार बिजली परियोजना का खर्च वहन करने को तैयार हो गई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने स्पष्ट किया कि पानी की जरूरत वाले राज्य ही इसका खर्च उठाएं। हिमाचल से यह खर्च वसूलना न्यायोचित नहीं था। इस समझौते से प्रदेश के करीब 3000 करोड़ रुपए बचेंगे और परियोजना शुरू होने पर हर साल 1200 से 1500 करोड़ की आय होगी। सीएम ने कहा कि बीबीएमबी के बकाया भुगतान को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में 23 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जीत से 401 करोड़ रुपये राजकोष में आए हैं और होटल से हर महीने करीब 2 करोड़ की आय हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने आरडीजी बंद कर दी है, जिससे प्रदेश को 8000 से 10000 करोड़ का नुकसान हुआ है। फिर भी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन-पेंशन दे रही है और बकाया चुका रही है। क्लास-3 पेंशनरों का पूरा बकाया दिया जा चुका है और महंगाई भत्ते की शेष किस्तें भी समय पर दी जाएंगी। सरकार ने पहली ही कैबिनेट में ओपीएस बहाल की। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण लोगों की मासिक आय 25-30 हजार करना है। उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर बद्दी-बरोटीवाला में 5000 बीघा से ज्यादा जमीन सस्ते दामों पर चहेते उद्योगपतियों को देने का आरोप लगाया। आपदा पर कहा कि सरकार ने पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों की सहायता 1.5 लाख से बढ़ाकर 8.5 लाख की, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ की सहायता अभी तक नहीं मिली है। भ्रष्टाचार पर अंकुश से सरकार ने 3000 करोड़ बचाए हैं, जो अनाथ बच्चों, विधवाओं के कल्याण पर खर्च हो रहे हैं।



◆ कहा- बीबीएमबी बकाया भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट से सकारात्मक फैसले की उम्मीद

◆ आरडीजी बंद होने से हिमाचल को 8 से 10 हजार करोड़ का नुकसान

भारत में संवाद व सहभागी शासन की परंपरा अत्यंत प्राचीन : अनुराग



भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के 5 वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम द्वारा आयोजित अभिव्यक्ति 1.0 एशियन पार्लियामेंट्री डिबेट प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक विमर्श, संवाद और खुली बहस भारत की सभ्यतागत चेतना का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, इन्हें पश्चिम से आयातित अवधारणा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अभिव्यक्ति 1.0 का आयोजन विधि संकाय की साहित्यिक एवं वाद-विवाद सोसाइटी द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य तर्कपूर्ण, सूचनापरक एवं रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करना था।

समकालीन नीति में भारत की सभ्यतागत विरासत की पुनर्प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत में संवाद और सहभागी शासन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। उन्होंने वैदिक सभा और समिति जैसी संस्थाओं तथा चोल काल के उथिरमेरूर अभिलेखों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की शासन परंपरा में विकेंद्रीकरण, सहभागिता और सहमति आधारित निर्णय की अवधारणाएं लंबे समय से विद्यमान रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों और बौद्धिक संस्थानों को केवल यूरोकेंद्रित दृष्टिकोण तक सीमित रहने के बजाय स्व-बोध की भावना के साथ भारत की अपनी ज्ञान परंपराओं को समझना चाहिए। न्याय, तर्क और लोक कल्याण पर आधारित भारतीय चिंतन परंपराओं को आधुनिक सार्वजनिक विमर्श, कानून और नीति निर्माण से जोड़ा जाना आवश्यक है। अनुराग सिंह ठाकुर ने अभिव्यक्ति की शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय धर्मपरंपरा में वाक केवल तर्क प्रस्तुत करने का माध्यम नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की स्थापना का साधन माना गया है।

पीजीडीसीए परीक्षा परिणाम में एमसीएम डीएवी कांगड़ा की छात्राओं का दबदबा







भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा घोषित पीजीडीसीए द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में एमसीएम डीएवी महाविद्यालय कांगड़ा की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है।

कॉलेज की ओर से जारी कॉलेज मेरिट सूची में छात्राओं ने शीर्ष तीनों स्थान हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया मेरिट सूची के अनुसार सुप्रिया ने 89 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। भावना ने 85.33 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरा और तारा ने 85 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। तीनों छात्राओं की इस उपलब्धि से महाविद्यालय परिसर में खुशी का माहौल है। शिक्षकों और सहपाठियों ने छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. बलजीत सिंह पटियाल ने मेधावी छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता छात्राओं की मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ-साथ प्राध्यापकों के मार्गदर्शन तथा अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। साथ ही, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बिलासपुर में 1 अक्तूबर को 14 स्थानों पर चलेगा स्वच्छता एवं नशा विरोधी अभियान

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। 'क्लीन ड्रग-फ्री' अभियान के शुभारंभ को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त रुपिंदर कौर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि अभियान का शुभारंभ 1 अक्तूबर को सुबह 10 बजे होगा। बिलासपुर शहर के नगर परिषद के 11 वार्डों सहित कुल 14 स्थानों पर एक साथ स्वच्छता और नशा विरोधी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी प्रत्येक स्थान पर जिला स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अभियान के तहत स्वच्छता, भांग उन्मूलन और नशे के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। नगर परिषद सफाई कर्मचारियों और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करेगी। अभियान में विद्यार्थियों, एनसीसी, एनएसएस, यूथ रेड क्रॉस, युवा क्लबों, महिला मंडलों और स्वयंसेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नालियों, जल स्रोतों, सड़कों और स्कूलों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। पुलिस के सहयोग से स्वयंसेवकों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और प्राथमिक उपचार की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी।

एनआईटी हमीरपुर में फिजिक्स शिक्षकों की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू

किताबों से आगे सोचें छात्र : पद्मश्री प्रो. एचसी



भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। एनआईटी हमीरपुर के फिजिक्स और फोटोनिक्स साइंस विभाग तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की रीजनल कार्डसिल-23 के नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से चार दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन 24 सितंबर की शाम को मिनी ऑडिटोरियम में हुआ।

उद्घाटन समारोह के मुख्यातिथि एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी रहे, जबकि पद्मश्री पुरस्कार विजेता और 'कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स' के लेखक प्रो. एचसी वर्मा विशिष्टातिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यातिथि प्रो. सूर्यवंशी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रयोगों के माध्यम से भौतिकी सीखने का बेहतरीन मंच हैं। यह शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करती है और छात्रों को किताबों से आगे जाकर बुनियादी ज्ञान देती है।

यह ज्ञान उन्हें स्टार्ट-अप और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। प्रो. एचसी वर्मा ने 3ई यानी नैतिकता, शिक्षा और पर्यावरण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे लक्ष्यों के लिए नैतिकता से समझौता न करें, अच्छी शिक्षा का अर्थ जीवन का आनंद लेना है और प्रकृति के साथ पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। उन्होंने चिंता जताई कि छात्र आज पाठ्यक्रम से आगे नहीं सोच पाते, जिससे उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। एनआईटी की रजिस्ट्रार डॉ. अर्चना संतोष ननोटी ने प्रो. वर्मा के योगदान की सराहना की। कार्यशाला के अकादमिक समन्वयक डॉ. कुलदीप कुमार शर्मा ने बताया कि देशभर से 35 शिक्षक भाग ले रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पिंकू पर तलवार से हमला, आरोपी की गिरफ्तारी को थाने पहुंचे ग्रामीण

इच्छी के ग्रामीणों का कांगड़ा थाने में प्रदर्शन



भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। मटौर-अनसोली सड़क पर इच्छी निवासी 38 वर्षीय पिंकू कुमार पर तलवार से हुए हमले के मामले में शुक्रवार को गांव के दर्जनों ग्रामीण कांगड़ा थाना पहुंचे।

बीडीसी सदस्य हरीश और पंचायत प्रधान इकबाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस के समक्ष रोष जताते हुए कहा कि घटना को दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मामले में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि तलवार से किया गया हमला गंभीर मामला है और इसमें पुलिस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रामीणों ने आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें विरोध-प्रदर्शन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है।

पुलिस के अनुसार मामले की जांच तेजी से की जा रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। बताया जा रहा है कि रविवार देर शाम मटौर-अनसोली सड़क पर कार सवार कुछ लोगों ने पिंकू कुमार पर तलवार से हमला किया था। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका एक हाथ बुरी तरह कट गया था। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पिंकू कुमार इच्छी पंचायत निवासी रमेश चंद के पुत्र हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

लॉरेट इंस्टीट्यूट में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर निकाली जागरूकता रैली



भारतेन्दु संवाददाता, ज्वालामुखी। लॉरेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में विश्व फार्मासिस्ट दिवस एवं राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह-2026 के तहत एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR), दवाओं के सुरक्षित एवं तर्कसंगत उपयोग और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान 400 से अधिक विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली में भाग लिया।

उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा और एसडीएम ज्वालामुखी डॉ. संजीव शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। विद्यार्थियों ने जागरूकता संदेश लिखी तख्तियां लेकर लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक सेवन से बचने और दवाओं के जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक किया। रैली के दौरान एसडीएम कार्यालय मैदान में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर AMR और एंटीबायोटिक के अनुचित इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। कार्यक्रम में पैनल डिस्कशन भी आयोजित किया गया, जिसमें बीएमओ ज्वालामुखी डॉ. पवन कुमार शर्मा ने दवाओं के सुरक्षित उपयोग, स्वास्थ्य सेवाओं और फार्मासिस्ट की भूमिका पर चर्चा की। संस्थान के निदेशक एवं प्राचार्य प्रो. डॉ. एमएस आशावत ने कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AMR के खिलाफ जागरूकता का संदेश समाज तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समन्वय प्रो. डॉ. शिव कुशवाह ने किया।

इंटर कॉलेज क्रिकेट में ढलियारा ने पालमपुर को 68 रन से हराया

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की इंटर कॉलेज क्रिकेट चैंपियनशिप ग्रुप-सी में राजकीय महाविद्यालय ढलियारा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजकीय महाविद्यालय पालमपुर को 68 रन से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। मुकाबला डीएवी महाविद्यालय कांगड़ा के खेल मैदान में खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ढलियारा की टीम 16.2 ओवर में 106 रन पर ऑल आउट हुई। सचिन ने 40, अमन ने 15 और अर्जुन ने 14 रन बनाए। पालमपुर की ओर से कुणाल ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पालमपुर की टीम 10.5 ओवर में 38 रन पर सिमट गई। कुणाल ने 18 और सैम ने 15 रन बनाए। ढलियारा की ओर से सुजल ने पांच, सौरव ने तीन और सचिन ने दो विकेट लिए। नगर परिषद कांगड़ा के पार्षद अशोक शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।

उत्पादन पहली बार तैयार किया एक लाख बीज, जलाशयों व नदियों में डाला जा रहा

हिमाचल की खड्डों से विलुप्ति की कगार पर महाशीर

सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। ये कहना कोई अतिशियोक्ति नहीं होगा कि लोअर हिमाचल की खड्डों से महाशीर मछली का बीज तक विलुप्त होने की कागार पर आ चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि महाशीर की विशेषताओं के चलते खास तौर पर खड्डों के किनारे रहे प्रवासी लोग ही इसका मुख्य कारण बनता जा रहा है। वजह ये है कि प्रवासी लोग लगातार खड्डों से इस मछली को पकड़ते है। यही नहीं गर्मियों में जब इसकी ब्रीडिंग का समय होता है उस समय भी ये लोग चदरों के सहारे छोटी से छोटी मछली तक को पकड़ लेते है। इस कारण इसकी सैल्फ ब्रिडिंग ही खत्म होती जा रही है। इसके अलावा पूरे देश में महाशीर की ब्रिडिंग के लिए केवल दो ही हैचरी स्थित है।



इनमें पूरे देश में सरकारी तौर पर केवल एक हैचरी हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर में स्थित है जबकि दूसरी निजी तौर पर महाराष्ट्र के लोनावाला में है। अलबता हिमाचल में सरकारी तौर पर जोगिंद्र नगर में ही इसका बीज तैयार किया जाता है। वो भी करीब पांच से छ: हजार तक ही बीज तैयार किया जाता है। बतातें चलें कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंची इस मछली का पहली बार वर्ष 2024 में एक लाख से ज्यादा बीज तैयार किया। अब लगातार पिछले तीन वर्षों से इसका बीज तैयार करते आ रहे है, जो केवल हजारों में ही हो पा रहा है। काबिलेगौर है कि महाशीर मछली केवल लोअर हिमाचल की खड्डो व नदियों में ही पाई जाती है। मसलन ये प्रजाति हल्के ठंडे पानी में पाई जाती है। लिहाजा अब इस प्रजाति की मछली को बचाने के लिए संबंधित विभाग ने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए है।

अवैध शिकार और खनन से बढ़ा खतरा

मत्स्य विभाग के अनुसार महाशीर की संख्या कम होने के प्रमुख कारणों में अवैध शिकार और जल स्रोतों में अवैध खनन शामिल हैं। गर्मियों में प्रजनन के समय छोटी मछलियों तक का शिकार होने से इसकी प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वहीं, खड्डों में खनन के कारण इसके प्रजनन स्थल यानी ब्रीडिंग ग्राउंड भी प्रभावित हो रहे हैं। विभाग की ओर से अवैध शिकार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में 27 लोगों को अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए पकड़ा गया और उन पर कुल 13,280 रुपए का जुर्माना लगाया गया। विभाग का कहना है कि महाशीर के अवैध शिकार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

राहुल और मृगल के भी डाले गए बीज

वर्ष 2024 से शुरू की गई इस संरक्षण मुहिम के तहत महाशीर के साथ राहुल और मृगल मछली के करीब दो लाख 40 हजार बीज भी विभिन्न जल स्रोतों में डाले गए हैं। इन्हें ब्यास नदी, मान खड्ड, कुनाह खड्ड, शीर खड्ड और उनकी सहायक खड्डों में छोड़ा गया है। मत्स्य विभाग के अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि महाशीर की विशेषता और घटती संख्या को देखते हुए कृत्रिम बीज तैयार कर विभिन्न नदियों तथा पौंग और कोलडैम जैसे जलाशयों में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाशीर के संरक्षण के लिए अवैध शिकार पर कार्रवाई के साथ-साथ कृत्रिम प्रजनन और बीज संचयन की प्रक्रिया भी लगातार जारी रखी जाएगी।

जलाशयों और नदियों में डाला जा रहा बीज

प्राकृतिक रूप से महाशीर का प्रजनन प्रभावित होने के कारण विभाग अब कृत्रिम रूप से तैयार बीज को विभिन्न जल स्रोतों में छोड़ रहा है। पहली बार करीब 30 हजार महाशीर बीज गोबिंद सागर में डाले गए हैं। इसके अलावा कोलडैम, पंडोह डैम और छोटी नदियों में भी 15 से 20 हजार के करीब बीज डाला जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य महाशीर की संख्या बढ़ाने के साथ उसके प्राकृतिक आवास में इस प्रजाति को फिर से मजबूत करना है।

डीएवी भड़ोली में जुटे 300 खिलाड़ी टेबल टेनिस, शतरंज में दिखाएंगे दमखम



भारतेन्दु संवाददाता, भड़ोली। डीएवी पब्लिक स्कूल भड़ोली में डीएवी स्पोर्ट्स स्टेट लेवल टूर्नामेंट के तहत टेबल टेनिस व शतरंज प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागियों की परेड और विद्यार्थियों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के डीएवी के आठ क्लस्टरों से करीब 300 छात्र-छात्राएं एस्कॉर्ट शिक्षकों के साथ भाग ले रहे हैं। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के बालक एवं बालिकाएं प्रतियोगिताओं में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। क

न्यूज ब्रीफ

अलख दाता मेले की भूपिंदर ने जीती बड़ी माली



भारतेन्दु संवाददाता, बद्दी। नालागढ़ रोड स्थित गंभर पुल में अलख दाता मेले व विशाल दंगल का आयोजन धूमधाम से किया गया। ग्राम पंचायत बनोह-खरड़हट्टी के क्षेत्र में आयोजित मेले में क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दंगल में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे पहलवानों ने शानदार दांव-पेंच दिखाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। दंगल की बड़ी माली में धामी के पहलवान भूपिंदर ने जीत हासिल की, जबकि चीला, बिलासपुर के बलबीर पहलवान उपविजेता रहे। दोनों के बीच हुए रोमांचक मुकाबले का दर्शकों ने तालियों के साथ आनंद लिया। कार्यक्रम में पंचायत प्रधान तृप्ता, उपप्रधान हेमराज पाल और बीडीसी सदस्य निर्मला चंदेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मेला कमेटी के प्रधान जगदीश, उपप्रधान जय पाल, राजिंदर ठाकुर, वीर सिंह और अशोक कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने विजेता पहलवानों को सम्मानित करते हुए आयोजन के लिए कमेटी को बधाई दी।

राम कृष्ण को सैन्य व पूर्व सैनिक लीग ने दी श्रद्धांजलि

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। ग्राम पंचायत बखालग निवासी पूर्व सैनिक राम कृष्ण का 80 वर्ष की आयु में शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। राम कृष्ण वर्ष 1969 में भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में भर्ती हुए थे व 1984 में सेवानिवृत्त हुए। वह अपने पीछे पत्नी और दो पुत्र छोड़ गए हैं। निधन की सूचना मिलते ही सैन्य अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। 14 जीटीसी सुबाथू की ओर से सूबेदार धालेंद्र केसी, नायक विकास पुन और नायक राकेश गुरंग ने पुष्पचक्र अर्पित किया। पूर्व सैनिक लीग अर्की के अध्यक्ष कैप्टन पदम देव ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सैनिकों, ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

सीर उत्सव में 2 और 3 को होंगी खेल प्रतियोगिताएं



भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। उपमंडल घुमारवीं में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक सीर उत्सव-2026 में इस बार खेल गतिविधियों को विशेष स्थान दिया गया है। उत्सव के तहत 2 और 3 अक्तूबर को विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें महिला मंडलों, युवाओं और सरकारी विभागों की टीमें भाग लेंगी। एसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने बताया कि प्रतियोगिताओं का उद्देश्य प्रतिभागियों को प्रतिभा प्रदर्शन के साथ टीम भावना और खेल भावना के लिए प्रोत्साहित करना है। महिला मंडलों के लिए रस्साकशी, बोरा दौड़, तीन टांग दौड़ और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होंगी। रस्साकशी में विभिन्न विभागों की महिला कर्मचारी भी भाग लेंगी। युवाओं के लिए कबड्डी, बास्केटबॉल और हैंडबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। कबड्डी महिला मंडलों और अंडर-19 बालक वर्ग में होगी। बैडमिंटन प्रतियोगिता अंडर-19, ओपन, महिला ओपन और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में करवाई जाएगी। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

बिलासपुर कॉलेज में मनाया एनएसएस स्थापना दिवस

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में एनएसएस इकाई द्वारा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रो. अनुप्रिया ने अतिथियों का स्वागत किया। स्थापना दिवस पर स्वयंसेवियों ने सांस्कृतिक व बौद्धिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मीनाक्षी, आंचल, आशा, तन्वी और अंकिता ने अपने विचार रखे। आदित्य, प्रियंका और तेजस्विनी ने कविता पाठ किया, जबकि अदिक्षा और प्रिया ने संगीत प्रस्तुत किया। मुख्यातिथि डॉ. कटवाल ने स्वयंसेवियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निस्वार्थ समाज सेवा, जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देना एनएसएस स्वयंसेवी की पहचान है। उन्होंने युवाओं से नशा, हिंसा और प्रदूषण जैसी सामाजिक समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

बखालग की छात्राओं ने जीता बास्केटबॉल का खिताब



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बखालग की छात्राओं ने अंडर-14 जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार जिला विजेता का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुनिहार में किया गया। फाइनल मुकाबले में बखालग की टीम ने डीपीएस सोलन को 43-32 के अंतर से हराकर खिताब पर कब्जा किया। रोमांचक मुकाबले में खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, अनुशासन और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बखालग स्कूल की पांच छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य धीरज कुमार ने पीईटी किशोर कुमार और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षक के मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने छात्राओं के उज्ज्वल प्रदर्शन की कामना की।

पीटीए कार्यकारिणी का गठन अब 27 सितंबर को

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में सत्र 2026-27 के लिए अध्यापक-अभिभावक संघ (पीटीए) की नई कार्यकारिणी का गठन अब 27 सितंबर को किया जाएगा। 30 अगस्त को निर्धारित बैठक में आवश्यक कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी थी। प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने बताया कि बैठक की सूचना मीडिया, विद्यार्थियों के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप और कॉलेज की वेबसाइट के माध्यम से दी गई थी, बावजूद इसके बैठक में गिने-चुने अभिभावक ही पहुंचे। उन्होंने कहा कि पीटीए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और महाविद्यालय की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैठक में चुनाव के अलावा विद्यार्थियों से जुड़े शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विषयों पर भी चर्चा होती है। प्राचार्य ने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे 27 सितंबर को सुबह 10 बजे महाविद्यालय परिसर में उपस्थित होकर नई कार्यकारिणी के गठन में भागीदारी सुनिश्चित करें।

अर्की अस्पताल में श्रवण दिव्यांगता को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को किया जागरूक



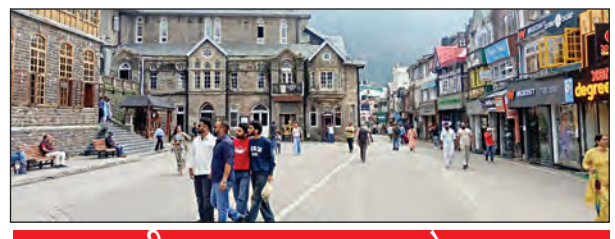
भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अंतरराष्ट्रीय बधिरजन सप्ताह (21 से 27 सितंबर) के तहत सिविल अस्पताल अर्की में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. मुक्ता रस्तोगी के नेतृत्व में हुआ। डॉ. विजय कुमार शांडिल ने स्वास्थ्य कर्मियों को श्रवण दिव्यांगता और बधिरता से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुनने में कमी एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है, जिसका समय पर पता लगाकर उपचार और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कान में संक्रमण, अत्यधिक शोर, चोट, कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव और बढ़ती उम्र सहित कई कारणों से श्रवण क्षमता प्रभावित हो सकती है। कार्यक्रम में समूह चर्चा के दौरान श्रवण दिव्यांगता की पहचान, मरीजों से प्रभावी संवाद और समय पर रेफरल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य कर्मियों ने श्रवण बाधित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की शपथ भी ली। डॉ. शांडिल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने और समावेशी वातावरण तैयार करना है।

हिमाचल में आज से भारी बारिश का अलर्ट

तीन दिन 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने के बाद पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन अब राज्य में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 26 से 28 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और आंधी चलने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने का अलर्ट जारी किया है। तीन दिनों के दौरान भारी बारिश को लेकर भी अलग-अलग स्तर की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 26 सितंबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ बारिश हो सकती है। इस दिन शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 सितंबर को मौसम ज्यादा खराब रहने की आशंका है। इस दिन हमीरपुर, चंबा और लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के अन्य नौ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 सितंबर को भी शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। इन तीनों दिनों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ तूफान चलने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने 26 और 27 सितंबर को राज्य में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। 26 सितंबर को गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। 27 सितंबर को कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दिन लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।



143 घर पूरी तरह ध्वस्त, 3,219 करोड़ का नुकसान

मानसून के दौरान प्रदेश में 143 घर पूरी तरह ध्वस्त हुए हैं। इनमें 43 कच्चे और 100 पक्के घर शामिल हैं। 525 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 18 दुकानें, पांच घराट और 495 पशुशालाएं पूरी तरह ध्वस्त हुई हैं। राज्य में चल और अचल संपत्ति को कुल 3,219 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। इसमें लोक निर्माण विभाग को सड़कों और पुलों के क्षतिग्रस्त होने से 2,744 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

मानसून में बारिश से जुड़े हादसों में 360 लोगों की मौत

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार इस मानसून सीजन में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 360 लोगों की मौत हुई है, जबकि चार लोग लापता हैं और 610 लोग घायल हुए हैं। शिमला में सबसे अधिक 52 मौतें दर्ज की गई हैं। कांगड़ा में 45, चंबा में 44, सिरमौर में 39, मंडी में 36, कुल्लू में 33, लाहौल-स्पीति में 25, सोलन और ऊना में 24-24, किन्नौर में 19, हमीरपुर में 10 और बिलासपुर में नौ लोगों की मौत हुई है। इनमें 214 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है, जबकि 146 लोगों की जान भूस्खलन, अचानक आई बाढ़, डूबने, बहने, फिसलने और बारिश से जुड़े अन्य हादसों में गई है। मानसून के दौरान 579 मवेशियों की भी मौत हुई है।

96,244 कर्मचारियों को ईपीएफओ की बढ़ी वेतन सीमा का मिलेगा लाभ

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेतन सीमा 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी गई है।



नई वेतन सीमा 17 सितंबर 2026 से लागू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 15 हजार रुपए मासिक वेतन पर अंशदान कर रहे 96,244 कर्मचारियों/कामगारों व अंशदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। वेतन सीमा बढ़ने से अधिक पात्र कर्मचारी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में आएंगे और भविष्य निधि, पेंशन तथा बीमा से जुड़े लाभों तक उनकी पहुंच बढ़ेगी। शिमला में शुक्रवार को ईपीएफओ पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश क्षेत्र की प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजीव बिष्ट ने यह जानकारी दी। राजीव बिष्ट ने बताया कि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में 8,664 अंशदायी प्रतिष्ठान ईपीएफओ से जुड़े हैं। इन प्रतिष्ठानों में कुल 3,36,759 अंशदायी सदस्य हैं। इनमें से 96,244 सदस्य वर्तमान में 15 हजार रुपए प्रति माह के वेतन पर अंशदान कर रहे हैं। वेतन सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किए जाने से इन 96,244 अंशदाताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वेतन सीमा बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। ईपीएफओ के तहत भविष्य निधि, पेंशन और बीमा सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होंगे। राजीव बिष्ट ने विश्वास 2026 योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 और एमनेस्टी 2026 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार सृजन और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने से संबंधित है। उन्होंने नियोक्ताओं से पात्र कर्मचारियों का समय पर पंजीकरण और नामांकन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साथ ही कर्मचारियों को उनके अधिकारों और ईपीएफओ से मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी देने को कहा।

गरामोड़ा बैरियर पर 180 पेटियां अवैध शराब बरामद, दो हिरासत में

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने गरामोड़ा बैरियर पर एक वाहन से 180 पेटियां अवैध शराब बरामद की हैं।



उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी हरीश छाहटे ने बताया कि तीन दिनों में यह विभाग की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। उन्होंने बताया कि नाकाबंदी के दौरान वाहन संख्या एचपी-82ए-4645 को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन से चंडीगढ़ में बिक्री के लिए निर्धारित शराब बरामद हुई। इसमें ऐस रम की 139 पेटियां, 999 पावरस्टार फाइन रम की 11 तथा रॉयल स्टैग की 30 पेटियां शामिल हैं। वाहन में सवार दोनों व्यक्ति शराब की खेप से संबंधित वैध परमिट या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों आरोपियों को शराब और वाहन सहित पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस थाना स्वारघाट में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी पंकज राणा की टीम ने की। विभाग ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

बिलासपुर कॉलेज में यूथ रेड क्रॉस यूनिट गठित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में विद्यार्थियों को मानव सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ने के उद्देश्य से यूथ रेड क्रॉस यूनिट का गठन किया गया। यह यूनिट जिला रेड क्रॉस सोसायटी के सहयोग से विभिन्न सामाजिक एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों में कार्य करेगी। कॉलेज प्राचार्य डॉ. कटवाल ने कार्यकारिणी का गठन करते हुए डॉ. जय चंद को समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि यह कार्यकारिणी महाविद्यालय की रेडक्रॉस कमेटी का ही एक रूप है, जो सामाजिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करेगी। समन्वयक डॉ. जय चंद ने बताया कि यूनिट के माध्यम से प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता, रक्तदान तथा आपदा के समय सहायता जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर एनएसएस, एनसीसी तथा रोवर्स एंड रेंजर्स के अधिकारी उपस्थित रहे।

खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता आत्मविश्वास का करते हैं विकास : धर्माणी

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के डडौर के डीएवी पब्लिक स्कूल में राज्य स्तरीय छात्र-छात्राओं की खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर व ग्राम नियोजन, आवास व तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने किया।



उन्होंने ध्वजारोहण व दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 8 क्लस्टर की 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें लगभग साढ़े चार सौ छात्र-छात्राएं शामिल हैं। मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा बच्चों के चहुंमुखी विकास के लिए खेलों के साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियां, एनएसएस, एनसीसी, वाद-विवाद प्रतियोगिता, विज्ञान मेलों आदि का आयोजन विविध स्तर पर किया जाता है। कृषि उपज विपणन समिति के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने विशेषातिथि के रूप में शिरकत की और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। इससे पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रशांत शर्मा ने मुख्यातिथि व अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया तथा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। इस अवसर पर मंत्री की धर्मपत्नी सोनिका धर्माणी, हिमाचल प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी, एलएमसी सदस्य लोकेश कपूर, पीटीए अध्यक्ष विनय धीमान, अभिभावक प्रतिनिधि एवं एलएमसी सदस्य जितेंद्र शर्मा सहित विद्यालय प्रबंधन के सदस्य, अध्यापक, खेल प्रशिक्षक, विद्यार्थी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

तीन दिन से लापता युवक का नहर से शव बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। थाना सुजानपुर के गांव छोटेपुर निवासी 30 वर्षीय पंकज का शव तीन दिन बाद संदिग्ध परिस्थितियों में एयरफोर्स स्टेशन के अंदर नहर से बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के तीन युवकों पर उसे काम के बहाने घर से ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पंकज 22 सितंबर से लापता था। तलाश के दौरान नहर किनारे उसकी चप्पलें और मोबाइल फोन बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने नहर में तलाशी अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव नौशहरा नाले से बरामद किया गया। परिजनों का दावा है कि पंकज के सिर, गर्दन और शरीर पर चोट के निशान हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

गिरिपार में अदरक की फसल पर सड़न रोग का प्रकोप, किसानों की बढ़ी चिंता

भारतेन्दु संवाददाता, पांवटा साहिब। गिरिपार क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल अदरक इस बार सड़न रोग की चपेट में आने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सतौन, कमरऊ सहित आसपास के कई गांवों में अदरक की फसल प्रभावित होने की शिकायतें सामने आई हैं। किसानों के अनुसार खेतों में खड़े पौधे पहले पीले पड़ रहे हैं और बाद में सूखने लगते हैं। वहीं, जमीन के भीतर अदरक की गांठों में भी सड़न दिखाई दे रही है।



किसानों राजेंद्र सिंह, बीजा राम, प्रवेश राणा, खतरी राम और लीला देवी ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष अच्छी पैदावार और बेहतर आमदनी की उम्मीद में फसल पर काफी मेहनत और खर्च किया था। फसल तैयार होने के समय रोग फैलने से उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। कई खेतों में रोग का असर अधिक होने के कारण उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। किसानों का कहना है कि अदरक गिरिपार क्षेत्र की महत्वपूर्ण नकदी फसल है और इससे होने वाली आय पर कई परिवारों की आजीविका निर्भर है। ऐसे में फसल में रोग फैलने से किसानों के सामने आर्थिक नुकसान का संकट खड़ा हो गया है।

किसानों ने कृषि विभाग से प्रभावित क्षेत्रों में विशेषज्ञों की टीम भेजकर खेतों का निरीक्षण करवाने, रोग के कारणों की पहचान करने तथा नियंत्रण के लिए आवश्यक दवाइयां और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने की मांग की है। इसके अलावा किसानों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से प्रभावित फसल का सर्वे करवाकर नियमानुसार राहत प्रदान करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि समय रहते प्रभावी कदम उठाए गए तो शेष फसल को बचाया जा सकता है और किसानों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

बारबेक्यू-नेशन में 1600 पदों के लिए साक्षात्कार 29 सितंबर से

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग के माध्यम से बारबेक्यू-नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड में सर्विस स्टीवर्ड और किचन हेल्पर के करीब 1600 पदों पर भर्ती की जा रही है। पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या अधिक निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को 11,000 से 14,000 रुपए मासिक वेतन के साथ पीएफ, ईएसआईसी, भोजन और आवास की सुविधा मिलेगी। साक्षात्कार 29 सितंबर को सरकाघाट, 30 सितंबर को जोगिंदरनगर, 1 अक्तूबर को सुंदरनगर और 3 अक्तूबर को करसोग के उप रोजगार कार्यालयों में होंगे। सभी स्थानों पर समय सुबह 10:30 बजे रहेगा। चयनित अभ्यर्थियों को दिल्ली में सात दिन का निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बोनाफाइड, फोटो और रोजगार पंजीकरण कार्ड साथ लाने होंगे। यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर राज्यपाल ने एनएच-205 फोरलेन कार्य का किया निरीक्षण



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एम्स बिलासपुर के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने एनएच-205 पर कलर बाला गांव से नौणी चौक तक चल रहे फोरलेन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान एनएचएआई अधिकारियों ने राज्यपाल को परियोजना की प्रगति और निर्माण कार्यों की जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि कलर बाला गांव से नौणी चौक तक 17.450 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन में उन्नत किया जा रहा है। परियोजना के तहत पूर्ण हो चुके कार्यों, वर्तमान निर्माण गतिविधियों तथा प्रस्तावित समय-सीमा से राज्यपाल को अवगत करवाया गया। परियोजना को सितंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान एम्स बिलासपुर के आसपास यातायात और कनेक्टिविटी व्यवस्था को लेकर की जा रही तैयारियों की भी जानकारी दी।

राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को एम्स के आसपास आवागमन और कनेक्टिविटी से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने दौरे के दौरान सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने को कहा, ताकि आम लोगों को असुविधा न हो। उन्होंने सभी विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा विकास कार्यों में जनसुविधा और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

आयोजन **जिला प्रशासन और सेना ने किए हैं पुख्ता प्रबंध, आज से 6 अक्तूबर तक चलेगी भर्ती रैली**

थल सेना भर्ती के लिए अणु का मैदान तैयार, एडीसी ने की प्रबंधों की समीक्षा

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। थल सेना में अग्निवीर भर्ती के तहत विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास करने वाले युवाओं के ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए अणु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड एवं डिग्री कॉलेज परिसर में 26 सितंबर से 6 अक्तूबर तक आयोजित की जा रही भर्ती रैली के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।



एडीसी अभिषेक गर्ग ने शुक्रवार सुबह एसडीएम संजीत सिंह, पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ रैली स्थल का जायजा लिया तथा थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन व सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सभी आवश्यक प्रबंधों की समीक्षा की। एडीसी ने बताया कि इस बार भर्ती रैली में जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के अभ्यर्थियों के अलावा क्लर्क श्रेणी की भर्ती के लिए प्रदेश के अन्य जिलों के युवाओं की भर्ती प्रक्रिया भी यहीं पर पूर्ण की जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 4571 होगी। यानि प्रत्येक दिन लगभग 550 युवाओं का ग्राउंड टेस्ट होगा। यह प्रक्रिया 4 अक्तूबर को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मौसम खराब रहने की स्थिति के लिए 5 और 6 अक्तूबर को रिजर्व दिन रखे गए हैं। एडीसी ने बताया कि रैली स्थल पर बिजली, पानी, अग्निशमन, शौचालय व सफाई, मेडिकल, इंटरनेट, कंप्यूटर्स-प्रिंटर्स और अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया गया है तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शिक्षा विभाग, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, आईटीआई और अन्य शिक्षण संस्थानों से भी अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए गए हैं। पात्र उम्मीदवारों की मैदान में एंट्री तड़के से ही शुरू हो जाएगी। इस दौरान बस सेवा की व्यवस्था भी की जाएगी। एडीसी ने बताया कि रैली स्थल के आस-पास सेना व पुलिस द्वारा कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। उम्मीदवारों और डयूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा मैदान में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शारीरिक क्षमता एवं प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयों के प्रयोग की आशंका को देखते हुए केमिस्ट की दुकानों के संचालकों को भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए बाहर से आए सेना के लगभग 200 अधिकारियों एवं सैनिकों के रहने की व्यवस्था भी की गई है।

सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं अभ्यर्थी : कर्नल

थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने एडमिट कार्ड का अच्छी क्वालिटी का रंगीन प्रिंट साथ लेकर आएं, ताकि भर्ती रैली में बार कोड स्कैनिंग के माध्यम से एंट्री में कोई दिक्कत न आए। अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां और दो-दो सेल्फ अटैस्टड प्रतियां साथ लाएं। इन दस्तावेजों में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की तीन-तीन प्रतियां, अगर ओपन स्कूल से मैट्रिक की है, तो अंतिम स्कूल के छोड़ने का प्रमाण पत्र जोकि सक्षम अधिकारी द्वारा काउंटर साइन किया हो, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, डोगरा क्लास या जाति प्रमाण पत्र, धर्म का प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सेवारत सैनिक या भूतपूर्व सैनिक के पुत्र का प्रमाण पत्र, अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, अधिसूचना में दिए गए फॉरमेट पर ऐफिडेविट, क्लर्क या एसकेटी के लिए ओ-लेवल सर्टिफिकेट, एनसीसी और खेल गतिविधियों के प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पैन कार्ड, अन्य दस्तावेज और 20 पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।

घुमारवीं में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। उपमंड

हाइडी के आगे मॉडल्स भी फेल

जर्मनी। हाइडी क्लम जर्मनी की प्रसिद्ध एथलीट , अभिनेत्री और टेलीविजन हस्ती हैं। उन्होंने खेल जगत में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है। वह कई लोकप्रिय कार्यक्रमों से जुड़ी रही हैं और अपनी रचनात्मकता व व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं।



स्पोर्ट्स विंडो

एशियाई खेल: टेबल टेनिस मिश्रित युगल में भारत का पदक पक्का

एजेंसी, नागोया। भारत के मानुष शाह और दीया चितले ने एशियाई खेल 2026 में इतिहास रचते हुए शुक्रवार को टेबल टेनिस मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने कम से कम कांस्य पदक भी पक्का कर लिया है। विश्व नंबर आठ मानुष और दीया ने क्वार्टर फाइनल में हांगकांग, चीन की विश्व नंबर चार जोड़ी डू होई केम और वोंग चुन टिंग को 3-1 से हराया। भारतीय जोड़ी ने मुकाबला 11-6, 13-15, 11-9, 11-5 से अपने नाम किया। मानुष और दीया एशियाई खेलों में टेबल टेनिस मिश्रित युगल में पदक पक्का करने वाली भारत की दूसरी जोड़ी बन गई है। इससे पहले 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में शरत कमल और मनिका बत्रा ने मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीता था। एशियाई खेलों में भारत ने टेबल टेनिस में अब तक पुरुष टीम (2018), मिश्रित युगल (2018) और महिला युगल (2023) में कांस्य पदक जीते हैं। अब सेमीफाइनल में मानुष और दीया का सामना चीन की विश्व नंबर दो जोड़ी वांग चुकिन और सुन यिंगशा से होगा। चीनी जोड़ी इस स्पर्धा की दो बार की मौजूदा चैंपियन है।

चेस ओलिंपियाड में भारतीय टीम ने टॉप पर पहुंचने का अवसर गंवाया

एजेंसी, समरकंद। समरकंद में चल रहे 46वें फीडे चेस ओलिंपियाड के 8वें राउंड में डिफेंडिंग चैंपियन भारत की मेंस और विमेंस टीम को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। मेंस कैटेगरी में भारत को अजरबैजान ने 2-2 से रोका। विमेंस कैटेगरी में भी कजाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। भारत की मेंस टीम के पास टॉप पर पहुंचने का मौका था, लेकिन ड्रॉ के कारण यह मौका छूट गया। वहीं, विमेंस में कजाकिस्तान के खिलाफ ड्रॉ के बाद भारतीय टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है, जबकि चीन की टीम टॉप पर पहुंच गई है। अजरबैजान के खिलाफ भारत के आर. प्रज्ञानानंद, अर्जुन एरिगैसी, डी. गुकेश और विदित गुजराती चारों अपनी बाजियां ड्रॉ खेले। गुकेश ने तीसरे बोर्ड पर सफेद मोहरों से मरदली महम्मद के खिलाफ अच्छी स्थिति बनाई थी। हालांकि, अजरबैजान के खिलाड़ी ने सटीक बचाव किया और 56 चाल के बाद बाजी ड्रॉ रही। आर. प्रज्ञानानंद को अनुभवी शाखरियार मामेद्यारोव ने ड्रॉ पर रोका। अर्जुन एरिगैसी और आयदिन सुलेमानली के बीच भी बाजी बराबर रही। विदित गुजराती ने रऊफ मामेदोव के खिलाफ ड्रॉ खेला।

विजय दहिया बने दिल्ली सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच

एजेंसी, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज विजय दहिया को 2026-27 घरेलू सत्र के लिए दिल्ली सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच फिर नियुक्त किया गया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने शुक्रवार को पुरुष और महिला टीमों के कोच तथा चयन समितियों की घोषणा की। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बचपन के कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता राजकुमार शर्मा को पुरुष टीम का स्टेट मेंटर बनाया गया है। महिला टीमों के लिए सुनीता शर्मा को स्टेट मेंटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीडीसीए के अनुसार पुरुष और महिला टीमों की चयन समितियों तथा कोचों के चयन का फैसला क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) की सिफारिशों के बाद किया गया। विजय दहिया इससे पहले आईपीएल-2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस के सहायक कोच रह चुके हैं।



एशियन गेम्स: भारत की पुरुष और महिला टीम कबड्डी के फाइनल में

मेंस टीम ने थाईलैंड को 66-28 से और वुमेंस टीम ने नेपाल को 48-24 से हराया

एजेंसी, नागोया





गत चैंपियन भारत ने शुक्रवार को एशियाई खेल 2026 की पुरुष और महिला कबड्डी स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली। आठ बार की चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में थाईलैंड को 66-28 से हराकर एशियाई खेल 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय टीम अब अपने खिताब का बचाव करने से एक जीत दूर है। भारत ने पुरुष कबड्डी स्पर्धा के अपने नौवें फाइनल में जगह बनाई है। टीम ने पूरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों हाफ में थाईलैंड पर दबदबा बनाए रखा। भारत ने पहले हाफ में 37 अंक हासिल किए, जबकि थाईलैंड 18 अंक ही जुटा सका। दूसरे हाफ में भी भारत ने 29 अंक जोड़े और थाईलैंड को केवल 10 अंक मिले। भारतीय पुरुष टीम प्रतियोगिता में अब तक अजेय है। उसने ग्रुप ए में अपने चारों मुकाबले जीतने के बाद सेमीफाइनल में भी शानदार जीत दर्ज की। फाइनल में भारत का सामना ईरान या चीनी ताइपे से होगा। दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने 22 आउट अंक और तीन बोनस अंक हासिल किए तथा दो और ऑलआउट लगाए। थाईलैंड को इस दौरान सात आउट अंक, दो बोनस अंक और एक तकनीकी अंक मिला। भारत ने लगातार आक्रामक रेडिंग और मजबूत डिफेंस के दम पर मुकाबला एकतरफा कर दिया। थाईलैंड के खिलाड़ी थकान से जूझते दिखे, जिसका भारत ने पूरा फायदा उठाया। देवांक ने शानदार रेड करते हुए लगातार अंक जुटाए, जबकि अयान, अर्जुन देशवाल और असलम इनामदार ने भी टीम की बढ़त बढ़ाने में योगदान दिया।

वहीं, महिला टीम ने नेपाल को 48-24 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय टीम ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और अब स्वर्ण पदक के लिए खेलेगी। भारत ने मुकाबले की तेज शुरुआत की और शुरुआती पांच मिनट के बाद 9-5 की बढ़त बना ली। भारतीय रेडरों ने लगातार अंक जुटाए, जबकि नेपाल ने भारतीय डिफेंस पर दबाव बनाने की कोशिश की। नेपाल ने वापसी का प्रयास करते हुए सोनाली को सुपर टैकल से रोककर अहम अंक हासिल किया। इसके बावजूद भारत ने 15-10 की बढ़त बनाए रखी। इसके बाद नेपाल की गंगा घिमिरे ने शानदार रेड करते हुए चार अंक हासिल किए। एंकल होल्ड के बावजूद उन्होंने लाइन को छू लिया और लंबी जांच के बाद उनकी रेड को चार अंकों के रूप में मान्यता दी गई। इससे भारत की बढ़त 21-15 रह गई।

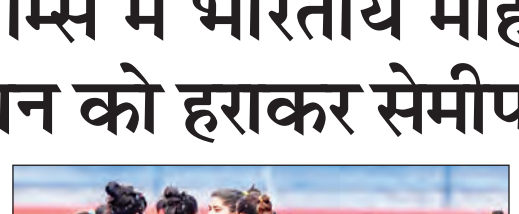
बैडमिंटन में सात्विक-चिराग की जोड़ी पहले ही दौर में हारी



एजेंसी, नागोया। एशियन गेम्स में शुक्रवार को बैडमिंटन से भारत के गोल्ड मेडल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। गत चैंपियन भारतीय जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को एशियाई खेल-2026 में पुरुष युगल स्पर्धा के पहले ही दौर में बड़ा उलटफेर झेलना पड़ा। थाईलैंड के सुकफुन और पकापोन तीरारत्साकुल ने शुक्रवार को राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में चौथी वरीय भारतीय जोड़ी को 12-21, 21-19, 21-14 से हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में 11-5 की बढ़त बनाई और लगातार दबाव बनाए रखते हुए 20 मिनट में गेम 21-12 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में थाई जोड़ी ने वापसी की। सुकफुन और पकापोन ने 8-7 की बढ़त बनाई, लेकिन भारतीय जोड़ी ने स्कोर 8-8 और फिर 11-11 कर दिया। इसके बाद थाई खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल जारी रखा और 17-14 की बढ़त हासिल कर ली। उन्होंने अंततः दूसरा गेम 21-19 से जीतकर मुकाबला निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। तीसरे गेम में सात्विक और चिराग अपनी शुरुआती लय हासिल नहीं कर सके। थाई जोड़ी ने लगातार आक्रामक रैलियों के जरिए 18-14 की बढ़त बनाई और निर्णायक गेम 21-14 से जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया। इस हार के साथ सात्विक-चिराग का पुरुष युगल अभियान पहले ही दौर में समाप्त हो गया।

एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम जापान को हराकर सेमीफाइनल में

एजेंसी, नागोया



भारतीय विमेंस हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में जापान को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। नागोया के गिफू प्रिफेक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में खेले गए पूल-बी के मुकाबले में भारत ने लगातार चौथी जीत दर्ज की। टीम 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। लालरेमसियामी ह्याजोंटे, इशिका चौधरी और नवनीत कौर ने भारत के लिए गोल किए, जबकि जापान की ओर से शिहो कोबायाकावा ने एक गोल किया।

पहले क्वार्टर में नवनीत कौर ने गोल की कोशिश की, लेकिन जापानी गोलकीपर यू कुडो ने उनके शॉट को रोक दिया। गोलकीपर के रोकने के बाद गेंद वापस मैदान में आई। इसी गेंद पर लालरेमसियामी ने सबसे पहले पहुंचकर उसे गोलपोस्ट में डाल दिया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। जापान ने पहले क्वार्टर में बराबरी की कोशिश की। उसे पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन भारतीय कप्तान और गोलकीपर सविता पुनिया ने माहो उएनो के प्रयास को रोक दिया। अंतिम क्वार्टर की शुरुआत में जापान ने एक गोल कर अंतर कम किया। शिहो कोबायाकावा ने जोरदार तोमाहॉक शॉट पर गोल कर स्कोर 3-1 कर दिया।

इसके बाद जापान ने लगातार हमले किए और पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया, लेकिन सविता पुनिया की अगुआई में भारतीय डिफेंस ने दबाव को अच्छी तरह संभाला और जापान को दूसरा गोल नहीं करने दिया। (अनंत ज्ञान)

लालरेमसियामी ने दिलाई बढ़त

भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। पहले क्वार्टर में नवनीत कौर ने गोल की कोशिश की, लेकिन जापानी गोलकीपर यू कुडो ने उनके शॉट को रोक दिया। गोलकीपर के रोकने के बाद गेंद वापस मैदान में आई। इसी गेंद पर लालरेमसियामी ने सबसे पहले पहुंचकर उसे गोलपोस्ट में डाल दिया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। जापान ने पहले क्वार्टर में बराबरी की कोशिश की। उसे पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन भारतीय कप्तान और गोलकीपर सविता पुनिया ने माहो उएनो के प्रयास को रोक दिया। इशिका के गोल से भारत 2-0 आगे, नवनीत ने बढ़त 3-0 की कर दी।

इंडिया-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए को हराया

कुशाग्र ने दोनों पारियों में बनाए 159 रन, शम्स ने 7 विकेट लिए

एजेंसी, नई दिल्ली



इंडिया-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए को पहले अनऑफिशियल टेस्ट में 162 रन से हरा दिया। पुडुचेरी में खेले गए मुकाबले में 363 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया-ए की टीम 200 रन पर ऑलआउट हो गई। इस जीत के साथ भारत ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहली पारी में 334 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया-ए 171 रन पर सिमट गई। इससे इंडिया-ए को पहली पारी में 163 रन की बढ़त मिली। दूसरी पारी में भारत ने 199 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया-ए के सामने 363 रन का टारगेट रखा। भारत के लिए कुमार कुशाग्र ने पहली पारी में 113 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 46 रन पर नाबाद रहे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शम्स मुलानी ने दोनों पारियों में कुल 7 विकेट लिए। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया-ए ने 55/2 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। टीम ने 31.5 ओवर में 100 रन पूरे किए। इसके बाद भारत-ए ने लगातार विकेट लेकर दबाव बनाया। 36 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया-ए का स्कोर 4 विकेट पर 114 रन था। 8वें विकेट के लिए फर्गस ओनील और टॉड मर्फी ने 59 गेंदों पर 50 रन जोड़े। लंच तक ऑस्ट्रेलिया-ए ने 7 विकेट पर 185 रन बनाए। इसके बाद टीम 54.5 ओवर में 200 रन पर ऑलआउट हो गई।

ऑस्ट्रेलिया-ए की दूसरी पारी में कोई फिफ्टी नहीं

ऑस्ट्रेलिया-ए के लिए दूसरी पारी में फर्गस ओनील ने 52 गेंदों पर 47 और नाथन मैकस्वीनी ने 75 गेंदों पर 35 रन बनाए। जेसन सांघा ने 23 गेंदों पर 26 रन की तेज पारी खेली, जबकि टॉड मर्फी ने 17 रन बनाए। भारत-ए की ओर से तुषार देशपांडे और शम्स मुलानी ने 3-3 विकेट लिए। अंशुल कंबोज और तनुश कोटियन को 2-2 विकेट मिले।

मेक इन इंडिया के 12 साल पूरे

एजेंसी, नई दिल्ली। देश में बड़े स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल ने शुक्रवार को 12 वर्ष पूरे कर लिए। केंद्र सरकार ने 25 सितंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। योजना के तहत देश में निवेश को प्रोत्साहित करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयास किए गए। सरकार ने इस पहल के माध्यम से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दवा, दूरसंचार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए नीतिगत कदम उठाए गए। सरकार के अनुसार, इस पहल ने देश में विनिर्माण और निवेश के माहौल को मजबूत करने में भूमिका निभाई है।

... एनसीएलटी ने अदाणी पावर की विलय योजना मंजूर की

अदाणी पावर में 10 कंपनियां होंगी शामिल

एजेंसी, नई दिल्ली



नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के फैसले के बाद अदाणी पावर लिमिटेड की विलय योजना को सभी आवश्यक मंजूरियां मिल गई हैं। 24 सितंबर 2026 को जारी आदेश में एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (वीआईपीएल) के अदाणी पावर में विलय को मंजूरी दे दी। कंपनी के लिए यह फैसला उसके कॉरपोरेट ढांचे को सरल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद समूह की ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के संचालन और प्रबंधन को एकीकृत करने में मदद मिल सकती है।

यह फैसला एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ के 4 अगस्त 2026 के आदेश के बाद आया है। अहमदाबाद पीठ ने अदाणी पावर की नौ अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के विलय को मंजूरी दी थी। इस तरह विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड समेत कुल 10 कंपनियां अदाणी पावर के साथ विलय योजना का हिस्सा हैं। इन कंपनियों के विलय से समूह के ऊर्जा कारोबार से जुड़ी अलग-अलग कॉरपोरेट संस्थाओं को एक ढांचे में लाने का रास्ता साफ हुआ है।

नौ कंपनियां होंगी एक

विलय होने वाली नौ कंपनियों में अदाणी पावर दहेज लिमिटेड, कच्छ पावर जनरेशन लिमिटेड, रिसर्जेंट फ्यूल मैनेजमेंट लिमिटेड, महान फ्यूल मैनेजमेंट लिमिटेड, ओडिशा थर्मल एनर्जी लिमिटेड, कोरबा पावर लिमिटेड, अनूपपुर थर्मल एनर्जी (एमपी) प्राइवेट लिमिटेड, मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड और एम्बरिजा इंफ्रा पार्क लिमिटेड शामिल हैं। इनके अलावा विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का भी अदाणी पावर में विलय किया जा रहा है।

विलय से बढ़ेगा एकीकरण

विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड महाराष्ट्र में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है। इसका अदाणी पावर में विलय समूह की बिजली उत्पादन गतिविधियों को एकीकृत करने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। एनसीएलटी की मंजूरी के बाद विलय योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा। अदाणी पावर देश के प्रमुख निजी बिजली उत्पादकों में शामिल है और विभिन्न राज्यों में बिजली उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं का संचालन करता है। कंपनी की ओर से अलग-अलग सहायक कंपनियों के विलय की प्रक्रिया को कारोबार के संगठनात्मक ढांचे को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। एनसीएलटी की दोनों पीठों से मंजूरी मिलने के बाद अब विलय योजना के लिए आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। कुल 10 कंपनियों के एकीकरण से अदाणी पावर के कॉरपोरेट ढांचे में बदलाव आएगा और ऊर्जा कारोबार से जुड़ी गतिविधियों को एक ही संस्था के तहत व्यवस्थित करने में सुविधा होगी।

सेबी के नए नियमों से पीएमएस में निवेश का दायरा बढ़ा

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) के लिए नई नियामकीय व्यवस्था को मंजूरी दी है। 'सेबी (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) विनियम, 2026' के तहत वर्ष 2020 के मौजूदा नियमों को बदला जाएगा। नए नियमों का उद्देश्य पीएमएस क्षेत्र में कारोबार को बढ़ावा देने के साथ अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना और अनावश्यक नियामकीय प्रावधानों को हटाना है। इसके तहत पोर्टफोलियो प्रबंधकों को ग्राहकों की राशि को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम और प्राथमिक ऋण निर्गम जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा। विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं में ग्राहक की स्पष्ट सहमति से प्रबंधनाधीन कुल संपत्ति का 10 प्रतिशत तक हिस्सा गैर-परिवर्तनीय और गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में लगाया जा सकेगा। वहीं, शेयर बाजार में कारोबार किए जाने वाले डेरिवेटिव्स के उपयोग की सीमा कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति के 1.25 गुना तक तय की गई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए गैर-कृषि सूचकांक आधारित कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भागीदारी का दायरा भी बढ़ाया गया है। हालांकि, सट्टेबाजी पर रोक के लिए कुछ सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे। सेबी के अनुसार, इन बदलावों से बाजार में तरलता और गहराई बढ़ने के साथ निवेशकों को पोर्टफोलियो में विविधता लाने के अधिक अवसर मिल सकते हैं।

मारुति सुजुकी ने मानेसर में शुरू किया 300 किलोवाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र

एजेंसी, मुंबई

◆2030-31 तक कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में मारुति का बड़ा कदम



मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर स्थित अपने विनिर्माण संयंत्र में 300 किलोवाट क्षमता का हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। यह कंपनी का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। इसका उद्देश्य वाहनों के निर्माण में पेट्रोल, डीजल और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना है। संयंत्र में हाइड्रोजन बनाने के लिए कारखाने में उपलब्ध अतिरिक्त सौर बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। छुट्टी या कम उत्पादन के दौरान जब सौर बिजली की खपत कम होगी, तब बची हुई बिजली को हाइड्रोजन उत्पादन में लगाया जाएगा। इसके लिए 300 किलोवाट क्षमता का विद्युत अपघटक लगाया गया है, जो बिजली की सहायता से पानी से हाइड्रोजन अलग करता है। तैयार हाइड्रोजन को संग्रहित किया जाएगा और बाद में प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर कारखाने में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

इससे वाहनों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा में हरित हाइड्रोजन की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। कंपनी मानेसर परियोजना से मिले अनुभव के आधार पर हरियाणा और गुजरात स्थित अपने अन्य विनिर्माण संयंत्रों में भी हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना बना रही है। मारुति सुजुकी सौर ऊर्जा, हरित बिजली, जैवगैस और बैटरी भंडारण जैसे विकल्पों पर भी काम कर रही है। खोरखौदा संयंत्र में प्रतिदिन 10 टन जैवगैस उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र लगाया जा रहा है। वहां एक मेगावाट घंटा क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी शुरू हो चुकी है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 561 करोड़ रुपये की लागत से चार संपीड़ित जैवगैस परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कंपनी वित्त वर्ष 2030-31 तक हरित ऊर्जा से जुड़े कार्यों पर करीब 925 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। कंपनी के विनिर्माण कार्यों से वर्तमान में करीब 6.15 लाख टन कार्बन उत्सर्जन होता है, जिसे 2030-31 तक घटाकर 2.66 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्पाइसजेट विस्तार त्योहारों में हवाई यात्रियों को राहत, स्पाइसजेट ने शुरू की 22 विशेष उड़ानें

10 अक्टूबर से स्पाइसजेट शुरू करेगी विशेष उड़ानें

एजेंसी, नई दिल्ली



त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट ने 10 अक्टूबर से 22 विशेष उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार, ये सभी विशेष उड़ानें कोलकाता के लिए या कोलकाता से संचालित होंगी। इन उड़ानों के जरिए पश्चिम बंगाल की राजधानी को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, बागडोगरा और पोर्ट ब्लेयर से जोड़ा जाएगा। इससे दुर्गा पूजा के दौरान यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिल सकेंगे।

स्पाइसजेट के अनुसार, बागडोगरा से दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए भी विशेष उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इससे उत्तर बंगाल के यात्रियों को त्योहारों के दौरान यात्रा करने में सुविधा होगी। दुर्गा पूजा के समय बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के पास जाते हैं, जिसके कारण हवाई यात्राओं की मांग में वृद्धि होती है। कंपनी ने इसी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की है।

स्पाइसजेट ने कोलकाता के रास्ते मुंबई और पोर्ट ब्लेयर के बीच भी हवाई संपर्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक, इस सुविधा के तहत यात्रियों को कोलकाता में विमान बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे मुंबई और पोर्ट ब्लेयर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी और यात्रा का समय तथा प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो सकेगी।

स्पाइसजेट के मुख्य कारोबारी अधिकारी देबोजो महर्षि ने कहा कि दुर्गा पूजा कोलकाता के लिए वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने और त्योहारों के दौरान कोलकाता तथा बागडोगरा की यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से 22 विशेष उड़ानें जोड़ी जा रही हैं।

कंपनी की ओर से विशेष उड़ानों की घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब स्पाइसजेट अपने बेड़े और उड़ानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी ने इसी महीने की शुरुआत में आगामी शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम के दौरान विमानों की संख्या बढ़ाने के लिए पट्टे पर 20 विमान लेने की घोषणा की थी।

सर्दियों में बढ़ेंगी उड़ानें

स्पाइसजेट के अनुसार, इन विमानों को अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य तक चरणबद्ध तरीके से बेड़े में शामिल किया जाएगा। विमानों की संख्या बढ़ने के बाद कंपनी को शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम के दौरान अपनी दैनिक उड़ानों की संख्या बढ़ाकर करीब 200 करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे विभिन्न शहरों के बीच हवाई संपर्क मजबूत करने में सहायता मिल सकती है। त्योहारों के दौरान हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण विमानन कंपनियां आमतौर पर प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था करती हैं। विशेष रूप से दुर्गा पूजा के समय कोलकाता और पश्चिम बंगाल से जुड़े मार्गों पर यात्रियों की मांग बढ़ जाती है।